चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 23 मई-29 मई 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

संवेदनशील सूचनाएं नहीं मिलने के कारण भारत की किरकिरी

फोटो-प्रभात पाण्डेय

Research and Analysis Wing
अनुसंधान और विश्लेषण विंग
India भारत

रॉ फेल

कुलभूषण जाधव, डॉल्कन ईसा वीज़ा प्रकरण, चीनी वीटो, नेपाल, पठानकोट किसी में भी सटीक सूचना नहीं दे पाई प्राइम खुफिया एजेंसी

घनघोर अराजकता में फंसे रिसर्च एंड अनासिलिस विंग (रॉ) को धो डालने पर आमादा पीएम मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल

प्रभात रंजन दीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (रॉ) में कई ढांचागत फेरबदल कर रहे हैं. रॉ के ठहरे हुए पानी को हिलाना मोदी के लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि विदेश की धरती पर अभिसूचनाएं हासिल करने वाली भारत की इस प्राइम खुफिया एजेंसी की नाकामियां देश पर भारी पड़ रही हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को लगातार परेशानियों में डाल रही हैं. रॉ के कई महत्वपूर्ण फेल्योर से भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय फोरम पर झेंप का सामना करना पड़ा है और अटपटी सफाई पेश करने पर विवश होना पड़ा है. पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रॉ के कथित एजेंट कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने का मसला हो या चीन के उइगुर प्रांत के विवादास्पद निर्वासित नेता डॉल्कन ईसा को भारतीय वीज़ा दिए जाने का मसला हो, ऐसे कई मामलों में सटीक अभिसूचना मुहैया कराने में रॉ नाकाम रहा, जिससे भारत सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा. कुलभूषण जाधव मामले में केंद्र को रक्षात्मक-तर्क का सहारा लेना पड़ा और चीन के विरोध के बाद डॉल्कन ईसा का वीज़ा रद्द करने का अपमानजनक फैसला लेना पड़ा. विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का तो यह भी कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रस्ताव के बारे में चीन को पहले ही जानकारी मिल गई, लेकिन चीन के वीटो की तैयारियों के बारे में रॉ को कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे भारतीय रणनीति को संयुक्त राष्ट्र में करारा झटका लगा. चीन से इसका कूटनीतिक बदला लेने के इरादे से डॉल्कन ईसा को भारत का वीज़ा देने का बचकाना फैसला हुआ, लेकिन उसे भी वापस ले लेना पड़ा. इससे भारत सरकार की भारी किरकिरी हुई. खुफिया विशेषज्ञ बताते हैं कि पठानकोट मामले में भी पाकिस्तान से जुड़ी जरूरी अभिसूचनाएं मुहैया कराने में रॉ का कोई योगदान नहीं रहा, जिसे बाकायदा रेखांकित किया गया है. नेपाल में भारत सरकार को लगातार मिल रहे कूटनयिक झटके के लिए रॉ की कमजोर अभिसूचना प्रणाली को ही दोषी ठहराया जा रहा है.

रॉ के कई खुफिया प्लान अंतरराष्ट्रीय फोरमों पर लीक होते रहे हैं, जिससे रॉ को कई बार अपने पैर पीछे खींचने पड़े और अपना ऑपरेशन रद्द करना पड़ा. टेलीकॉन ऑफ थंडरबोल्ट प्लान के लीक होने की घटना को रॉ की बड़ी नाकामी माना जाता है. रॉ के टॉप सीक्रेट प्लान का आधिकारिक पत्र (संख्या: जेज़ेडएक्स/629/ऑप्स/1/5 डीबी, दिनांक 16 जून 2015) दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गया था. इस पत्र पर रॉ के अधिकारी विशाल मौलजी, इश्मित मनोहर और कुणाल रोहित के बाकायदा हस्ताक्षर थे. कुछ अर्सा पहले भारतीय नौसेना और ताईवान के बीच होने वाली गोपनीय सैन्य-वार्ता की सूचना भी चीन को लीक हो गई थी. इस वजह से बैठक स्थगित कर देनी पड़ी. संदेह है कि वह सूचना भी रॉ के किसी क्रॉस एजेंट के जरिए ही चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्युरिटी (एमएसएस) को मिली थी. पाकिस्तान में रह रहे माफिया सरगना दाऊद इब्राहीम के बारे में सटीक सूचनाएं मुहैया कराने में भी रॉ फेल रहा है. भारत सरकार को दाऊद के बारे में सूचनाएं हासिल करने के लिए कभी अमेरिकी खुफिया एजेंसी तो कभी इजराइली खुफिया एजेंसी से चिरौरी करनी पड़ी है. इसे लेकर भी पीएमओ को गहरी नाराजगी है. केंद्र की भाजपा सरकार कई बार दाऊद को लेकर सार्वजनिक दावे करती रही, लेकिन फिर झेंप कर चुप्पी साधने पर विवश होती रही है.

कई विशेषज्ञों का मानना है कि संसदीय नियंत्रण नहीं होने के कारण रॉ में अराजकता व्याप्त है. रॉ की कोई अकाउंटिबिलिटी कानूनी प्रक्रिया के तहत तय (फिक्स्ड) नहीं है. सेना के सारे कार्य-कलाप सख्त सैन्य कानून के तहत नियंत्रित हैं, इसलिए सेना में अराजकता और अनुशासनहीनता नहीं है. एकमात्र पीएमओ के प्रति उत्तरदायी होने के कारण रॉ के अधिकारी अपने इस विशेषाधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हैं और विदेशी एजेंसियों से मनमाने तरीके से संपर्क साधते और फायदा उठाते हैं. रॉ के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम-काज के तौर तरीकों और धन खर्च करने पर अलग से कोई निगरानी नहीं रहती, न उसकी कोई ऑडिट ही होती है. रॉ के अधिकारियों की बार-बार होने वाली विदेश यात्राओं का भी कोई हिसाब नहीं लिया जाता. कौन ले इसका हिसाब? पीएमओ छोड़ कर किसी को इसका अधिकार नहीं है. उसमें भी सीधे प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार छोड़ कर कोई अन्य अधिकारी रॉ से कुछ पूछने या जलाब-तलब करने की हिमाकत नहीं कर सकता. रॉ के अधिकारी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में बेतहाशा आते-जाते रहते हैं. लेकिन दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीकी देशों में उनकी आमद-रफ्त काफी कम होती है. जबकि, इन देशों में रॉ के अधिकारियों का काम ज्यादा है. रॉ से कोई यह भी नहीं पूछ सकता कि अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों से वे किस तरह के भारत हित की सूचनाएं लाते हैं और देश को उसका क्या फायदा मिला है? अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे आलीशान देशों में रॉ अधिकारियों की पोस्टिंग अधिक क्यों होती है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अन्य दक्षिण एशियाई देशों या मध्य पूर्व के देशों में काफी कम क्यों? दक्षिण एशियाई देशों में जरूरत के मुताबिक निर्धारित संख्या से भी काफी कम अधिकारी तैनात हैं. ऐसे देशों में रॉ का कोई अधिकारी जाना ही नहीं चाहता. लेकिन इस अराजकता के बारे में रॉ से कोई कुछ नहीं पूछ सकता. रॉ में मध्यम और उससे नीचे के स्तर में होने वाली नियुक्तियों की कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है. कोई निगरानी नहीं है. रॉ के कर्मचारियों का सर्वेक्षण करें तो अधिकारियों के नाते-रिश्तेदारों की वहां भीड़ जमा है. सब अधिकारी अपने-अपने रिश्तेदारों के संरक्षण में लगे रहते हैं. तबादलों और तैनातियों पर अफसरों के हित हावी हैं. यही वजह है कि जिस खुफिया एजेंसी को सबसे अधिक पेशेवर (प्रोफेशनल) होना चाहिए था, वह सबसे अधिक लचर साबित हो रही है. रॉ में व्याप्त अराजकता के कारण ही विभागीय अफसर अनन्य चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और दो बच्चों की दिल्ली में हुई हत्या का रहस्य दो साल बाद भी नहीं खुल पाया है. चक्रवर्ती को फांसी से लटकी हुई हालत में और उनकी पत्नी जयश्री, 17 साल के बेटे अर्नब और 12 साल की बेटी दिशा को फर्श पर लहूलुहान हालत में बरामद किया गया था. रॉ ने यह कह कर मामला निपटाने की कोशिश की कि रॉ अधिकारी ने अपने परिवार के लोगों को मार कर खुद फांसी लगा ली, लेकिन यह दावा संदेह में लिपटा हुआ माना गया था और इसके पीछे गहरे षडयंत्र की आशंका जताई गई थी. रॉ के प्रभाव के कारण दिल्ली पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई. अनन्य चक्रवर्ती ने भुज

(शेष पृष्ठ 2 पर)

रॉ में लगी है गद्दारों की लंबी कतार

रॉ के दक्षिण-पूर्वी एशिया मसलों के प्रभारी व संयुक्त सचिव स्तर के आला अफसर मेजर रविंदर सिंह का सीआईए के लिए काम करना और सीआईए की साजिश से फरार हो जाना भारत सरकार को पहले ही काफी शर्मिंदा कर चुका है. रविंदर सिंह जिस समय रॉ के कवर में सीआईए के लिए क्रॉस-एजेंट के बतौर काम कर रहा था, उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. वर्ष 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद रविंदर सिंह भारत छोड़ कर भाग गया. उसकी फरारी के दो साल बाद नवंबर 2006 में रॉ ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की. मेजर रविंदर सिंह की फरारी का रहस्य ढूंढ़ने में रॉ को आधिकारिक तौर पर आजतक कोई सुराग नहीं मिल पाया. जबकि रॉ के ही अफसर अमर भूषण ने बाद में यह रहस्य खोला कि मेजर रविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमिंदर कौर सात मई 2004 को राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमारी शर्मा के छद्म नामों से फरार हो गए थे. उनकी फरारी के लिए सीआईए ने सात अप्रैल 2004 को इन छद्म नामों से बाकायदा अमेरिकी पासपोर्ट जारी किया था. इसमें रविंदर सिंह को राजपाल शर्मा के नाम से दिए गए अमेरिकी पासपोर्ट का नंबर था 017384251. सीआईए की मदद से दोनों पहले नेपालगंज गए और वहां से काठमांडू पहुंचे. काठमांडू में अमेरिकी दूतावास में तैनात फर्स्ट सेक्रेटरी डेविड वास्ला ने उन्हें रिसीव किया. काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे से दोनों ने ऑस्ट्रेलियन एयर की फ्लाइट (5032) पकड़ी और वाशिंगटन पहुंचे, जहां डल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईए एजेंट पैट्रिक बर्न्स ने दोनों को रिसीव किया और उन्हें मैरीलैंड ले गए. मैरीलैंड के एकांत आवास में रहते हुए ही फर्जी नामों से उन्हें अमेरिका के नागरिक होने के दस्तावेज तैयार करा के दिए गए, उसके बाद से वे गायब हैं. पीएमओ ने रविंदर सिंह के बारे में पता लगाने के लिए रॉ से बार-बार कहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि रॉ प्रधानमंत्री के तहत ही आता है. इस मसले में रॉ ने कई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के निर्देशों को भी ठेंगे पर रखा. रविंदर सिंह प्रकरण खुलने पर रॉ के कई अन्य अधिकारियों की भी पोल खुल जाएगी. इस वजह से रॉ ने इसे ठंडे बस्ते में छोड़

(शेष पृष्ठ 2 पर)

तालिबान ने कुलभूषण को अगवा किया और आईएसआई के हाथों बेच डाला

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव नाम के जिस भारतीय नागरिक को पकड़ कर रॉ का एजेंट बताया और उसे पकड़ने का श्रेय लेकर अपनी ही पीठ ठोकी उसके बारे में जर्मन राजनयिक गुंटर मुलैक ने कहा कि तालिबानों द्वारा अगवा किए गए कुलभूषण जाधव को खरीद कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपनी पीठ ठोक रही है. जर्मन राजनयिक की यह सूचना वाकई चौंकाने वाली है. बहरीन, कुवैत और सीरिया में राजदूत रह चुके जर्मन कूटनयिक गुंटर मुलैक ने कहा कि कुलभूषण जाधव को तालिबान ने कुछ दिनों पहले ही अगवा कर लिया था. कई दिनों तक तालिबान और पाकिस्तानी एजेंसी के बीच मोलभाव होता रहा. दोनों ओर से सहमति बनने के बाद तालिबान ने कुलभूषण जाधव को आईएसआई के हाथों बेच डाला. ईरान ने भी कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताए जाने का विरोध करते हुए पाकिस्तान को ऐसा करने से मना किया था. कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना में कमांडर (सर्विस नंबर:41558 ज़ेड) था. नौसेना में उसे इंजीनियरिंग कैडर के अफसर के रूप में कमीशन मिला था. उसने 1987 में संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा और सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड की स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के बाद नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में दाखिला लिया था. उसे नौसेना अकादमी से 1991 में कमीशन मिला था. कुलभूषण जाधव वर्ष 2002 तक नौसेना में रहा. उसके बाद वर्ष 2003 में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

संवेदनशील सूचनाएं नहीं मिलने के कारण भारत की किरकिरी

रॉ फेल

पृष्ठ 1 का शेष

के भूकंप में अनाथ हुई बच्ची को गोद लिया था और उसे दिशा नाम दिया था.

बहरहाल, इन सब अराजकताओं के कारण रॉ को ढांचागत स्तर पर सुधारने और टास्क ओरिएंटेड करने पर तेजी से काम चल रहा है. रॉ की पूरी प्रणाली को दुरुस्त करने के इरादे से ही उसकी एक शाखा एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी) को बंद कर उसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) और भारतीय वायुसेना के अधीन करने का निर्णय लिया गया. एविएशन रिसर्च सेंटर के जरिए रॉ किसी भी संवेदनशील स्थान की खुफिया तरीके से हवाई तस्वीरें और उस जगह चल रही गतिविधियां रिकॉर्ड करती थी. मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसे रॉ की अन्य शाखा एनटीआरओ और वायुसेना के तहत जोड़ने के फैसले पर पीएमओ की सहमति ली. उल्लेखनीय है कि रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी) के पास रूसी आईएल–76एस, एएन–32, ग्लोबल–5000 जेट और अमेरिकी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस के अत्याधुनिक विमानों का बेड़ा और एमआई–17 व फ्रांसीसी एलूते–2 और एलूते–3 किस्म के हेलीकॉप्टर हैं. एआरसी के विमानों की उड़ान खास तौर पर ओड़ीशा के चरबतिया, उत्तर प्रदेश के सरसावां, असम के तिनसुकिया और दिल्ली के पालम एयरबेस से होती है. एआरसी में अधिकतर अधिकारी कर्मचारी सेना और सुरक्षा बलों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं. एआरसी रॉ के लिए जवाबदेह है और एआरसी के प्रमुख रॉ प्रमुख के मातहत होते हैं.

पीएमओ की चिंता यह भी है कि रॉ में सीआईए या कुछ अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की अंदर तक बनी घुसपैठ कैसे रोकी जाए. कई ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं और कई ढंके–छुपे हुए हैं. रॉ के डायरेक्टर तक सीआईए के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं. लेकिन सामर्थ्य के आगे देशद्रोह का आरोप भी अधिक समय तक खड़ा नहीं रह पाया और वह बाइज्जत बरी हो गए. ऐसा ही वाकया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईबी का निदेशक बनने जा रहा था कि ऐन मौके पर पाया गया कि वह दिल्ली में तैनात महिला सीआईए अधिकारी हेदी अगस्ट के लिए काम कर रहा था. तब उसे नौकरी से जबरन रिटायर किया गया. भेद खुला कि सीआईए ही उस आईपीएस अधिकारी को आईबी का निदेशक बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से लॉबिंग कर रही थी. रॉ की अपनी काउंटर इंटेलिजेंस प्रणाली भी बुरी तरह फेल साबित हुई है. अराजकता का आलम यह है कि रॉ के अधिकारी और कर्मचारी यूनियनबाजी कर रहे हैं और काउंटर इंटेलिजेंस होने या उसका शक होने पर भी सीनियर अधिकारियों का घेराव करने और नारेबाजी करने से बाज नहीं आते. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रॉ जैसे संवेदनशील संगठन में सामान्य कल–कारखानों जैसी यूनियनबाजी और राजनीति देश के हित में नहीं है, इस पर कारगर तरीके से सख्त कानूनी बंदिशों के तहत रोक लगनी चाहिए.

फोटो– प्रभात पाण्डेय

रॉ में लगी है गद्दारों की लंबी कतार

पृष्ठ 1 का शेष

दिया. मेजर रविंदर सिंह कितना गिरा हुआ व्यक्ति था, इसका एक उदाहरण देखिए. भारतीय वायुसेना को मिग–21, मिग–23 और मिग–27 के लिए कैनोपीज़ की जरूरत थी. रूस में उस समय कैनोपीज़ उपलब्ध नहीं थी. लिहाजा, वायुसेना की टीम कैनोपीज़ के लिए सीरिया के दमस्कस गई. वहां पर तैनात रॉ अधिकारी मेजर रविंदर सिंह को वायुसेना की टीम की मदद में लगाया गया. रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सीरिया के साथ बातचीत हो रही थी कि सीरिया स्थित अमेरिकी राजदूत तक यह खबर पहुंच गई. बाद में यह रहस्य खुला कि गोपनीय सूचना मेजर रविंदर सिंह ने लीक की थी. इस घटना के बाद रविंदर सिंह को भारत वापस भेज दिया गया था. लेकिन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी को गोपनीय सूचनाएं देने का काम वह करता रहा. रॉ के भगोड़े गद्दारों की कमी नहीं है. विदेशी एजेंसियों के लिए क्रॉस एजेंसी करने और अपने देश से गद्दारी करने वाले ऐसे कई रॉ अधिकारी हैं, जो पकड़े जाने के डर से या प्रलोभन से देश छोड़ कर भाग गए. मेजर रविंदर सिंह जैसे गद्दार अकेले नहीं हैं. रॉ के संस्थापक रहे रामनाथ काव का खास सिकंदर लाल मलिक जब अमेरिका में तैनात था तो वहीं से लापता हो गया. सिकंदर लाल मलिक का आज तक पता नहीं चला. मलिक को रॉ के कई खुफिया प्लान की जानकारी थी. बांग्लादेश को मुक्त कराने की रणनीति की फाइल सिकंदर लाल मलिक के पास ही थी, जिसे उसने अमेरिका को लीक कर दिया था. मलिक की उस कार्रवाई को विदेश मामलों के विशेषज्ञ एक तरह की तख्ता पलट की कोशिश बताते हैं, जिसे इंदिरा गांधी ने अपनी बुद्धिमानी और कूटनीतिक सझ–बूझ से काबू कर लिया. मंगोलिया के उलान बटोर और फिर इरान के खुर्रमशहर में तैनात रहे रॉ अधिकारी अशोक साठे ने तो अपने देश के साथ निकृष्टता की इंतिहा ही कर दी. साठे ने खुर्रमशहर स्थित रॉ के दफ्तर को ही फूंक डाला और सारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज आग के हवाले कर अमेरिका भाग गया. विदेश मंत्रालय को जानकारी है कि साठे कैलिफोर्निया में रहता है, लेकिन रॉ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया. रॉ के सीनियर फील्ड अफसर एमएस सहगल का नाम भी रॉ के भगोड़ों में आव्वल है. लंदन में तैनाती के समय ही सहगल वहां से फरार हो गया. टोकियो में भारतीय दूतावास में तैनात रॉ अफसर एनवाई भास्कर सीआईए के लिए क्रॉस एजेंट का काम कर रहा था. वहीं से वह फरार हो गया. काठमांडू में सीनियर फील्ड अफसर के रूप में तैनात रॉ अधिकारी बीआर बच्चर को एक खास ऑपरेशन के सिलसिले में लंदन भेजा गया, लेकिन वह वहीं से लापता हो गया. बच्चर भी क्रॉस एजेंट का काम कर रहा था. रॉ मुख्यालय में पाकिस्तान डेस्क पर अंडर सेक्रेटरी के रूप में तैनात मेजर आरएस सोनी भी मेजर रविंदर सिंह की तरह पहले सेना में था, बाद में रॉ में आ गया. मेजर सोनी कनाडा भाग गया. रॉ में व्याप्त अराजकता का हाल यह है कि मेजर सोनी की फरारी के बाद भी कई महीनों तक लगातार उसके अकाउंट में उसका वेतन जाता रहा. इस्लामाबाद, बैंकॉक, कनाडा में रॉ के लिए तैनात आईपीएस अधिकारी शमशेर सिंह महाराजकुमार भी भाग कर कनाडा चला गया. इसी तरह रॉ अफसर आर वाधवा भी लंदन से फरार हो गया. केवी उन्नीकृष्णन और माधुरी गुप्ता जैसे उंगलियों पर गिने जाने वाले रॉ अधिकारी हैं, जिन्हें क्रॉस एजेंसी या कहें दूसरे देश के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सका. पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग में आईएफएस ग्रुप–बी अफसर के पद पर तैनात माधुरी गुप्ता पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी के साथ मिल कर भारत के ही खिलाफ जासूसी करती हुई पकड़ी गई थी. माधुरी गुप्ता को 23 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह, अर्सा पहले रॉ के अफसर केवी उन्नीकृष्णन को भी गिरफ्तार किया गया था. पकड़े जाने वाले रॉ अफसरों की तादाद कम है, जबकि दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी के साथ साठगांठ कर देश छोड़ कर भाग जाने वाले रॉ अफसरों की संख्या कहीं अधिक. ■

पीएमओ की चिंता यह भी है कि रॉ में सीआईए या कुछ अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की अंदर तक बनी घुसपैठ कैसे रोकी जाए. कई ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं और कई ढंके–छुपे हुए हैं. रॉ के डायरेक्टर तक सीआईए के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं. लेकिन सामर्थ्य के आगे देशद्रोह का आरोप भी अधिक समय तक खड़ा नहीं रह पाया और वह बाइज्जत बरी हो गए. ऐसा ही वाकया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईबी का निदेशक बनने जा रहा था कि ऐन मौके पर पाया गया कि वह दिल्ली में तैनात महिला सीआईए अधिकारी हेदी अगस्ट के लिए काम कर रहा था.

तालिबान ने कुलभूषण को अगवा किया और आईएसआई के हाथों बेच डाला

पृष्ठ 1 का शेष

उसने ईरान के चाबहार में व्यापार शुरू किया. व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह जाता रहता था. लेकिन उसे एक दिन अचानक उठा कर रॉ का एजेंट करार दे दिया जाएगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. मुंबई और पठानकोट जैसे हादसों में पाकिस्तान के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद से बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को कुलभूषण जाधव के रूप में बलि का बकरा मिल गया. उस पर तरह–तरह के आरोप लादे जा रहे हैं. हालांकि, शुरुआत में पाकिस्तान ने भी कहा था कि कुलभूषण का विभिन्न बंदरगाहों पर माल लाने ले जाने का धंधा है. अब, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के जरिए भारत पर पाकिस्तान में जासूसी करने और बलूचिस्तान में हिंसा फैलाने के आरोप मढ़ रहा है. ■

अल कायदा ने रॉ को मेल पर बताया था, सीआईए के हाथों मारा जा चुका है मेजर रविंदर

रॉ के दक्षिण–पूर्वी एशिया मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव मेजर रविंदर सिंह के देश छोड़ कर भागने की सनसनीखेज घटना के कुछ ही दिन बीते थे. पूरा देश और पूरी दुनिया उस फरारी पर तरह–तरह के कयास लगाने में लगी थी. मशक्कतों के बाद भी भारत सरकार को अपने फरार एजेंट का पता नहीं चल पा रहा था. तभी रॉ को मेल पर मिले एक संदेश ने इस खुफिया तंत्र को बौखला कर रख दिया. मेल पर कुख्यात आतंकी संगठन अल कायदा ने रॉ को सनसनीखेज संदेश भेजा था और अमेरिका से सतर्क रहने की सलाह दी थी.

अल कायदा ने लिखा था कि सीआईए ने भारत से भागने में रविंदर सिंह की मदद की और बाद में उसकी हत्या करा दी. अल कायदा की इस सूचना का रॉ के पास कोई जवाब नहीं था, आज तक नहीं है. फरार एजेंट का आज तक कहीं पता नहीं चला. अगर वह अमेरिका में भी छद्म नाम से रह रहा होता तो किसी को तो दिखता, कहीं तो दिखता! न कहीं वह जिंदा मिला और न कहीं उसकी लाश ही मिली. अल कायदा ने अमेरिका के हाथों खिलौना बनने से रॉ को सचेत करते हुए लिखा था कि अमेरिका किसी का नहीं. ■

मंत्री जसवंत सिंह और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा शामिल थे. पूर्व राज्यपाल व सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ गिरीश सक्सेना कमेटी, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव डॉ. माधव गोडबोले कमेटी और पूर्व रक्षा मंत्री अरुण सिंह कमेटी की रिपोर्टें भी सामने रखी गई हैं, लेकिन समीक्षा के बाद सक्सेना कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर केंद्र गंभीर है. उक्त चारों कमेटियों ने के. सुब्रमण्यम की करगिल रिव्यू कमेटी (केआरसी) की रिपोर्ट का अलग–अलग आयामों से विस्तार से अध्ययन किया था. करगिल रिव्यू कमेटी ने यह माना था कि खुफिया अभिसूचनाएं एकत्र करने में नाकामी और खुफिया एजेंसियों में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण करगिल में घुसपैठ की घटना घटी और देश को अनावश्यक युद्ध लड़ना पड़ा और शहादतों का भारी नुकसान झेलना पड़ा. रॉ और आईबी दोनों ही केआरसी की रिपोर्ट से असहमत थी. गिरीश सक्सेना कमेटी ने 244 पेज की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व और निगरानी में नेशनल इंटेलिजेंस बोर्ड का गठन किए जाने की सिफारिश कर रखी है. नेशनल इंटेलिजेंस बोर्ड में रॉ, आईबी, डीआरआई, थलसेना–वायुसेना–नौसेना की खुफिया इकाइयों के प्रमुखों को सदस्य के बतौर शरीक किए जाने का प्रावधान है, ताकि बेहतर समन्वय के साथ अभिसूचनाएं एकत्र करने या टास्क पूरा करने का काम प्रोफेशनल तरीके से संपादित हो सके. पूर्व रक्षा मंत्री अरुण सिंह की कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत सेना के तीनों अंगों को मिला कर अलग से डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की सिफारिश की थी. मोदी सरकार के पहले मनमोहन सरकार ने रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (रॉ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के बीच बेहतर समन्वय और प्रोफेशनल कार्यप्रणाली बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा था. यूपीए सरकार ने यह विचार किया था कि देश की बाह्य, अंदरूनी और सैन्य खुफिया एजेंसियां नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी के तहत रखी जाएं और अथॉरिटी देश की सारी खुफिया एजेंसियों पर नियंत्रण रखे. लेकिन सेना के विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक करार दिया था. इस तरह कांग्रेस सरकार का वह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 12
23 मई–29 मई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

अमित शाह के यूपी दूत सुनील बंसल ने कहा, भाजपा सबको साथ लेकर चलेगी, मुस्लिमों को भी

राम मंदिर भाजपा का चुनावी मुद्दा नहीं

फोटो : सुरेश वर्मा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे-धीरे सरगर्म होता जा रहा है. दिल्ली और बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने के पहले फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. ऐसा दिख रहा है कि भाजपा वैचारिक बदलाव की प्रक्रिया में है. कई ज्वलंत मसले हैं जिन पर भाजपा के विचार पहले कुछ और थे अब कुछ और. ऐसे कई मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खास दूत और उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री (संगठन) **सुनील बंसल** से **प्रभात रंजन दीन** की पिछले दिनों विस्तार से बातचीत हुई. उस बातचीत के प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं...

सवाल: भाजपा अपने ही मुद्दों से अलग हटती दिखाई दे रही है. राम मंदिर का मसला हो या समान आचार संहिता का या धारा-370 का. धर्म के विचार-बिन्दु से अलग हटकर व्यापक जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने पर भाजपा का अधिक ध्यान है. पार्टी पर जिन लोगों या समुदायों का पारंपरिक वर्चस्व रहा है, वह तेजी से टूट रहा है. चुनाव के संवेदनशील समय में इसका नकारात्मक असर भी पड़ेगा. इससे कैसे निपटेंगे? क्या भाजपा सम्पूर्ण वैचारिक बदलाव की प्रक्रिया में है?

बंसल: देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो विश्लेषण है कि हम 20 प्रतिशत की राजनीति करते रहे हैं. उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है. जो हमारा अपना है, जो भाजपा के साथ जुड़ा रहा है, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या वैश्य हो. यह बड़ा समुदाय भाजपा की पारंपरिक ताकत के रूप में रहा. राम मंदिर आंदोलन के कारण ब्राह्मण वर्ग भी बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ा. लेकिन हम उसी 20 प्रतिशत के बीच की ही राजनीति करते रहे. हमने 40 प्रतिशत पिछड़ों और 20 प्रतिशत दलितों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यह 60 फीसदी वर्ग हमसे छूटता चला गया. पिछले कई साल से भाजपा पर एक टैग लगा कि भाजपा शहरी लोगों की पार्टी है, भाजपा अगड़े लोगों की पार्टी है, भाजपा अमीर लोगों की पार्टी है. ऐसे टैग लगाते थे लोग. इसमें कुछ सत्य भी था. चुनावों में हम शहरों में ज्यादा जीतते थे और ग्रामीण इलाकों में कम जीतते थे. लोग कहते थे कि यह तो शहरियों की पार्टी है. जीतने वालों में पिछड़े और दलित कम होते थे और अगड़ी जाति के अधिक होते थे. उत्तर प्रदेश में भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए सौ प्रतिशत की राजनीति करनी होगी. 20 प्रतिशत के आधार पर आप संगठन तो चला सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते. व्यापक राजनीति के लिए हमें सौ प्रतिशत की राजनीति करनी होगी. अगर भाजपा को प्रदेश में सरकार बनानी है तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो हमारा अपना भी है उसे भी और जो हमसे दूर चला गया है, उसे भी. जैसे कल्याण सिंह जी के समय बहुत सारे लोग साथ थे, बाद में दूर चले गए, उन्हें फिर से साथ लाया जा रहा है. सबको साथ लाना ही होगा. अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में बढ़ना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको मतलब मैं 20 प्रतिशत मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहा हूं. हमें 20 फीसदी मुस्लिमों के बारे में भी सोचना होगा. हम यह नहीं कर सकते कि मुस्लिम समाज की उपेक्षा करके राजनीति करें. उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता. हम वोटों को बांटकर राजनीति नहीं कर सकते कि यह वोट मुसलमानों का है या यह वोट मायावती है, यह वोट इनका है या उनका है. यानी, सबको दूर करके और अपनी ही गुफा में सीमित रहकर हम व्यापक राजनीति नहीं कर सकते. हमने जब यह प्रयोग शुरू किया तो उसका बेहतरीन उदाहरण सामने आया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश का प्रभारी होने के नाते लोकसभा चुनाव के पहले एक साल तक गहराई से अध्ययन किया और इसे देखते हुए ही लोकसभा चुनाव में सामाजिक, सर्वस्पर्शी, सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में हम 73 सीटें जीतकर आए. दलित और पिछड़े समाज के सभी वर्गों के बीच इतना अच्छा टिकट वितरण हुआ कि छोटे-छोटे समाज के लोग जो भाजपा से अलग थे या अपना नहीं मानते थे, वे सब भी जीते और भाजपा से जुड़े. यादव समुदाय का भी वोट हमें मिला. जाटव समाज का भी वोट मिला. हमने जाटव समाज के लोगों को भी लड़ाया और जिताया. इसका अर्थ क्या है कि समाज तैयार है, लोग तैयार हैं, हम उन्हें अपना तो कहें और अपना तो मानें. इस आधार पर योजना बनाई गई तो परिणाम अच्छा आ गया. मेरा मानना भी यही है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे हैं वे तो हैं ही, उन्हें साथ लेकर चलना है, उनकी चिंता करनी है, उनको महत्व मिलना चाहिए क्योंकि पार्टी तो उन्होंने खड़ी की, जिंदगी तो उन्होंने लगाई, इसलिए उन सबकी भी चिंता करनी है, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चलना ही होगा. जो आपने कहा ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व टूटता देखकर नकारात्मक चर्चाएं करते हैं, या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, उसमें भाजपा में सभी लोग साथ में रहेंगे.

सवाल: राम मंदिर निर्माण का मसला भाजपा के लिए प्राथमिकता पर नहीं रहा. सौ प्रतिशत को साथ लेकर चलने के तर्क में समान आचार संहिता और धारा-370 के मसले से बचने का उपाय तलाशता हुआ भाजपा का चेहरा नज़र आता है. उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, इसे लेकर आप लोगों को क्या जवाब देंगे? राम मंदिर चुनाव का मसला बनेगा कि नहीं?

बंसल: देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मसला नहीं है. यह हमारी आस्था का मसला है. जब भी चुनाव आता है तो राम मंदिर की चर्चा शुरू हो जाती है. सिंहस्थ कुंभ में भी साधु-संतों ने यह मांग की. चलेगा यह सब, इस तरह की चर्चाएं तो चलती रहेंगी. लेकिन यह स्पष्ट है कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी मुद्दा नहीं है. हम राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राम मंदिर हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है.

सवाल: अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर की चर्चा खूब तेज हुई. सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक बोल गए कि एक महीने के अंदर ही मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा. लेकिन फिर भाजपा ने अचानक चुप्पी साध ली. भाजपा ने अचानक अपना पैंतरा क्यों बदल लिया?

बंसल: देखिए राम मंदिर को लेकर हमने कोई पैंतरा या रणनीति नहीं बदली. हमारा स्पष्ट मानना है कि यह करना ठीक नहीं है. राम मंदिर चुनावी मसला नहीं है, यह आस्था का विषय है. हमारा कमिटमेंट है कि राम मंदिर बने, लेकिन उसको चुनावी इश्यू बनाकर, एजेंडा बनाकर करने का कोई लाभ नहीं है.

सवाल: नए प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जिस जाति से आते हैं, उसे प्रभावशाली राजनीतिक फैक्टर के रूप में कभी नहीं देखा गया. आप इसका क्या फायदा देखते हैं? पिछड़ा वर्ग की अन्य दबंग व प्रभावशाली जातियों के कद्दावर नेताओं को पार्टी में शरीक कराने की अंदरूनी तैयारियां पटल पर कब आ रही हैं, क्योंकि समय तो अब परिपक्व हो चुका है, इसे उद्घाटित करने का?

बंसल: ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि अब सौ प्रतिशत सबको साथ लेकर चलने की योजना पर पार्टी अग्रसर है. हम किसी भी वरिष्ठ नेता का अपनी पार्टी में सम्मान के साथ स्वागत करने को तैयार हैं. जहां तक केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाए जाने का मसला है, वे पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन के सिस्टम से निकले हुए हैं और दूसरे कि वो जिस समुदाय से आते हैं उनमें भी बहुत उत्साह है और वे पार्टी से बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं. लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का सोशल कॉम्बिनेशन बदला है. यह सहज है कि अब लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं. इस तरह का अब सहज-स्वाभाविक माहौल बन रहा है. मैं अभी किसी बड़े नेता का नाम स्पष्ट तौर पर नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस में हों या बसपा में हों या समाजवादी पार्टी में हों और वहां खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हों या परेशान हों तो भाजपा उनका स्वागत करेगी और सम्मान देगी. देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसी कई बातें होती हैं, क्या होता है, क्या निर्णय होगा, अंतिम समय तक पता नहीं होता. जहां तक भाजपा के लीडरशिप का प्रश्न है तो मैं यह कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में हर जाति और हर समुदाय का प्रभावी नेता उभर कर सामने आया है.

सवाल: इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोन वाइज़ चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है. जोन को महत्वपूर्ण दायित्व देकर और उसे परिणामकारी बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति क्या पार्टी के लिए व्यावहारिक साबित होगी? या यह फार्मूला प्रति-उत्पादी (काउंटर प्रोडक्टिव) साबित होगा?

बंसल: ऐसा है कि भाजपा में पहले से जोन बने हुए हैं. यह कोई नई बात नहीं है. प्रदेश में आठ जोन हैं. उसके अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी है, बाकायदा पूरी टीम है. ये जोन स्टेट की फंक्शनिंग का हिस्सा हैं, जो जिले और प्रदेश के बीच में कड़ी का काम करते हैं. अब आठ जोन को कम कर छह जोनों में तब्दील किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है कि इलेक्शन मैनेजमेंट को कारगर तरीके से परिणामकारी बनाने के लिए छह जोनों को प्रभावकारी बनाया जाना आवश्यक है. छह जोन इतने ताकतवर हों कि चुनाव प्रचार अभियान से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं सब कारगर तरीके से हो सकें और उसकी सटीक मॉनिटरिंग की जा सके, यह अकेले लखनऊ से संभव नहीं.

सवाल: उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियों में चुनावी सरगर्मियां और तैयारियां दिख रही हैं. लेकिन भाजपा की तैयारी पटल पर कहीं नहीं दिख रही. यह रणनीति का हिस्सा है या तैयारी का अभाव है?

बंसल: भाजपा की तैयारी तो पिछले छह महीने से चल रही है. बूथों के गठन का काम चल रहा है. एक लाख 40 हजार बूथों में से एक लाख 13 हजार बूथों का गठन हो चुका है, मई महीने तक बूथों के गठन का बाकी काम भी पूरा हो जाएगा. बूथों के गठन के काम को साथ-साथ वैरीफाइ भी किया जा रहा है. वोटर लिस्ट के द्वारा और दूसरे दस्तावेजों के जरिए. कुल बूथ हैं एक लाख 40 हजार. ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम के तहत 56 हजार ग्राम पंचायतों में से करीब 36 हजार ग्राम पंचायतों में भाजपा के कार्यकर्ता गए और मोदी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को लोगों को बताया. गांवों में छोटी-छोटी चौपालें लगाकर लोगों से संवाद बनाया. हम लोग 56 हजार ग्राम पंचायतों में जाएंगे. चुनाव की तैयारियां तो हमारी चल रही हैं, लेकिन बहुत ही साइलेंटली ग्राउंड लेवल पर चल रही हैं. यह रणनीति है, यह ग्राउंड लेवल पर हमारा कैंपेन है, जिसका असर चुनाव में दिखेगा.

सवाल: प्रदेश अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों हुई? अभी तमाम कमेटियां बननी बाकी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना अभी बाकी ही है. तो पार्टी चुनाव कब लड़ेगी?

बंसल: प्रदेश अध्यक्ष बनने में तकरीबन एक महीने की देरी हुई यह मानता हूं. देर तो हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ. इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लैक्ट भी पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ा है. इसलिए उस दृष्टि से बाकी होमवर्क पूरा करके रखा हुआ था. मई तक संगठनात्मक काम पूरा कर लिया जाएगा. जिला अध्यक्षों के चयन का काम करीब-करीब पूरा कर लिया गया है. मई में ही जिला कमेटियां बन जाएंगी और प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन कर लिया जाएगा. नया संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का काम मई महीने में पूरा हो जाएगा, यानी इससे अधिक डिले हम और नहीं करेंगे और उसके बाद हम सब चुनावी प्रक्रियाओं में उतर जाएंगे.

सवाल: नए अध्यक्ष को अपने मुताबिक टीम चुनने का कोई मौका नहीं मिला. अध्यक्ष चुने जाने के पहले ही तकरीबन 50 जिला अध्यक्ष चुन लिए गए थे. यह कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है?

बंसल: भाजपा में संगठन के चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में पूरा किया जाता है. बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक. सबसे पहला काम बूथ इकाई का अध्यक्ष चुनना, उसके बाद उनके माध्यम से मंडल अध्यक्ष चुनना और मंडल अध्यक्षों के जरिए जिला अध्यक्षों का चुनाव कराना. इसके बाद जिला अध्यक्ष ही प्रदेश के अध्यक्ष को चुनते हैं. इस प्रक्रिया के लिहाज से यह तो जरूरी है न कि प्रदेश अध्यक्ष के पहले जिला अध्यक्ष चुन लिए जाएं.

सवाल: अव्वल तो उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों का चयन चुनाव की प्रक्रिया से तो हुआ ही नहीं. चुनाव की प्रक्रिया के दरम्यान मतभेद, गुटबाजी और हिंसा जैसी कई घटनाएं सतह पर आईं. बाद में सारा निर्णय बंद कमरे में ही लेना पड़ा. प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के पहले करीब 50 जिला अध्यक्ष चयनित हुए. आप कहते हैं कि सारे जिला अध्यक्ष मिलकर नया प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं तो सारे जिला अध्यक्ष पहले ही क्यों नहीं चुन लिए गए, 25 छोड़ क्यों दिए गए? जिला अध्यक्षों को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने का मौका क्यों नहीं दिया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मन और अपने पसंद का प्रदेश अध्यक्ष कैसे मनोनीत कर दिया? इससे क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित नहीं हुई?

बंसल: सामान्यतः चुनाव का अर्थ यह ही नहीं है कि वोट डले. चुनाव का अर्थ यह भी है कि सर्वसम्मति से सब लोग मिलकर चुन लें. भारतीय जनता पार्टी में हमने उस प्रक्रिया को अपनाया कि सब मिलकर के चुन लें, इससे संगठन का समूहिक निर्णय उभरकर सामने आता है. इस बार के जिला अध्यक्षों के चुनाव में सामूहिक निर्णय के आधार पर ही, यानी चुनाव अधिकारी गए, मंडल अध्यक्षों से राय ली, वरिष्ठ नेताओं से बात की और इस आधार पर जो पैनल बना, उस आधार पर ही जिला अध्यक्ष चुने गए. इस बार अपनाई गई इस प्रक्रिया में कहीं से भी कोई विरोध सामने नहीं आया. जिला अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोटर होता है. यही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करता है. इस तरह प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बाकायदा एक प्रक्रिया रहती है.

सवाल: यानी, कागज पर सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं. केशव जी का चयन तो उस प्रक्रिया से हुआ नहीं. केशव जी का चयन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन से हुआ?

बंसल: हां, केशव जी का चयन नहीं हुआ, उनका मनोयन हुआ. 50 प्रतिशत अगर जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हों तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है. इसी तरह अगर 50 प्रतिशत प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हों तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है. इसके बाद जो होगा वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन से ही होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा केशव जी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए. अब केशव जी चुने हुए जिला अध्यक्षों को मनोनीत कर रहे हैं.

सवाल: बड़े-बड़े नेताओं के छोटे-छोटे हित जो पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे निबटने की कोई रणनीति है कि नहीं?

बंसल: वरिष्ठों का पार्टी में सम्मान रहना चाहिए. देखिए हमारा मानना है कि भाजपा में जो भी हमारे ऐसे सहयोगी हैं, उनका भी तो सपना है कि भाजपा प्रदेश में फिर से ताकतवर बने. भाजपा अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा. अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो मैं भी छोटा ही नेता बना रहूंगा. सरकार बनेगी तो सबका कद बढ़ेगा. इसलिए सब लोगों का संगठन में उपयोग करते हुए और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति हम बना रहे हैं, उससे कोई अपने आपको अलग नहीं समझे. सबको साथ लेकर चलने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम पुरानों को छोड़ दें और नए को आगे लेकर चलें.

सवाल: हर सुबह एक चर्चा होती है कि बंसल तो आज जा रहे हैं, इसका फीडबैक आपको भी मिलता होगा. इसका कैडर में नकारात्मक असर जा रहा है. यह चर्चा बहुत ही नियोजित तरीके से फैलाई जा रही है. इस तरह की नकारात्मक चर्चाएं पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती हैं कि नहीं, जो नई व्यवस्था में प्रतिबद्धता से संलग्न हैं? आप इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं?

बंसल: सामान्यतः मेरा काफी लंबा समय हो गया सामाजिक जीवन में काम करते हुए. लगभग 26 साल लग गया सामाजिक काम में. ऐसे विषयों में मेरा मानना है कि अपना काम ईमानदारी से करते चलना है. इसी मूल मंत्र पर चलने के कारण मैं न परेशान होता हूं और न निराश होता हूं. मेरा काम है करना, इसी कारण से धीरे-धीरे जो ऐसे लोग हैं वो अपने आप संगठन में आइसोलेट हो रहे हैं. अपने आप हो रहा है यह सब. उनके लिए ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में बहुत उत्साह है. कार्यकर्ता ग्राउंड पर चाहता है कि भाजपा खड़ी हो तभी तो वह मोटिवेट होकर उत्तर प्रदेश में दो करोड़ तीन लाख सदस्य बना लेता है. जबकि हम लोगों ने डेढ़ करोड़ का लक्ष्य रखा था. यह कुछ लोग नहीं हैं बल्कि भाजपा के लाखों कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं. भाजपा का कार्यकर्ता 50 लाख फॉर्म भरवाकर ले आता है, इसे आप क्या कहेंगे. दो करोड़ तीन लाख सदस्यों का पूरा डाटा पार्टी के पास है, जिलावार, बूथवार और विधानसभावार. जिन्हें लगता है कि उनकी मोनोपॉली समाप्त हो रही है, यह दरअसल दोष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है. यह एक माइंडसेट बन गया है एक लंबे समय के दरम्यान. उनके दिमाग में यह स्थापित हुआ है कि भाजपा में गुटबाजी होगी, जातिवाद होगा, परिक्रमा होगी, नेताओं के आगे-पीछे घूमो, लोगों ने वर्षों से यही राजनीति की है. जो देखा उसी की नकल पर चलते रहे और पूरी पार्टी परिक्रमा और मिठाई के पैकेट पर चलती रही. यही बड़े नेताओं ने दिखाया, बताया और सबने यही सीखा. लेकिन जब हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया तो यह मैसेज गया कि काम करो तभी पार्टी में आगे बढ़ सकोगे.

सवाल: नई व्यवस्था के तहत अब सांगठनिक बैठकों में भाषण प्रतियोगिता का ऊबाऊ चलन समाप्त हुआ है. अब चुने हुए लोग ही बोलते हैं और प्रोडक्टिव बैठकें होती हैं. इससे बातबहादुर नेता नाखुश हैं, इसे आप कैसे देखते हैं?

बंसल: उसमें कई समस्याएं थीं. पहले तो छह महीने मैंने कई बातें ऑब्ज़र्व कीं. बैठक में मंच पर पीछे से कुर्सियां उठ उठ कर आती रहती थीं और धीरे-धीरे मंच नेताओं से भर जाता था. फिर स्वागत का क्रम चलता था, देर तक माल्यार्पण ही चलता रहता था. फिर भाषण का क्रम शुरू होता था. सामने बैठा कार्यकर्ता ऊबता था, ऊंघता था. उसकी मजबूरी थी कि वह नेताओं के भाषण सुनना ड्यूटी समझता था. फिर मैंने समझा कि यह ठीक नहीं है. मीटिंग में आने की औपचारिकता पूरी करने के चलन को मैंने रोका. बैठक को प्रोडक्टिव बनाया. अब बैठकें होती हैं और उनमें समय का रचनात्मक इस्तेमाल होता है. अब मैंने पूरे सिस्टम को टू-वे कर दिया है, ताकि कार्यकर्ता भी अपना सीधा जुड़ाव महसूस कर सकें. बिना इन्वॉल्वमेंट के सफलता नहीं मिल सकती.

सवाल: चलते-चलते यह सवाल भी... देश के खिलाफ अब खुलेआम नारे लग रहे हैं, संविधान और क़ानून के डर का आवरण जैसे खत्म होता दिख रहा है. आपकी राष्ट्रवादी सरकार इससे निपटने में डरती क्यों है? क्या केवल भारत माता की जय कहने से काम चल जाएगा?

बंसल: ऐसा लगता है कि और कठोर क़ानून बनाने की आवश्यकता है. देश के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. ऐसे क़ानून जिसका सहारा लेकर ऐसे तत्व बच जाते हैं, उसे रोकने के लिए और सख्त क़ानून लाने की जरूरत है. इस मसले पर समाज में जागरूकता पैदा हुई है, यह सकारात्मक संकेत है. ■

अब तक 20 प्रतिशत की ही राजनीति करती रही है भारतीय जनता पार्टी

अब 40 फीसदी पिछड़े, 20 फीसदी दलित और 20 फीसदी मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेंगे

feedback@chauthiduniya.com

ओड़ीशा से पोस्को का जाना

स्थानीय सहमति और सहभागिता की उपेक्षा का नतीजा

बिभूतिपति

दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को (पोहांग स्टील कंपनी) ने ओड़ीशा में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील प्लांट की अपनी महत्वकांक्षी परियोजना से पीछे हटने का फैसला किया है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में यह परियोजना अपने समय की सबसे बड़ी परियोजना थी. लेकिन पिछले एक दशक से जारी विरोध प्रदर्शन, अदालती कार्रवाई और काम में आई बार-बार की रुकावट के बाद पोस्को ने इस एकीकृत परियोजना से अपने हाथ खींचने का फैसला किया है. इस बात का खुलासा कंपनी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष इस परियोजना से संबंधित सुनवाई के दौरान किया. पोस्को ने ट्रिब्यूनल के सामने यह साफ किया कि ओड़ीशा में स्टील प्लांट और उससे संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है. वर्ष 2005 में ओड़ीशा के जगतसिंहपुर में पोस्को द्वारा स्टील प्लांट स्थापित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के ज़बरदस्त विरोध, पर्यावरणीय मंजूरी (एनवॉयरनमेंट क्लीयरेंस) एवं भूमि अधिग्रहण में आई परेशानियों की वजह से दस साल बाद भी इस प्लांट पर काम शुरू नहीं हो सका. लेकिन उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से यह परियोजना दिन का उजाला नहीं देख सकी.

पोस्को मामला भारत के सबसे गरीब जिलों में विकास के नाम पर लंबे समय तक चलने वाली बेनतीजा प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है. इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत कितना मुश्किल देश है. बहरहाल काफी समय पहले ही यह लगने लगा था की पोस्को जगतसिंहपुर के अपने विवादित स्टील प्लांट के निर्माण से पीछे हट जाएगा. इस बात का इशारा उसी वक्त मिल गया था जब जगतसिंहपुर में उसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसइजेड) की मंजूरी साल 2014 में समाप्त हो गई थी और कंपनी ने उसके रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं दिया था.

स्टील प्लांट और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत परियोजना के तहत अक्टूबर 2006 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एसइजेड को मंजूरी दी थी. जिसके तहत पोस्को को 1,601.6 एकड़ भूमि पर एसइजेड विकसित करने का काम मिला था. लेकिन इस भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ इसलिए इस परियोजना पर कभी काम शुरू नहीं हो सका. इस परियोजना को शुरू करने के लिए मांगी गई अतिरिक्त समय सीमा 24 अक्टूबर 2014 को समाप्त हो गई थी, इसके बाद समय सीमा बढ़ाने के लिए कंपनी ने आवेदन नहीं दिया. ओड़ीशा सरकार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ ओड़ीशा के उदासीन रवैये को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय के विकास आयुक्त ने पोस्को के एसइजेड की मंजूरी रद्द करने की सिफारिश कर दी थी.

इस परियोजना से पीछे हटने का पोस्को का फैसला अचानक नहीं हुआ. यह बात भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चो हुन के ओड़ीशा की राजधानी भुवनेश्वर के हालिया दौरे में दिए गए बयान से भी साबित होती है. हुन ने कहा था कि पिछले एक वर्ष के दौरान पोस्को ने जगतसिंहपुर प्रोजेक्ट पर दक्षिण कोरिया सरकार से मदद नहीं मांगी है और न ही यह मुद्दा भारत-दक्षिण कोरिया के बीच हुई हालिया द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उठा. अब सवाल यह उठता है कि पोस्को ने इस परियोजना से पीछे हटने का फैसला क्यों किया? क्या जनता के विरोध की वजह से ऐसा हुआ? या भूमि अधिग्रहण में ओड़ीशा सरकार की नाकामी इसका कारण बनी? या फिर इसकी कोई और वजह थी? भूमि अधिग्रहण में अत्यधिक विलम्ब के साथ-साथ पर्यावरण मंजूरी से जुड़े मामले पोस्को के लिए चिंता का विषय बने हुए थे. लेकिन दस साल लंबे इंतजार के बाद कंपनी के इस परियोजना से पीछे हटने के केवल यही कारण नहीं थे. हालांकि, लोगों को यह भी लग सकता है कि पोस्को का यह फैसला तात्कालिक है, लेकिन हकीक़त यह है कि इस फैसले के लिए कम से कम एक साल पहले से ज़मीन तैयार की जा चुकी थी.

दरअसल, मार्च 2015 में केंद्र सरकार द्वारा खदानों की नीलामी से संबंधित पारित क़ानून इस परियोजना के ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ. हालांकि इस क़ानून के पारित होने से पहले ओड़ीशा सरकार ने पोस्को को यह आश्वासन दिया था कि उसे खदान की लीज मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन अब इस नए क़ानून के मुताबिक़ उसे खदानों की नीलामी में भाग लेना होगा. ज़ाहिर है, नीलामी में यह आशंका तो बनी ही रहेगी कि उसे खदानों की लीज मिलेगी या नहीं? दूसरा प्रतिस्पर्धा के आधार पर बोली लगने की वजह से खनिज की लागत भी बढ़ सकती है. इस दौरान वैश्विक बाज़ार में स्टील की कीमतों में लगातार गिरावट आई है. लिहाजा इस परियोजना की व्यावहारिकता भी सवालों के घेरे में आ गई है. पिछले साल भारत में पोस्को के प्रवक्ता आईजी ली ने पोस्को का पक्ष साफ करते हुए कहा था कि हमें देखना होगा कि इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी और यह आर्थिक तौर पर व्यावहारिक है या नहीं. उन्होंने यह भी कहा था कि आखिरी निर्णय नीलामी का पूरा विवरण आने के बाद ही लिया जाएगा.

बहरहाल, पोस्को ने नीलामी में भाग नहीं लिया था और उसके फौरन बाद अपने स्टाफ की संख्या में भी कटौती करके उसने अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी थी. ओड़ीशा सरकार की मदद से कंपनी ने केंद्र सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली. ओड़ीशा के स्टील और खान मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक के मुताबिक पोस्को को रियायत देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया. उसके बाद पोस्को को यह फैसला करना था कि वह नीलामी में हिस्सा ले या नहीं, और नीलामी उसके लिए व्यावहारिक है या नहीं.

निवेश की इस दुर्गति में पोस्को, राज्य और केंद्र सरकार और राज्य की जनता सभी शामिल हैं. पोस्को के वापस जाने के फैसले के बाद क्या फिर सब कुछ वहीं वापस चला गया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. शायद नहीं! क्योंकि इस परियोजना पर पूरी तरह से पर्दा गिरना अभी बाकी है. सरकार के फैसले वापस हो सकते हैं लेकिन पिछले दस वर्षों में यहां जो काम हुआ है वह वापस नहीं हो सकता.

जब साल 2005 में ओड़ीशा सरकार के साथ पोस्को ने इस परियोजना के लिए समझौता किया था तब यह (उस समय तक का) भारत में आया सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था. पोस्को ने स्टील प्लांट के साथ-साथ एक बंदरगाह और एक मल्टी-प्रोडक्ट एसइजेड की एकीकृत परियोजना के लिए 12 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा था. वर्ष 2007 में जहां उसे पर्यावरण की मंज़ूरी मिल गई थी, वहीं 2010 में वन विभाग ने भी परियोजना को हरी झंडी दिखा दी थी लेकिन भूमि अधिग्रहण मुश्किल काम साबित हुआ, क्योंकि स्थानीय लोगों (जिनके लिए चावल और पान के पत्तों की खेती जीविका का मुख्य साधन है) ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

इस दौरान 2014 में पर्यावरण की संशोधित मंज़ूरी को ओड़ीशा के पर्यावरण कार्यकर्त्ता प्रफुल्ल समंतारे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी. लेकिन इस परियोजना का बचाव करने के बजाए पोस्को ने ट्रिब्यूनल से इस मंज़ूरी को समाप्त करने की अपील कर दी. कंपनी ने भूमि अधिग्रहण में आने वाली दुश्वारियों का हवाला देते हुए कहा कि 19 जुलाई 2017 तक दी गई पर्यावरण मंजूरी की अवधि में पोस्को के लिए इस परियोजना को पूरा कर पाना असंभव है.

पर्यावरण मामलों के वकील ऋत्विक दत्त कहते हैं कि भारत में किस तरह वैधानिक और क़ानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करके विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है, पोस्को प्रकरण इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. इस परियोजना के लिए उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन (एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेस्मेंट) नहीं किया गया. बगैर इस बात की जांच किए कि 12 अरब डॉलर की इस परियोजना का पर्यावरण और सामाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उसे अपनी स्वीकृति भी दे दी. इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पोस्को ने बिना लौह अयस्क की उपलब्धता की गारंटी लिए स्टील प्लांट स्थापित करने और बंदरगाह निर्माण की परियोजना में हाथ डाल दिया. पोस्को का मामला एक और उदाहरण पेश करता है जिसमें कंपनियां सरकारों के सामने ऐसे हालात खड़े कर देती हैं जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता. ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह साबित हो गया कि पोस्को को मंजूरी देते वक्त सभी शर्तों का ध्यान नहीं रखा गया था और निर्णय प्रक्रिया भी पूर्वाग्रह से ग्रसित थी. दत्ता के मुताबिक कंपनी ने वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों के तहत औपचारिक अनुमति से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी. एक कंपनी के व्यापारिक हितों के लिए बिना किसी रोक-टोक के क़ानून तोड़ने दिए गए. सरकार आम लोगों (खास तौर पर हाशिए पर पड़े लोगों) के हितों की रक्षा करने के बजाए, कंपनी की एजेंट बन गई. और कंपनी हित को लोक हित बताकर उसके लिए काम करने लगी.

निवेश की इस दुर्गति में पोस्को, राज्य और केंद्र सरकार और राज्य की जनता सभी शामिल हैं. पोस्को के वापस जाने के फैसले के बाद क्या फिर सब कुछ वहीं वापस चला गया है जहां से इसकी शुरूआत हुई थी. शायद नहीं! क्योंकि इस परियोजना पर पूरी तरह से पर्दा गिरना अभी बाकी है. सरकार के फैसले वापस हो सकते हैं लेकिन पिछले दस वर्षों में यहां जो काम हुआ है वह वापस नहीं हो सकता.

पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार और स्थानीय लोगों के बीच घमासान लगातार जारी रहा. जहां एक तरफ सरकार दक्षिण कोरियाई कंपनी के लिए किसी भी कीमत पर भूमि अधिग्रहण के लिए दृढ़ थी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग अपनी जान देकर भी अपनी जीविका के पारंपरिक साधन को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे. प्लांट की साईट से लेकर कई अंतरराष्ट्रीय मंच इस लड़ाई का मैदान बने हुए थे. दरअसल सामाजिक बहिष्कार से लेकर धरना प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी तक सभी तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए.

अब जब यह जंग समाप्त हो गई है, तो ज़ाहिर है इसमें किसी की जीत हुई होगी और किसी की हार. धिनकि, नवगांव और गडकुजंग ग्राम पंचायतों ने मौजूदा घटनाक्रम पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रसन्नता के भी कई कारण गिनवाए हैं. मनोरमा खटुआ का कहना है कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. जो ज़मीन किसानों से जबरदस्ती छिनी गई है, हम उनकी वापसी की मांग करेंगे. आज कंचन मल्ला, कुनिलता, स्वेन और सबितल दीलुआ जैसी वृद्ध महिलाओं समेत सैकड़ों आंदोलनकारी अपने शरीर पर रबर की गोलियों के घाव लेकर बैठी हुई हैं. इन जैसे लोग आज भी कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास न तो हिम्मत है और न ही पैसा. ताकि वे अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा सकें. वहीं नारायण मंडल की त्रासदी कौन सुनेगा जिन्होंने 20 जून 2008 को पोस्को के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में अपने 33 वर्षीय बेटे तपन को खो दिया था या फिर तरुण जिनका छोटा बेटा 2 मार्च 2013 को मारा गया था, उनका दुखड़ा कौन सुनेगा. इसके अलावा उन 1200 पोस्को विरोधी आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज मुक़दमों का क्या होगा?

पोस्को के समर्थकों की परेशानियां और भी बड़ी हैं. उन्होंने अपना वर्तमान और भविष्य सब कुछ पोस्को के पास गिरवी रख दिया था. पटान गांव के उन 52 परिवारों का क्या होगा जिन्होंने पोस्को का समर्थन किया था और अपनी जड़ों और घरों से विस्थापित हो गए थे? वे एक अलग तरह के संघर्ष से जूझ रहे हैं. वे फिर से अपने पुश्तैनी गांव में बसना चाहते हैं. क्या इन परिवारों की जीवन फिर से सामान्य हो पाएगा? इन किसानों ने आगे आकर पोस्को समर्थक ग्रुप बनाया था. इन्होंने अपने लिए नौकरी के सपने पाल रखे थे ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकें. बहुतों को मुआवजे की जो रक़म मिली थी उसे उन्होंने घोटाला ग्रस्त चिट-फंड कंपनियों में गंवा दिया, पिछले कई वर्षों से उनके हाथ खाली हैं. प्रभाकर स्वेन स्थानीय लोगों की भावनाओं को बयान करते हुए कहते हैं कि इस खेल में केवल दलालों को फायदा पहुंचा है. स्थानीय लोगों ने अपनी जायदाद और जीविका के साधन खो दिए हैं. आपसी भाईचारा खो दिया है. जो लोग पोस्को का समर्थन कर रहे थे वे आज पोस्को का विरोध करने वाले लोगों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं. क्षेत्र में आम सोच यह है कि यदि लोगों की ज़मीनें उन्हें वापस दे दी जाती हैं और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुक़दमे वापस ले लिए जाते हैं तब भी सामान्य जीवन के पटरी पर आने में थोड़ा समय लगेगा. बहरहाल सरकार की तरफ से इस सिलसिले में कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई जा रही है.

यदि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बयान से कुछ नतीजा निकाला जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि इस परियोजना को लेकर सरकार में कोई उत्साह बाक़ी है. इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटनायक ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष ज़ाहिर करने के बाद पोस्को ने हमारे समक्ष हालिया बैठक कुछ भी नहीं कहा है. यदि राज्य सरकार अब इस सिलसिले में पोस्को से बात करने में पहल नहीं कर रही है तो वह परियोजना का विरोध करने वाले लोगों की फिक्र क्या करेगी?

राज्य सरकार ने भी इस परियोजना में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता दांव पर लगा रखी थी लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया. कोरियाई कंपनी के राज्य से बाहर जाने की वजह से निवेश के लिए एक ठोस स्थान के रूप में ओड़ीशा के नाम पर बट्टा लगा है. क्या ओड़ीशा इस बदनामी से उभर पाएगा? जिस तरह प्रशासन इस स्थिति से अनजान बनने की कोशिश कर रहा है उससे तो ऐसा नहीं लगता है.

पोस्को का मामला भारत में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी है. उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे भारत के क़ानून का अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ें. दूसरी बात यह कि कोई भी व्यवसाय स्थानीय लोगों को अलग-थलग करके सफल नहीं हो सकता. रेगुलेटरी (नियामक) शॉर्टकट्स किसी परियोजना के लिए केवल विलंब का कारण ही बन सकते हैं. भारत में औद्योगिकरण के लिए पर्यावरण की मंजूरी पेड़ों और वन जीवन की सुरक्षा से संबंधित होते हैं लेकिन यहां स्थानीय लोगों की जीविका, उनकी जीवनशैली और उनकी संस्कृति की भी सुरक्षा होनी चाहिए. जीविका और ज़मीन से संबंधित कोई भी फैसला स्थानीय लोगों की सहमती और उनकी सहभागिता से होना चाहिए. उनकी अनदेखी करना व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है, चाहे वह व्यवसाय निर्यात, राजस्व और रोज़गार के कितने ही अवसर पैदा करने का दावा क्यों न करता हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

पीलीभीत जेल में पीट–पीट कर मारे गए सात सिख युवकों के मां–बाप को कब मिलेगा न्याय?

सिख अपने ही देश में दोयम दर्जे का अल्पसंख्यक

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 11 सिख युवकों को बस से उतार कर मारे जाने के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को 25 साल बाद सजा तो सुना दी गई, लेकिन उन सात सिख युवकों के परिजनों को न्याय और कितनी देर से मिलेगा, जिन्हें पीलीभीत जेल में पीट–पीट कर मार डाला गया था! भारतवर्ष की लोकतांत्रिक प्रणाली पर अर्ध–सत्य की तरह चिपके अर्ध–न्याय को खुरचने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन न्याय मिलने में और कितने साल लगेंगे, इसके बारे में तो ईश्वर–अल्लाह–वाहेगुरु भी कुछ नहीं कह सकता. सिख अपने ही देश में दोयम दर्जे के अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ आजादी से लेकर आज तक भेदभाव बरता जा रहा है, लेकिन उनके लिए रोने वाला कोई नेता नहीं. सड़क से लेकर अदालतों तक सिखों का मसला उठाते हुए अपना पूरा जीवन बिता चुके सरदार अमीर सिंह विर्क जब यह कहते हैं तो देश की राजनीतिक–प्रशासनिक व्यवस्था का आपराधिक चरित्र और न्यायिक व्यवस्था की बेचारगी साफ–साफ झलकती है. सरदार अमीर सिंह विर्क गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने न केवल देश के सिखों के मानवाधिकार हनन के मामले राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय फोरम पर उठाए हैं, बल्कि पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह की रिहाई के मसले को भी देश–दुनिया में काफी परवान चढ़ाया. 1984 के दंगों के शिकार सिख परिवारों को मुआवजा दिलाने में सरदार अमीर सिंह विर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. विर्क अब पीलीभीत जेल में सात सिख युवकों को पीट–पीट कर मार डालने की घटना पर पीड़ित परिवारों को न्याय और उनकी आर्थिक मदद दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. 28 नवंबर 1994 को पीलीभीत जेल में बंद 28 सिख युवकों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया था, जिनमें से सात युवकों की मौत हो गई थी. लेकिन उस मामले के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पीलीभीत में सिख तीर्थयात्रियों के मारे जाने के मामले में न्याय मिलने के बाद अब जेल हत्याकांड को भी निर्णायक शक्ल पर पहुंचाने की तैयारी है. विर्क कहते हैं कि इस मामले की उस समय सीबीसीआईडी से जांच कराई गई थी और मामले की लीपापोती कर दी गई थी. अब सीबीआई द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए. जेल हत्याकांड मामले में पीड़ित सिख युवकों के परिजनों को अदालत का दरवाजा खटखटाने तक का मौका नहीं मिला. उस मामले के सारे आरोपी बिना किसी गवाही और दलील के बच गए थे. यहां तक कि उन्हें अपनी जमानत भी नहीं करानी पड़ी थी. मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने 48 जेलकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें तत्कालीन जेल अधीक्षक वीएस यादव का नाम भी शामिल था. मगर मामले की इतनी लीपापोती कर दी गई कि आगे कोई कार्रवाही नहीं हुई. इसके बाद सरकार ने 2007 में यह मुकदमा वापस भी ले लिया. सीबीसीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 12 बंदियों को चोटें आई थीं, लेकिन कोई गवाह न होने की वजह से यह जांच आगे नहीं बढ़ पाई.

सनद रहे, पीलीभीत जेल में बंद 28 सिख युवकों की आठ नवंबर 1994 को बुरी तरह पिटाई की गई थी. इसमें गंभीर रूप से जख्मी बंदी तरसेम सिंह उर्फ सेमा, गांव–बग्गादीना (राजासांसी) अमृतसर, लाभ सिंह उर्फ गुल्ली, गांव–मैनी गुल्दिया पीलीभीत, सुखदेव सिंह, गांव–हरेरिया शाहजहांपुर, सर्वजीत सिंह, गांव–जगत कुंद्रो पीलीभीत, जीत सिंह गांव–सद्दरपुर पीलीभीत और हरदयाल सिंह, गांव–फैजुल्लागंज शाहजहांपुर की उसी दिन मौत हो गई. एक अन्य घायल विचित्र सिंह, गांव चित्ता का भगवा (लोपोके) अमृतसर की लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. 21 बंदियों को गंभीर चोटें आई थीं.

इस मामले में पीलीभीत थाने में तहरीर दी गई थी. इस आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. घटना पर बवाल मचने के बाद पीलीभीत के जिलाधिकारी ने सीबीसीआईडी जांच की सिफारिश की थी. हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश पर सीबीसीआईडी की जांच हुई थी.

सिख तीर्थ यात्रियों की हत्या करने वाले पुलिसकर्मियों की तरह हत्यारे जेलकर्मियों को भी सजा मिले.
–सरदार अमीर सिंह विर्क

जांच के बाद सीबीसीआईडी ने पीलीभीत के जेल अधीक्षक विंध्याचल सिंह यादव, जेलर शहंशाह हुसैन जाफरी, राम किशोर त्रिपाठी, मुन्नालाल द्विवेदी, लियाकत अली, भारत सिंह चौधरी, राजेंद्र प्रसाद दीक्षित, हेमचंद सती, गिरजा शंकर, हरपाल सिंह, हरद्वारीलाल, छोटेलाल, जानकी प्रसाद गंगवार, रामेश्वर दयाल (1), यशवंत सिंह, मोहम्मद सुलेमान, मोहनलाल, राम स्वरूप, रामेश्वर दयाल (2), रामपाल, अनिल कुमार सिंह, रामपाल सिंह, परमानंद, रामबहादुर, हीरा सिंह, शांति स्वरूप, मेवाराम, कृष्णपाल सिंह, सुख लाल, लाल बहादुर, जगत नारायण, कल्लू सिंह, नोखे सिंह, भरत जी, गंगाराम, श्याम सिंह, मलखान सिंह, देवी सिंह, खेमपाल सिंह और अनोखे सिंह समेत 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उस समय पुलिस और जेलकर्मियों का इतना खौफ था कि पीड़ित परिवार पैरवी की हिम्मत नहीं जुटा सके. डर के कारण कोई व्यक्ति गवाही के लिए भी सामने नहीं आया. उस समय जो लोग जेल में बंद थे वे बताते हैं कि बिना किसी सबूत के सिख युवकों को जेल में डाल दिया जाता था. जिन युवकों की पीटकर हत्या की गई, उनको बैरक से निकालकर पुलिस वालों ने मिलकर वहशियों की तरह पीटा था. उस समय लग रहा था कि जेलकर्मी सारे सिखों को मार डालेंगे. मामला तूल पकड़ने पर सरकार ने टाडा के तहत जेल में बंद बहुत से सिखों को रिहा कर दिया था. सरकार ने पीड़ित परिवारों को एक–एक लाख रुपये दिए थे और न्याय का दरवाजा बंद कर दिया था.

सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि पीलीभीत जेल में सिख युवकों के इस तरह बर्बरतापूर्वक मारे जाने के मामले में प्रदेश और देश की सरकारें तो चुप्पी मारकर बैठ गईं, लेकिन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाया गया. इसका असर यह हुआ कि 29 नवंबर 1994 को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह मामला गूंजा और सिखों पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. अमेरिकी संसद के जरिए यह बात सामने आई कि जिन सिख युवकों को पीलीभीत जेल में पीटकर मारा गया, उन्हें जल्दी ही रिहा किया जाना था. हत्या के पीछे साजिशों के तार देखिए कि मारे गए सिखों में चार लोग उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी बस से 11 सिख युवकों को उतारकर मार डाला गया था. विर्क कहते हैं कि कानून के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर पहले से सजा पाए पुलिसकर्मियों पर और भी धाराओं के तहत सजा बढ़ सकती है और पीलीभीत जेल के कर्मचारियों पर बस हत्याकांड में साजिश करने का मामला भी चलाया जा सकता है.

उस घटना को भी याद करते चलें कि अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले सिख परिवारों के 11 नवयुवकों नरिंदर सिंह उर्फ निंदर, पिता दर्शन सिंह, पीलीभीत, लखविंदर सिंह उर्फ लाखा, पिता गुरमेज सिंह, पीलीभीत, बलजीत सिंह उर्फ पप्पू, पिता बसंत सिंह, गुरदासपुर, जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, पिता बसंत सिंह, गुरदासपुर, जसवंत सिंह उर्फ फौजी, पिता अजायब सिंह, बटाला, करतार सिंह, पिता अजायब सिंह, बटाला, मुखविंदर सिंह उर्फ मुखा, पिता संतोख सिंह, बटाला, हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटा, पिता अजायब सिंह, गुरदासपुर, सुरजन सिंह उर्फ बिट्टो, पिता करनैल सिंह, गुरदासपुर, रनधीर सिंह उर्फ धीरा, पिता सुंदर सिंह, गुरदासपुर और तलविंदर सिंह, पिता मलकैत सिंह, शाहजहांपुर (लाश भी नहीं मिली) को बस से उतार कर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस ने उनकी हत्या कर दी थी. 12 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस ने यह जघन्य कृत्य किया था. पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ कांड में दोषी ठहराए गए सभी 47 पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने अभी हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना के 25 साल बाद अदालत का फैसला आया. विशेष अदालत के जज लल्लू सिंह ने सभी हत्यारे पुलिसवालों पर उनके पद के हिसाब से जुर्माना भी लगाया और फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 11 सिखों के परिवार को 14–14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया. अब उनके खिलाफ पीलीभीत जेल हत्याकांड की साजिश करने का भी मामला चलाया जाना बाकी है. बस हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस के बड़े अफसरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे और और कहा था कि सीबीआई की जांच में व्यवस्थागत दिक्कतों की वजह से ये ट्रायल से बच गए लेकिन उन आला अफसरों पर दोबारा केस चलाने की सारी संभावनाएं हैं. यह सवाल अब भी सामने है कि सीबीआई ने उस फर्जी मुठभेड़ का निर्देश देने वाले आला अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया और उनके खिलाफ छानबीन क्यों नहीं की थी? सीबीआई ने उन बड़े अफसरों को क्यों बचाया? जिस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उससे स्पष्ट था कि सिखों को गोलियां मारने का निर्देश आला अधिकारियों से मिल रहा था. पुलिस के सामान्य अधिकारी या कर्मचारी बिना सीनियर अधिकारियों के निर्देश के इस तरह का हत्याकांड नहीं कर सकते. लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच से उन्हें दूर रखा. फर्जी मुठभेड़ मामले में तत्कालीन आइजी जोन, बरेली रेंज के डीआइजी व पुलिस अधीक्षक शामिल थे. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीलीभीत के तत्कालीन एसपी आरडी त्रिपाठी समेत तीन अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए थे. आखिर क्या कारण था कि सीबीआई ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं मांगी. विर्क कहते हैं कि इसकी जांच होनी ही चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुआवज़ा था या मज़ाक़!

32 साल हो गए. तीन दशकों से भी अधिक समय में देश में कई दंगे हुए. इन दंगों पर तमाम सियासी रुदालियां हुईं और मुआवजों की रेवड़ियां बांटी गईं. लेकिन 1984 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों की खोज खबर किसी ने नहीं ली. सिख संख्या में कम हैं. उनका वोट मुसलमानों की तरह गोलबंद नहीं होता. इसीलिए उनकी राजनीतिक औकात भी कम है. राहत और मुआवज़े की जद्दोजहद करते-करते पीढ़ियां बुढ़ा गईं और कई बुजुर्ग चले भी गए. लेकिन सिख परिवारों को मुआवज़े के नाम पर केवल धोखा बांटा जाता रहा. उत्तर प्रदेश में तो सिखों की और भी दुर्गत की गई. बसपा और सपा सरकारों ने सिखों से खूब खेला. कभी यह शासनादेश तो कभी वह शासनादेश. उत्तराखंड बनने के बाद तो वहां सिखों की और दुर्दशा कर दी गई. घर उनका उत्तराखंड में, लेकिन मुआवज़े की क़ानूनी लड़ाई चलती रही उत्तर प्रदेश में. यहां तक कि दंगे का शिकार हुए गुरुद्वारों की मरम्मत तक सरकारों ने नहीं होने दी. टूटे-फूटे गुरुद्वारों में ही सिख मत्था टेकते हैं और सियासतदानों को कोसते हैं. लखनऊ में अलीगंज स्थित चौधरी टोला संगत श्री गुरुग्रंथ साहब गुरुद्वारा इसका नायाब उदाहरण है. इस गुरुद्वारे को तीन नवंबर 1984 को तहस-नहस कर दिया गया था. हमलावरों ने गुरुग्रंथ साहब को भी जलाकर खाक कर दिया था. उस गुरुद्वारे की आज तक मरम्मत नहीं होने दी गई. स्थानीय असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं और पुलिस की मिलीभगत के कारण गुरुद्वारा आज तक उसी तरह खंडहर बना पड़ा है.

सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा पीड़ित सिख परिवारों के मुआवज़े का मामला वीभत्स स्थितियों में फंस कर रह गया. दंगों के शिकार सिखों को मुआवज़ा दिलाने के लिए दाखिल मूल याचिका के संवेदनशील पन्ने और सात-सात अन्य याचिकाएं अदालत से गायब करा दी गईं. और तो और, सिखों के मुआवज़े पर जिस भी बेंच ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, उस बेंच को ही रेन कैसले के वक्त बदल डाला गया. 1984 के दंगों के शिकार ज्यादातर सिखों को मुआवज़ा नहीं मिला, जिन्हें मिला वह भीख से भी बदतर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1984 के दंगों के मुआवज़े के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होती रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दंगों के शिकार सिखों की तरफ से मुआवज़े के लिए छह हज़ार 647 दावे दाखिल किए गए. इनमें रिट संख्या 1582-एमबी-97, 2513-एमबी-97 और 3647-एमबी-97 समेत सात याचिकाएं गायब कर दी गईं. जिस बेस रिट पर पूरा मामला टिका था, उस याचिका (संख्या: 3175-एमबी-96) से 47 महत्वपूर्ण पेज गायब कर दिए गए. मूल याचिका से 30 से 44 नंबर तक के पन्ने गायब हो गए. इसी तरह 52 से 55 नंबर, 163 से 175 नंबर, 191 से 205 नंबर और 250 से 251 नंबर पेज गायब कर दिए गए. इसकी अदालत से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दे रखा है कि 84 दंगों के भुक्त भोगियों को अद्यतन (करंट) दर से मुआवज़े दिए जाएं. लेकिन उत्तर प्रदेश में शासनादेशों के मुताबिक मुआवजे दिए जाने का फैसला किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवज़े का जिलेवार ब्यौरा देने को कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया. इसके बावजूद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि शासनादेशों के मुताबिक मुआवज़े दिए जाएं. इस फैसले के मुताबिक मिले मुआवज़े का हाल देखिए. कानपुर के मंजीत सिंह आनंद के परिवार का चार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने उनकी मां ज्ञान कौर को 27 हजार रुपये दिए. लखीमपुर खीरी जिले के निघासन स्थित कुन्नू घाट निवासी बलविंदर सिंह के परिवार के पांच सदस्यों को दंगा पीड़ित तो माना गया, लेकिन उन्हें 30 रुपये से 70 रुपये का मुआवजा देकर निबटा दिया गया. कानपुर के गांधी ग्राम स्थित फौजी सूबेदार दलजीत सिंह का घर दंगे में तबाह कर दिया गया था. उनके पिता को गोली मारी गई. वे विकलांग हो गए. लेकिन मुआवजे में उन्हें पांच हजार रुपये दिए गए. कानपुर में ही तिवारीपुर के रिटायर फौजी सरदार हरबंस सिंह और उनके भाई सरदार कुलवंत सिंह दंगे के दिन लापता हो गए. उनका कुछ पता नहीं चला और न उनकी लाशें बरामद हुईं. मुआवजे का मसला उठा तो कानूनगो ने रिपोर्ट में लिख दिया कि तिवारीपुर में कोई सिख रहता ही नहीं. पांच-पांच गांवों के लोगों और ग्राम प्रधानों ने शपथपत्र दाखिल करके कहा कि तिवारीपुर में सिख रहते हैं. यह भी लिखा कि दंगे के दिन से ही सरदार अमरजीत सिंह के पिता और भाई गायब हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और पीड़ित परिवार का दावा खारिज कर दिया. 1984 के दंगों के समय उत्तर प्रदेश में रहने वाले कई सिख राज्य का विभाजन होने के बाद उत्तराखंड के हो गए. लेकिन उनके मुआवज़े का मसला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अटका रहा. लेकिन उन्हें आज तक मुआवज़ा नहीं मिला. ■

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भू–अधिग्रहण पर लग सकता है ग्रहण

पुनर्मूल्यांकन की मांग पर डटे सैकड़ों भूधारी

न्यूनतम मूल्य निर्धारण में भारी अनियमितता, करोड़ों के सरकारी राजस्व का नुकसान

राकेश कुमार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2014 द्वारा बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति मिली. इसमें से गया स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हो गई है. वहीं दूसरी ओर मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस सत्र से शिक्षण कार्य आरंभ करने की कवायद तेज़ है. कुलपति डॉ अरविन्द अग्रवाल ने विश्वविद्यालय भवन के निर्माण तक वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करने को कहा है, जहां पठन–पाठन शुरू किया जा सके. जिला प्रशासन ने कई विकल्प सुझाए हैं. जिसमें मोतिहारी के डॉ. रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, एम एस कॉलेज सहित कई संस्थाओं के भवनों को चिन्हित किया जा रहा है. वहीं विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 301 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. लेकिन प्रशासनिक गलती के कारण भू–अधिग्रहण पर ही ग्रहण लगता नज़र आ रहा है. इसके कारण महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण पर ही प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है. भूमि के मूल्यांकन को लेकर सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित हैं. उन्होंने मांग की है कि भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाए, अन्यथा वे भूमि नहीं देंगे. जिलाधिकारी से लेकर केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष तक को इस संदर्भ में मांग पत्र दिया गया है. हालांकि, जिला प्रशासन अपनी गलती सुधारने के बजाए पल्ला झाड़ता नज़र आ रहा है.

आखिर कल तक स्वेच्छा से महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए भूमि देने की बात करने वाले सैकड़ों किसान क्यों आक्रोशित हैं और भूमि के पुनर्मूल्यांकन की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका कारण प्रशासनिक ब्लंडर है जो पूरी तरह प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पोल खोल रहा है. ज्ञात हो कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए चन्द्रहिया पंचायत के तीन गांव बनकट, राजस्व थाना सं.–194, बैरिया राजस्व थाना सं.–192, और फुर्सतपुर राजस्व थाना सं.–208 की भूमि का चुनाव स्थल चयन समिति ने किया है. जिला प्रशासन द्वारा इन तीनों गांवों की कुल 301.97 एकड़ भूमि को चिन्हित कर प्रस्ताव दिया गया था. केन्द्र सरकार की नई भू–अर्जन नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने नई नियमावली आने के नाम पर पूरा एक वर्ष गुजार दिया. इसके अनुसार भूमि–अधिग्रहण के पूर्व अधिग्रहित होने वाले क्षेत्र और भू–स्वामियों के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का सर्वेक्षण कराना था. पटना के प्रतिष्ठित संस्थान अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान को सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया. डॉ. विद्यार्थी विकास के नेतृत्व में आई टीम ने बड़ी सूक्ष्मता से एक–एक भू–स्वामी से बात की. जमीन की पूरी स्थिति का आकलन किया और भू–अर्जन के बाद पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक प्रभाव के साथ ही पर्यावरण और कालान्तर में होने वाले बदलाव का आकलन कर दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंपा. इसके पूर्व जन–सुनवाई के लिए सभा बुलाई गई. इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जन–सुनवाई में पता चला कि एक ही पंचायत के तीन गांवों की भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में भारी अनियमितता की गई है. सूत्रों के अनुसार भू–माफियाओं द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है उसके एवज में सरकार द्वारा भू–स्वामियों को बहुत कम पैसा दिया जाएगा. इसके बाद विगत दो–तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर ज़मीन की खरीद–बिक्री औने–पौने दाम पर की गई. सूत्रों की मानें तो भू–माफियाओं के इशारे पर ही न्यूनतम मूल्य निर्धारण के पुनःनिरीक्षण (एमवीआर) में फुर्सतपुर और बैरिया ग्राम को छोड़ दिया गया. अंचल और निबंधन विभाग की इस कारस्तानी से इस दौरान हुए ज़मीन की खरीद–बिक्री में सरकार को करोड़ों का चूना लगा और अब इसका खामियाजा दोनों गांवों के सैकड़ों काश्तकारों को भुगतना पड़ेगा. एमवीआर में की गई गड़बड़ी के कारण पंचायत चन्द्रहीया के बनकट ग्राम और फुर्सतपुर, बैरिया की भूमि के मूल्य में दस गुना का अंतर है. इतना ही नहीं बैरिया ग्राम एनएच–28 से जुड़ा हुआ है पर एमवीआर में इसे शून्य दर्शाया गया है जिसे ब्लंडर ही कहा जा सकता है. जिससे निबंधन में करोड़ों रुपये के राजस्व का सरकार को नुक़सान हुआ है. भू–माफियाओं की गोद में बैठे अंचल और जिला निबंधन विभाग ने एमवीआर में सरकारी आदेशों का खुलकर उल्लंघन किया है. बिहार स्टांप (लिखत का न्यूनतम मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली–2013 की कंडिका 2 (ड) में स्पष्ट प्रावधान है कि पेरिफेरल क्षेत्र से अभिप्रेत है, नगर परिषद की सीमा से 4 किमी. की परिधि वाले क्षेत्र की भूमि में यदि किसी ग्रामीण मौजा का अंश भी पेरिफेरल क्षेत्र में पड़ेगा, तो संपूर्ण मौजा को पेरिफेरल ही माना जाएगा. नियमावली के अनुसार ग्रामीण गैर कृषि, पेरिफेरल एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि/संपत्ति के प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित की जाएगी. केंद्रीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर यदि आवश्यक हो तो वर्ष में दो बार पुनरीक्षित की जा सकेगी. स्पष्ट नियमों के बावजूद भू–माफियाओं से प्रभावित अंचल और निबंधन विभाग ने कई वर्षों से बैरिया और फुर्सतपुर राजस्व ग्राम की भूमि का मूल्य पुनरीक्षण नहीं किया. इस कारण उक्त दोनों गांवों की भूमि का मूल्य बाजार मूल्य से कई गुना कम हो गया है जिसका सीधा प्रभाव अधिग्रहित होने वाली ज़मीन के मालिकों को भुगतना पड़ेगा. डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को अंकित किया है और कहा है कि बनकट और फुर्सतपुर, बैरिया की भूमि के मूल्य में बहुत अंतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा मोतिहारी की ज़मीन की कीमत संबंधी कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे जिनमें मोतिहारी प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की भूमि का न्यूनतम मूल्य (प्रति डिसमिल) दर्शाया गया है. जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि 1 फरवरी 2016 को गांव बनकट, थाना–194 की ज़मीन की कीमत में संशोधन किया गया है, जबकि गांव बैरिया, थाना–192 एवं गांव फुर्सतपुर, थाना– 208 की जमीनों के न्यूनतम बाजार मूल्य में संशोधन नहीं किया जा सका है. भूमि के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिल चुका है. उन्हें मांग पत्र भी दिया गया है. जिलाधिकारी अनुपम कुमार इस मुद्दे पर जांच करने की बात तो करते हैं पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं. वहीं अवर–निबंधन पदाधिकारी इस भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में हुई गड़बड़ी की बात मानते हैं पर इस मसले पर कोई कार्रवाई करने से इंकार करते हुए कहते हैं कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति के आदेश पर ही कोई कार्यवाही हो सकेगी. अब सभी इस प्रशासनिक अनियमितता से पल्ला झाड़ने की फिराक में दिख रहे हैं और भू–स्वामियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने मानवाधिकार उल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी आवेदन दिया है. वहीं केंद्रीय मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव के के पाठक एवं महानिरीक्षक निबंधन कुंवर जंग बहादुर को भी मांग पत्र दिया है. मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को भी ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाई और उन्हें आवेदन दिया. प्रमोद कुमार ने इसे भू–माफियाओं और पदाधिकारियों के गठबंधन का नतीजा बताया और कहा कि किसानों और भू–स्वामियों को न्याय दिलाया जाएगा. उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार से मिलकर उन्हें मामले की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पठन–पाठन का कार्य शुरू कराने का अनुरोध किया है. वहीं बिहार सरकार के निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के प्रधान सचिव के के पाठक से मिलकर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने उन्हें ज़मीन के मूल्यांकन के घोटाले की जानकारी दी और बताया कि इससे जहां एक ओर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. वहीं दूसरी ओर इसका विपरीत असर स्थानीय भू–स्वामियों को भुगतना पड़ेगा. कुमार के अनुसार केके पाठक ने इस मामले की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है. उधर भू–धारी विभूति नारायण सिंह, शिव कुमार यादव, इन्द्र यादव, अनिल पाण्डेय, रविन्द्र पाण्डेय, सीता राम पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भूमि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक वे अपनी ज़मीन नहीं देंगे. इसके लिए वे आन्दोलन करेंगे और न्यायालय की शरण में जाएंगे.

दूसरी तरफ चम्पारण विकास मोर्चा ने भी विश्वविद्यालय द्वारा पठन–पाठन शुरू करने में हो रहे विलम्ब को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है. मोर्चे के अध्यक्ष राय सुन्दरदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर राजनीति कर रही है. उन्होंने चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों को आरम्भ करने की मांग की और आन्दोलन का शंखनाद किया. इसी के साथ मोतिहारी के मुख्य गांधी चौक से गांधी संग्रहालय तक कैंडल मार्च का आयोजन किया. उन्होंने कहा कि उनके मोर्चे का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी देगा और इसमें तेज़ी लाने की मांग करेगा.

बहरहाल, भूमि के मूल्यांकन को लेकर उठे विरोध के कारण महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण पर ग्रहण लगता दिख रहा है. किसानों की मांग जायज़ है. वे वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पेरिफेरल एरिया के रूप में भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं. मूल्यांकन पुनःनिरीक्षण में इतना बड़ा घोटाला करने वालों को चिन्हित कर सजा देने की मांग भी उठने लगी है, जिसके कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है साथ ही भूमि–अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा मिलने की आशंका है इस वजह से प्रभावित भू–स्वामी विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं. इन वजहों से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में आने वाली अड़चनों और विलम्ब का जिम्मेदार कौन होगा?■

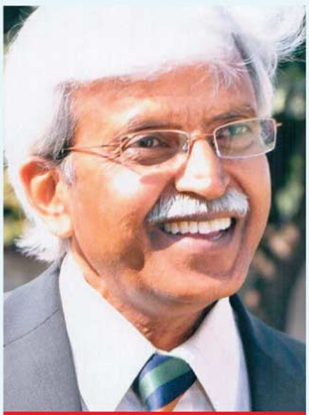
डॉ. अरविन्द अग्रवाल, वीसी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय

डॉ. विद्यार्थी सुमन, सहायक प्रोफेसर, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट

मूल्यांकन पुनःनिरीक्षण में इतना बड़ा घोटाला करने वालों को चिन्हित कर सजा देने की मांग भी उठने लगी है, जिसके कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है साथ ही भूमि–अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने की आशंका है, इस वजह से प्रभावित भू–स्वामी विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मध्यप्रदेश

हरियाली की लाश पर स्मार्ट सिटी

सौरिष शर्मा

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हरियाली की लाश पर स्मार्ट सिटी बसाने की योजना बनाई गई है. यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बेशुमार हरियाली, झीलों और सुंदर पहाड़ियों के लिए विख्यात है, परंतु इस शहर के जिस हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उस क्षेत्र में तकरीबन तीस हजार से अधिक पेड़ हैं. उनमें से अधिकांश वृक्ष विशालकाय और हरे-भरे हैं. यदि इन वृक्षों को काटा गया तो सरकार अगले बीस सालों में भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी. यही कारण है कि यहां स्मार्ट सिटी बसाने के विरोध में आम जनता के साथ-साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी सड़क पर उतर आए हैं. लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इन पेड़ों को काटकर स्मार्ट सिटी बनाई गई तो यहां चिपको आंदोलन चलेगा.

अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात भोपाल को स्मार्ट सिटी के नाम पर कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सौ स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी. उस योजना के अंतर्गत भोपाल को सम्मिलित तो कर लिया गया है, परंतु मध्यप्रदेश की राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इसकी हरियाली को नष्ट करने का कुचक्र शुरू हो गया है. और इसमें खुद सरकार तथा भोपाल का प्रशासन व नगर निगम शामिल हैं. इस सरकारी कवायद के विरोध में शहर की जनता अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है.

स्मार्ट सिटी की योजना

स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल शहर के पर्यावरण को संतुलित करने वाले शिवाजी नगर और तुलसी नगर में करीब तीस हजार पेड़ों को बचाने के लिए अब स्मार्ट सिटी कंपनी इन पेड़ों को बचानेस के लिए आम लोगों से सलाह लेगी. इसके लिए जगह-जगह चौपाल लगाकर सुझाव लिए जाएंगे. स्मार्ट सिटी की जानकारी देने के लिए निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी जा रही है. इसके लिए दो-तीन दिन के भीतर एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. कंपनी स्मार्ट सिटी के फायदों से शहर के लोगों को रू-ब-रू कराएगी. स्मार्ट सिटी में सेकेंड स्टॉप से 6 नंबर स्टॉप तक का लगभग 332 एकड़ क्षेत्र शामिल है. यहां लगभग 45 हजार लोग रहते हैं. स्मार्ट सिटी के लिए प्राइवेट मकानों, प्राइवेट कॉलोनी, शासकीय स्कूल, धार्मिक स्थल और हॉस्पिटल को नहीं हटाया जाएगा. पहले फेस में स्मार्ट सिटी के निर्माण पर 3,440 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है, जबकि स्मार्ट सिटी से प्रस्तावित आय 6,645 करोड़ रुपये सालाना है. इस निर्माण की वजह से क्षेत्र के करीब तीस हज़ार पेड़ों को

काटना पड़ेगा. इसमें छोटे-बड़े पेड़ शामिल हैं. पेड़ों को बचाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी शहर के लोगों से चौपाल लगाकर सुझाव मांगेगी. इसमें यहां रहने वाले लोगों की शिफ्टिंग के संबंध में भी बातचीत की जाएगी. कलेक्टर निशांत वरवड़े का कहना है कि दो-तीन दिन के भीतर इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

चिपको आंदोलन की चेतावनी

राजधानी के मयूर पार्क में एक बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच के अलावा एक दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हुए. उनके अलावा वरिष्ठ समाजसेवी, पत्रकार और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद थे. इस बैठक में सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि यदि सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर तीस हज़ार पेड़ों को काटने पर तुली रहेगी तो जनता को इसके विरोध में मैदान पर आना पड़ेगा. इसकी पहल इस बैठक में शामिल सभी लोग करेंगे और जिस तरह से हिमालय की तराई में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, उसी तर्ज पर यहां भी लोग पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने का विरोध करेंगे. इससे पहले केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, भोपाल नगर निगम व जिला प्रशासन को भोपाल के उन विकल्पों से भी अवगत कराया जाएगा, जहां पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा सकता है. जाने-माने आर्किटेक्ट अजय कटारिया ने तो दो वैकल्पिक क्षेत्रों का पूरा नक्शा ही तैयार कर लिया है. उनका कहना है कि शहर में जब वैकल्पिक स्थान हैं, तो फिर हरे-भरे क्षेत्र को बर्बाद क्यों किया जा रहा है. आज तक कोई भी सरकार उतने पेड़ नहीं लगा सकी है, जितने किसी भी निर्माण के समय काटे जाते हैं. जहां भोपाल में स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है, उससे भोपाल की लाइफ लाइन भी टूट रही है. ऐसे में शहर दो हिस्सों में बंटकर रह जाएगा, जो इस शहर के नागरिकों को कई दशकों तक सालता रहेगा.

प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच कहती हैं कि कुछ समय पहले घर में लगे एक पेड़ को कटवाने के लिए निगम में आवेदन दिया था. उस पर कार्रवाई करने से पहले निगम ने पेड़ काटने की फीस सहित दूसरी शर्तों की जानकारी दी थी. लेकिन, अब स्मार्ट सिटी के लिए निगम के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. निगम अफसरों ने पहले इस क्षेत्र में 30 हजार पेड़ होने की जानकारी दी थी. दूसरी बार यह संख्या 6 हजार बताई गई. आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर अवनीश सक्सेना ने कहा कि शहर में एमपी नगर और न्यू मार्केट गलत प्लानिंग का ही नतीजा हैं. इन दोनों क्षेत्रों के बीच का हिस्सा शिवाजी नगर और तुलसी नगर है. हरा-भरा होने के कारण यह हवा को स्वच्छ करने का काम करता है. इन दोनों जगह अब पेड़ नहीं बचे हैं. स्मार्ट सिटी में भी यही होगा.

4 हजार पेड़ काटे, 13,500 पौधे लगाए पर जीवित एक भी नहीं

पूर्व महापौर विभा पटेल ने बताया कि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए उनके कार्यकाल में पेड़ों को काटा और शिफ्ट किया गया था. इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में 13,500 पेड़ लगाए गए थे. लेकिन इनमें से एक भी जीवित नहीं है. जबकि जो पेड़ शिफ्ट हुए थे, वे भी जिंदा नहीं बचे. स्मार्ट सिटी के लिए चयनित स्थल का सर्वे एक महीने तक चलेगा. इसके लिए संस्थाओं ने एक फॉरमेट बनाया है. इसमें पेड़ों के तने की मोटाई, पेड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की चौड़ाई और घरों से पेड़ों की दूरी देखी जा रही है. सर्वे में यहां रुद्राक्ष, सिंदूर जैसे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ भी मिले हैं. कुछ ऐसी प्रजाति के पेड़ हैं, जिन्हें सहज पहचानना आसान नहीं है. इसके अलावा यहां नीम, जामुन, आम, अमरूद, पीपल, बरगद आदि के पेड़ भी हैं.

कोई समझौता नहीं ...

समाज सेवी राजेंद्र कोठारी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी की साइट सिलेक्शन में निगम कर्मचारियों और अफसरों ने बड़ी गड़बड़ी की है. सरकार से चर्चा करके स्मार्ट सिटी के निर्माण क्षेत्र को बदलने की कोशिश सिर्फ कोशिश बनकर रह जाएगी. क्षेत्र की हरियाली को बचाने के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन

राजधानी की हरियाली के साथ ही इसके स्वाभाविक स्वरूप को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञापन भेजा जा चुका है और लोग उनसे मिलने की तैयारी में जुट गए हैं. पहले भोपाल के स्थानीय प्रशासन को स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित स्थल से होने वाले नुकसान और इससे बेहतर वैकल्पिक स्थानों की जानकारी दी जा रही है. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्य सचिव एंटोनी डिसा को ज्ञापन दिए जाएंगे. यदि इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा. साथ ही वे राष्ट्रपति से भी मिलेंगे. कई संगठन स्मार्ट सिटी के स्थान को बदलने के लिए मैदान में आ गए हैं, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर स्मार्ट सिटी को लेकर होने वाले नफा-नुकसान की जानकारी देने की शुरुआत कर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सिंहस्थ
कुंभ महापर्व
उज्जैन
22 अप्रैल-21 मई, 2016

पवित्र, अद्भुत, अलौकिक
द्वितीय शाही स्नान आज

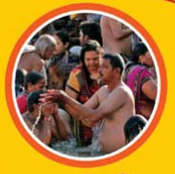

सभी संतजनों, श्रद्धालुओं का
आत्मीय स्वागत
एवं अभिनन्दन

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ

12-14 मई, 2016 ◆ निनोरा, उज्जैन, मध्यप्रदेश

महाकुंभ में विचार मंथन की ओजस्वी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए
अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है।
देश-दुनिया के कई मनीषी, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री व विद्वान
इसमें विश्व के सम्मुख उपस्थित ज्वलंत विषयों पर विचार मंथन करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 मई 2016 को विचार मंथन के निष्कर्षों को
विश्व के सम्मुख सिंहस्थ के सार्वभौम अमृत-संदेश के रूप में जारी करेंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रातः चार बजे से
दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

तृतीय एवं अंतिम शाही स्नान 21 मई 2016

क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला

सिंहस्थ मोबाइल एप्लीकेशन "Simhasth Ujjain 2016", मेला हेल्प लाइन नंबर - 1100 | www.simhasthujjain.in /SimhasthUjjain2016 /Simhasth

म.प्र. माध्यम/80905/2016

सौर ऊर्जा लाएं प्रदूषण भगाएं

श्याम कुमार

कई वर्ष हुए, मायावती का शासन खत्म हुआ था और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे. मायावती के अनेक परमप्रिय अधिकारी उस समय वनवास में हो गए थे तथा साधारण विभागों में भेज दिए गए थे. उन्हें बापू भवन के प्रथम तल पर कक्ष आवंटित हुए थे. मैंने इसका उल्लेख करते हुए उस समय बापू भवन की दुखिया मंजिल शीर्षक से आलेख भी लिखा था. उस समय बापू भवन की दुखिया मंजिल के एक कक्ष में गोपबंधु पटनायक बैठते थे तथा उनके पास वैकल्पिक ऊर्जा विभाग था. मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि हमारे देश में जब सौर ऊर्जा असीमित मात्रा में उपलब्ध है तो सरकार उस अपार शक्ति-भंडार के उपयोग को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है? उत्तर में उन्होंने कहा था कि सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत मंहगा पड़ता है. उन्होंने यह भी बताया था कि सौर ऊर्जा के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, ताकि लोग अपने बूते पर सौर ऊर्जा की ओर आकृष्ट हों.

पिछली आधी शताब्दी से अधिक हो गए, मेरा दृढ़ मत रहा है कि हमारे यहां इफरात मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, इसलिए शासन द्वारा उसके अधिकाधिक उपयोग के उपाय किए जाने चाहिए तथा अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए. सौर ऊर्जा हमारे देश में विकास की अद्भुत क्रांति ला सकती है तथा इसके बल पर भविष्य में हमारा देश अतिविकसित देश बन सकता है. मैंने गोपबंधु पटनायक से अनुरोध किया था कि वह किसी भी दशा में सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग का कार्यक्रम लागू करें. सरकार शुरुआत में ही यदि समस्त सरकारी भवनों, सरकारी कॉलोनियों, गांवों आदि में सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य कर देती तो इससे देश में बिजली का उपयोग बहुत कम किया जा सकता था. पिछले दिनों मेरी भेंट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चंद्रभानु गुप्त द्वारा स्थापित भारत सेवा संघ के अंतर्गत संचालित नवचेतना केंद्र के प्रभारी सदस्य डॉ. जागेश्वरनाथ मिश्र से हुई तो यह जानकर बड़ा अच्छा लगा कि वह भी सौर ऊर्जा के प्रबल समर्थक हैं. उन्होंने कहा कि यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे यहां सूर्यदेव की कृपा से इतनी अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है कि हम इसे अपने यहां वैकल्पिक ऊर्जा नहीं, बल्कि उसे मुख्य ऊर्जा-स्रोत बना सकते हैं.

डॉ. जागेश्वर नाथ मिश्र ने मत व्यक्त किया कि सौर ऊर्जा के उपयोग में लाभ ही लाभ है तथा इससे प्रदूषण से मुक्ति पाई जा सकती है. अभी हमारे यहां कोयले के उपयोग द्वारा ताप-संयत्रों से तथा जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली पैदा की जाती है. कोयले का भंडार सीमित समय तक ही चलेगा तथा जलविद्युत परियोजनाओं से नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हुआ है. लेकिन सौर ऊर्जा का हमारे पास ऐसा अनंत स्रोत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा. डॉ. मिश्र ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा में लागत बहुत अधिक बैठ रही है, लेकिन जब इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग व उत्पादन होने लगेगा तो धीरे-धीरे लागत कम होती जाएगी तथा एक समय ऐसा आएगा, जब सौर ऊर्जा बहुत सस्ती हो जाएगी. सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक सस्ता बनाने के लिए नए वैज्ञानिक उपाय भी ढूंढे जा सकते हैं.

डॉ. मिश्र अच्छे प्रशासक तो माने ही जाते हैं, उनकी विद्वता की भी प्रशंसा होती है. विभिन्न विषयों में उनका गहन अध्ययन है. जिस प्रकार वह सौर ऊर्जा के प्रबल समर्थक हैं, उसी प्रकार प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में भी वह लंबे समय से सक्रिय हैं. कई वर्ष पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रदूषण की समस्या पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें डॉ. मिश्र ने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था. उन्होंने अपने व्याख्यान में आगाह किया था कि प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है तथा यदि विश्व ने उस पर अभी से गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा उत्पन्न हो जाएगा. कई वर्ष पूर्व जिस ख़तरे की ओर आगाह किया गया था, वह ख़तरा अब सत्य सिद्ध हो रहा है. प्रदूषण के तरह-तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं तथा समस्या विकराल होती जा रही है. प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शीर्षस्थ नगरों में उत्तर प्रदेश के चार नगर हैं, जो हमारे लिए चिंतनीय है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के शहरों में लगातार हवा का स्तर गिर रहा है. सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद और संगम नगरी इलाहाबाद जैसे शहर शुमार हो गए हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कानपुर इस सूची में 15वें स्थान पर है जबकि फिरोजाबाद और लखनऊ 17वें और 18वें स्थान पर हैं. इलाहाबाद में प्रदूषण की स्थिति तो और भी खराब है. अनुसंधान एवं पक्षपोषण संगठन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण को देखें तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और इलाहाबाद में प्रदूषण का स्तर चौंकाने वाला है. इलाहाबाद और ग़ाजियाबाद में वायु प्रदूषण लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, खुर्जा व गजरौला से तीन गुना अधिक है. जबकि लखनऊ और कानपुर के बीच स्थित उन्नाव में हवा स्वास्थ्य के लिहाज से अपेक्षाकृत बेहतर है. दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के सर्वे के मुताबिक ग़ाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर व बरेली में प्रदूषण का स्तर 10 माइक्रॉन है. लखनऊ, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मथुरा, गजरौला व आगरा में वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित स्तर से करीब तीन गुना अधिक है. मेरठ, गोरखपुर, ग़ाजियाबाद और कानपुर में नाइट्रोजन डाइ-ऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ी है और वर्तमान में खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है. लखनऊ और इलाहाबाद के मध्य स्थित रायबरेली में इस गैस की वायुमंडल में मौजूदगी सबसे कम है. खुर्जा व ग़ाजियाबाद सल्फर डाइ-ऑक्साइड की दृष्टि से भी घातक स्तर पर पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रमुख इलाके मसलन आलमबाग, अमौसी, चौक, चारबाग वगैरह प्रदूषण की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित पाए गए हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव भी कुछ समय पहले इस समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश करते नज़र आ रहे थे लेकिन फिर सब कुछ ठंडा ही पड़ गया. मुख्यमंत्री की भी बातों का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीथिन भी बैन कर दी है, इसके बावजूद लोग बड़ी मात्रा में पॉलीथिन का इस्तेहमाल कर ही रहे हैं. ऐसे में यह असंभव है कि इसका कोई समाधान निकल पाएगा.

यदि यही स्थिति बनी रही तो लोग शुद्ध वायु को तरस जाएंगे. वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए अन्य उपायों का अनुसरण तो किया ही जाना चाहिए, किन्तु सबसे बड़ा उपाय अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है. पिछले दशकों में हमारे यहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है तथा वन-क्षेत्र घटता जा रहा है. इसी से मौसम भी असामान्य होने लगे हैं. हमें वृक्षारोपण के लिए युद्ध स्तर पर जुट जाना चाहिए तथा जहां-जहां भी संभव हो, चप्पा-चप्पा हरियाली से भर देना चाहिए. ■

(लेखक यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

गलत विज्ञापन पर सजा

संसदीय समिति ने निर्णय लिया है कि गलत विज्ञापन करने वाले और जनता के बीच भ्रामक प्रचार करने वाली मशहूर हस्तियों के खिलाफ 10 लाख का जुर्माना किया जाए. कोर्ट चाहे तो उन्हें दो साल की सजा भी दे सकती है. कड़वी सच्चाई यह है कि करोड़ों रुपये लेकर मशहूर हस्तियां जिस उत्पाद का विज्ञापन करती हैं, शायद ही उन्होंने उस उत्पाद का इस्तेमाल कभी किया हो. संसदीय समिति का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है. इसी तरह अश्लील विज्ञापन प्रकाशित करने वाले पत्र प्रकाशकों को भी जेल भेजा जाए.

–राज किशोर पाण्डेय(प्रहरी), *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

लोकतंत्र की हत्या

केंद्र की मोदी सरकार ने संघ-परिवार के सपने 'कांग्रेस-मुक्त भारत' को पूरा करने का संकल्प ले लिया है. केंद्र सरकार ने धन-बल और अपनी सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग करके पहले अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया. उसके बाद एक राजनीतिक नाटक रचकर उत्तराखंड में भी निर्वाचित सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार के गठन के लिए कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करने का षड्यंत्र रचा. सुप्रीम कोर्ट बोम्मई केस में स्पष्ट कर चुका है कि बहुमत का फैसला हमेशा सदन के पटल पर ही होना चाहिए. मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में बहुमत साबित का निर्देश राज्यपाल दे चुके थे. ऐसे में हरीश रावत को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता देख फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. ऐसी जल्दबाजी केंद्र की मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करती है. केंद्र सरकार में बैठे संघी मंत्री कांग्रेस-मुक्त भारत की अपनी नीति की वजह से प्रत्येक कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं. भाजपा खरीद फरोक्त करने में माहिर है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना केंद की तानाशाही, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सोच की जबरदस्त और बेशर्म उदाहरण है. यह बात उत्तराखंड को लेकर सुप्रीमकोर्ट के फैसले से भी साबित होती है. केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान की आत्मा की खुलेआम हत्या की है.

–आनंद गोयल, *29-स्टेट बैंक कालोनी, दिल्ली.*

यूपीए का एक और भ्रष्टाचार

कहते हैं कि सफर कोई भी हो और कितना भी लंबा क्यों न हो, यदि आपके दिल ओ-दिमाग में उसे पूरा करने की शिद्दत हो, तो सफर ज़रूर कट जाता है. शायद इसी लगन की वजह से आज़ादी के बाद से आज तक देश में चल रहे भ्रष्टाचार के सफर का अंत नहीं हुआ और न ही निकट भविष्य में खत्म होता दिख रहा है. मुझे यह भी नहीं पता कि इसका आदि और अंत कहां है? लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इन भ्रष्टाचारियों का अंत जरूर है. कवर स्टोरी- (9 मई-15 मई) ''भ्रष्टाचार की उड़ान में पनामा से इटली तक'' के सफर में बड़ी-बड़ी शख्सियतों के ग्राफ में भारी गिरावट दर्ज हुई है. बात चाहे अमिताभ बच्चन की हो या उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की. इससे यह बात एक बार फिर साबित होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं. यदि बात अगस्टा-वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले की हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सफर में अगस्टा-वेस्टलैंड के रुप में एक और मुकाम हासिल कर लिया है. साथ ही वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी का देश के प्रति ऐसा त्याग देखकर प्रत्येक भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है.

–शशिकांत भारतीय, *गोंडा, उत्तर प्रदेश*

पत्रकारिता का नया दौर

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. इसमें छपे सभी आलेख अन्य अखबारों व पत्रिकाओं से कुछ ज्यादा ही बेबाक होते हैं. चौथी दुनिया में पहले आदरणीय संतोष भारतीय जी का ''पत्रकारिता, नया दौर : नए प्रतिमान'' कॉलम छपता था जो आम लोगों के लिए कई तरह की अहम जानकारियों का स्रोत था. मगर पिछले कई माह से वह कॉलम नहीं छप रहा है. अत: हमारा निवेदन है कि उस कॉलम को फिर से अखबार में फिर से जगह दी जाए या ऐसा कोई आलेख छापा जाए जो आमजन के लिए हितकारी और ज्ञानवर्धक साबित हो सके. ऐसे आलेखों से नई पीढ़ी के लोगों को बीते समय की ज़मीनी हक़ीकतों से रूबरू होने का मौका मिलता है.

–नमन चौधरी, *भागलपुर ,बिहार*

किसानों की कोई नहीं सुनता

जब तोप मुक़ाबिल हो-सरकार सूखे को राष्ट्रीय समस्या घोषित कर निदान करे (09 मई-15 मई 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है कि किसानों की आत्महत्या की खबरें इतनी आम हो गई हैं कि उनकी चिंता न टेलीविजन को है न अखबारों को और न ही संसद को. किसानों की आत्महत्या की खबरें प्रतिदिन आती हैं, लेकिन उनकी चिंता करने वाला और उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है. किसान कर्ज़ के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन अपने पीछे विधवा पत्नी और बेटे-बेटियों को छोड़ जाता है. ऐसे में उस परिवार पर क्या बीतती है कोई उनसे ही जाकर पूंछे. इसलिए सरकार को किसानों के बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए और सूखा एवं बाढ़ क स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कोई दूरगामी योजना बनानी चाहिए. क्योंकि किसानों का हर साल किसी न किसी समस्या या प्राकृतिक आपदा से सामना होता है और वह फसल नष्ट होने की वजह से आत्महत्या कर लेता है. मैं किसानों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे हिम्मत हारकर आत्महत्या न करें और संगठित होकर सरकार पर उनके हित की नीतियां बनाने का दबाव डालें. जब तक किसान राजनीतिक तौर पर सशक्त होकर सरकारों से अपना हक़ नहीं मांगेंगे तब तक राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल करके उन्हें यूं ही अकेला छोड़ते रहेंगे.

–राकेश कुमार, *बेतिया, बिहार.*

पाठकों से...

सुथी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाओं का विश्लेषण कीजिए

प्रधानमंत्री जी से कैसे निवेदन किया जाए ताकि उन्हें यह समझ में आए कि वह 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. मैं अभी यह सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि यह सवाल अपने आप में इतना बड़ा है कि उन्हें शायद खुद सीख देगा कि वह जितनी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं. उन योजनाओं का प्रतिफल क्या निकल रहा है. बिना पूर्ण सोच के, बिना उसके लॉजिकल अनालिसिस के 50 से ज्यादा योजनाएं पिछले दो सालों में शुरू की गईं. उनका प्रतिफल क्या निकला है? यह जानकारी सरकार के सामने अगर सरकारी अधिकारी नहीं रख रहे हैं या प्रधानमंत्री के सामने उनके सचिव नहीं रख रहे हैं, तो फिर इसमें किसका दोष है? ज़मीन पर कहीं पर भी इन योजनाओं का परिणाम निकलता नहीं नज़र आ रहा है. शायद सरकार पांच साल के बाद विश्लेषण करेगी और देश के सामने रखेगी. अभी तो सरकार पूरे तौर पर टेलीविजन, रेडियो और अखबारों के माध्यम से यह समझाने में लगी है कि पिछले दो सालों जितनी नई योजनाएं लागू की गई हैं उससे हमारे देश में बदलाव आना शुरू हो गया है और हम अच्छे दिनों की तरफ छलांग लगाने वाले हैं. प्रचार से चुनाव तो जीता जा सकता है लेकिन प्रचार से लोगों की थाली में रोटी, हाथों को काम, नौजवानों का भविष्य नहीं संवारा जा सकता. यह बातें शायद न प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगेंगी और न मंत्रिमंडल के सदस्यों को. पर क्या करें सच्चाई यही है और यह सच्चाई जब विकराल रूप में सामने आएगी तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी.

आप अगला एक साल और चैन से गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद का वक्त आपके लिए शायद बहुत बेचैनी का वक्त होगा, क्योंकि तब आपके सामने इस देश का किसान होगा, इस देश का नौजवान होगा, इस देश का मजदूर होगा और वह सारे वंचित लोग होंगे जो आज आपकी आर्थिक नीतियों के दायरे में नहीं हैं. कृपया हम लोगों का यह प्रलाप सुनने की कोशिश कीजिए. बहुत सारे लोगों के कान बह रहे हैं, पर कम से कम आप तो अपने कानों को जनता की तकलीफों को सुनने के लिए बंद मत कीजिए.

इसीलिए हमारा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी योजनाओं का विश्लेषण समय-समय पर करते रहना चाहिए, अन्यथा भाजपा सांसदों को दी गई उनकी यह सलाह बेमानी हो जाएगी कि वे महीने के 14 दिन अपने चुनाव क्षेत्र में रहें और चार या पांच रातें गांवों में गुजारें. प्रधानमंत्री जी को पता नहीं यह मालूम है या नहीं मालूम है कि उन्हीं के सांसद उनकी इन योजनाओं की सफलता नहीं देख पा रहे हैं. वे गांव के लोगों को क्या बताएंगे, गांव के लोग तो उनसे सवाल पूछेंगे और वह सवाल सांसदों के लिए बहुत असहज करने वाले होंगे. क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों से यह पूछा कि उन्होंने जो गांव गोद लिए हैं उन गांवों में उन्होंने अब तक क्या काम किया है. सात लाख-आठ लाख लोगों की आबादी वाले चुनाव क्षेत्र में एक हजार लोगों की आबादी वाला एक गांव और उस गांव में भी सांसद की सीधी देखरेख में सरकारी योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ और सांसद ने अपनी सांसद निधि से जो पैसा लगाया उसका क्या प्रतिफल निकला. दो साल बाद यह सवाल प्रधानमंत्री को सांसदों से पूछना ही चाहिए और प्रधानमंत्री जी को स्वयं के द्वारा सांसद होने के नाते गोद लिए गांव की भी सुध लेनी चाहिए. अब प्रधानमंत्री के प्रति किस तरह का अविश्वास उनके द्वारा गोद लिए गांव वालों ने दिखाया कि उन्हें गांव में हुए चुनाव में हरवा दिया. इसका भी कुछ आकलन प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए. बनारस के लोग जहां से यह सांसद हैं बहुत विश्वास से भरे हुए थे, लेकिन आज वह विश्वास तार-तार हो गया है.

प्रधानमंत्री जी से अगर यह कहा जाए कि योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं की घोषणा और योजनाओं का अपने ही अन्तर्विरोधों के जाल में उलझकर उद्देश्य से भटक जाना, आपकी चिंता का विषय होना ही चाहिए, पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय आपके राजनीतिक फैसलों का होना चाहिए. आपकी पार्टी ने पिछले दो सालों में जितने राजनीतिक फैसले लिए, उन राजनीतिक फैसलों ने भविष्य में आपके सामने बहुत सी चुनौतियों के बीज बो दिए हैं. सबसे पहले बिहार चुनाव, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को चुनो या मुझे चुनो. मुझे चुनो का मतलब मेरी पार्टी को चुनोगे तो बिहार में विकास होगा और नीतीश कुमार को अगर बिहार के लोग चुनेंगे तो वहां जंगलराज होगा. इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों से कही और लगभग हर जिले में जाकर उन्होंने मीटिंग की. उन्होंने पूरे चुनाव में बिहार में मीटिंग की, इसके बावजूद लोगों ने उन्हें नकार दिया. क्या इसके बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा कि उनसे या उनकी पार्टी से कहां बड़ी राजनीतिक भूल हुई कि लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया. अरुणाचल में जिस तरह का फैसला प्रधानमंत्री की पार्टी ने किया, उससे सारे देश में उनकी राजनीतिक साख के ऊपर सवाल खड़े हुए और अब उत्तराखंड, जहां पर उनकी पार्टी की वजह से, उन्हीं की पार्टी की देश में भयानक किरकिरी हुई है. कहां नहीं हारे आप! ऐसे लोगों के हाथ में आपने फैसले लेने की ताकत दे दी जो राजनीतिक तौर पर बहुत बौने हैं. प्रधानमंत्री जी, यह जो राजनीतिक साख खत्म होती है, यह बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है. इसीलिए आपकी पार्टी जब राम मंदिर बनाने की बात करती है, आपकी पार्टी जब ऐसे लोगों को संसद में नामित करती है जो कांग्रेस का रोल स्वयं निभाने लगते हैं, तो यह मानिए कि अच्छा नहीं हो रहा है.

चुनाव के दौरान कांग्रेस से निराश लोगों ने आपको इसलिए इतना वोट दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े करिश्मे की आशा नहीं थी, लेकिन उन्हें सिस्टम को सही ढंग से चलाने की क्षमता पैदा करने वाले व्यक्ति की तलाश थी, और जितनी योजनाएं हैं, अगर वही योजनाएं ठीक ढंग से चलने लगें तो भी इस देश में लोगों को राहत मिल सकती है. गांव में लोग क्या चाहते हैं? बिजली चाहते हैं और सड़क चाहते हैं. प्रधानमंत्री जी, आपने जब सबको बिजली देने की घोषणा की थी और सोलर पावर की बात कही थी, तब लगा था कि आपने विकास की शुरुआत का पहला कदम तलाश लिया है. पर दो साल बीत गए, इस देश के गांव में बिजली वही आठ घंटे और दस घंटे आ रही है. फर्क नहीं है और चूंकि बिजली नहीं है इसलिए विकास के सारे काम ठप्प हैं. आपके बिजली मंत्री या आपका ऊर्जा उत्पादन मंत्रालय आंकड़े ही नहीं दे पा रहा है कि उसने दो साल में कितनी प्रगति की. प्रचार में जो हो रहा हो, पर किसी भी गांव में आप चले जाएं वहां पर बिजली नहीं आती. पीने का पानी, सूखा इनसे लड़ने का कोई मनोबल लोगों में तो कम से कम दिखाई नहीं देता. मेरा यह निश्चित तौर पर मानना है कि आप लोगों को पानी, बिजली और सड़क दे दीजिए, बाकी काम लोग अपने आप कर लेंगे. और फिर प्रधानमंत्री का काम देश की राज्य सरकारों को, चाहे वह उनके प्रदेश की सरकार हो, उनकी पार्टी की सरकारें हों या दूसरी पार्टी की सरकारें हों, प्रेरित करना होता है. प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता.

इसलिए नरेंद्र मोदी जी से इतना ही आग्रह है कि आज भी अगर आप नहीं चेतेंगे और यह मानेंगे कि हमारे जैसे लोग पागल प्रलाप कर रहे हैं, तो आप अगला एक साल और चैन से गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद का वक्त आपके लिए शायद बहुत बेचैनी का वक्त होगा, क्योंकि तब आपके सामने इस देश का किसान होगा, इस देश का नौजवान होगा, इस देश का मजदूर होगा और वह सारे वंचित लोग होंगे जो आज आपकी आर्थिक नीतियों के दायरे में नहीं हैं. कृपया हम लोगों का यह प्रलाप सुनने की कोशिश कीजिए. बहुत सारे लोगों के कान बह रहे हैं, पर कम से कम आप तो अपने कानों को जनता की तकलीफों को सुनने के लिए बंद मत कीजिए. ■

editor@chauthiduniya.com

पुराना आतंकवाद, नया आतंकवाद

मेघनाद देसाई

मदन लाल ढींगरा लंदन में श्यामजी कृष्णा द्वारा संचालित इंडिया हाउस में रुके थे. सावरकर भी यहीं ठहरे थे. ढींगरा ने वायसरॉय के एसीडी रह चुके कर्ज़न वाईली की हत्या कर दी. लंदन में रह रहे विशिष्ट भारतीयों की एक बड़ी सभा में ढींगरा की भर्त्सना करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया. यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया होता यदि सावरकर ने आगे आकर हस्तक्षेप न किया होता और ढींगरा के क्रांतिकारी आतंकवाद का बचाव न किया होता. मोहनदास करमचंद गांधी (जो उस समय तक महात्मा नहीं बने थे) ने ढींगरा द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की थी.

कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कुछ इसी तरह का रुख भगत सिंह के संबंध में अपनाया था. उन्होंने भगत सिंह को सुनाई गई फांसी की सज़ा को उम्र क़ैद में बदलने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन से बात करने से इंकार कर दिया था. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नौजवानों द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाई का गांधी और कांग्रेस दोनों ने हमेशा विरोध किया. हिंसा का विरोध गांधी के लिए सिद्धांत का मामला था, जबकि उनके समर्थकों के लिए यह केवल कार्यनीति थी. स्वतंत्रता के लिए हो रहे संघर्ष में अहिंसा की राह अपनाकर सफलता की उम्मीद की जा रही थी, और ऐसा हुआ भी. जिसका नतीजा यह हुआ कि हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करने वाले लोगों की अहमियत कम हो गई. लिहाज़ा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगत सिंह जैसे लोग हाशिए पर चले गए.

भले ही आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं किया हो, लेकिन आतंकवाद सबके लिए नकारात्मक शब्द नहीं था. ब्रिटेन में लोगों को आयरिश स्वतंत्रता सेनानियों सिन फैन और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (आईआरए) के आतंकवाद का सामना करना पड़ा था. अक्सर इन गिरोहों की आर्थिक सहायता आयरिश अमेरिकन लोगों द्वारा की जाती थी. आयरिश अमेरिकन ब्रिटेन के लोगों से नफरत करते थे. खालिस्तान आंदोलन के समय भारत राष्ट्रवादी आतंकवाद का शिकार बना और फिर तमिल एलम आंदोलन के समय अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का शिकार हुआ, जिसमें राजीव गांधी की जान गई. ये बातें 1990 के शुरुआती दौर तक की हैं.

आतंकवाद को नकारात्मक मायनों में (1990 के दशक के अंत में) उस समय से देखा जाने लगा जब कीनिया में अपने दूतावास और यूएसएस कोल पर हुए हमले के रूप में अमेरिका ने पहली बार इसका अनुभव किया. और जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो आतंकवाद अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या बन गया. नतीजतन यह दुनिया के लिए भी सबसे बड़ी समस्या बन गया. अमेरिका उस समय भी एक मात्र सुपर पॉवर या जैसा कि फ्रांसीसी कहते हैं हाइपर पॉवर था. लिहाज़ा 21वीं सदी की शुरुआत से ही किसी गैर-सरकारी गिरोह द्वारा किसी भी हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधियों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा.

अलक़ायदा ने आतंकवादी कार्रवाई और आतंकवाद की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया. आतंकवाद कोई राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने की निजी (गैर-सरकारी) कार्रवाई होती है. अनुशीलन ग्रुप या भगत सिंह की लड़ाई उन अधिकारियों के विरुद्ध थी जो साम्राज्यवादी ताक़तों का

प्रतिनिधित्व करते थे. शुरुआत में आयरलैंड की क्रांतिकारी परंपरा का भी यही तरीका था. दरअसल, उत्तरी आयरलैंड में 20वीं सदी के आखिर में आतंकवादी गतिविधियां सांप्रदायिक हो गईं और आम लोगों को भी इसमें निशाना बनाया जाने लगा. एक बार जब अमेरिका आतंकवाद के ख़िलाफ हो गया, तो उसने उत्तरी आयरलैंड को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद वहां शांति स्थापित करना आसान हो गया.

आधुनिक आतंकवाद, खास तौर पर ज़िहादी आतंकवाद नागरिक ठिकानों को निशाना बनाता है. जिसका मकसद होता है सत्ता में बैठे लोगों को यह संदेश देना कि वैचारिक और राजनीतिक जंग जारी है. ज़िहादी संघर्ष की न तो कोई सरहद होती है और न ही कोई अंतिम लक्ष्य, सिवाय इसके कि सबको वहाबी मुसलमान बना दिया जाए. लिहाज़ा यह दूसरे राष्ट्रों के साथ-साथ मुस्लिम देशों को भी अपना निशाना बनाते हैं. ये न तो बातचीत करना चाहते हैं और न ही इनका कोई अंतरिम लक्ष्य है. तकनीकी विकास ने आतंकवादियों को शहरी गोरिल्ला के तौर पर एक ही प्रयास में कई लोगों को मारने की क्षमता दे दी है. दरअसल भगत सिंह का क्रान्तिकारी आतंकवाद एक अलग दुनिया की चीज़ थी. ■

आधुनिक आतंकवाद, ख़ास तौर पर ज़िहादी आतंकवाद नागरिक ठिकानों को निशाना बनाता है. जिसका मकसद होता है सत्ता में बैठे लोगों को यह संदेश देना कि वैचारिक और राजनीतिक जंग जारी है. ज़िहादी संघर्ष की न तो कोई सरहद होती है और न ही कोई अंतिम लक्ष्य, सिवाय इसके कि सबको वहाबी मुसलमान बना दिया जाए. लिहाज़ा यह दूसरे राष्ट्रों के साथ-साथ मुस्लिम देशों को भी अपना निशाना बनाते हैं. ये न तो बातचीत करना चाहते हैं और न ही इनका कोई अंतरिम लक्ष्य है. तकनीकी विकास ने आतंकवादियों को शहरी गोरिल्ला के तौर पर एक ही प्रयास में कई लोगों को मारने की क्षमता दे दी है. दरअसल भगत सिंह का क्रान्तिकारी आतंकवाद एक अलग दुनिया की चीज़ थी.

feedback@chauthiduniya.com

सत्ता की हनक में बेलगाम जनप्रतिनिधि

आदित्य सचदेवा (मृतक)

बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नए गठबंधन की सरकार बनी. लेकिन इस गठबंधन की सरकार बने अभी छह महीने भी नहीं हुए कि सत्ता से जुड़े विधायकों की हरकतों से पूरा प्रदेश परेशान हो गया है. एक मामला ठंडा नहीं होता है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है. जदयू विधायक सरफराज आलम ट्रेन में बिना टिकट सफर करते और शराब के नशे में महिला से छेड़खानी करते पकड़े जाते हैं, तो वहीं नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पकड़े जाते हैं.

सरोज सिंह

बिहार में सत्ता की हनक में जनप्रतिनिधि और उनके रिश्तेदार बेलगाम हो गए हैं. जनप्रतिनिधि जनता के वोट से जीतकर विधानसभा और विधान परिषद तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पावर और पैसा आने के बाद जब सत्ता से जुड़ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वह जनता के प्रतिनिधि हैं जनता की सेवा मेरा धर्म है. सत्ता के नशे में चूर यह जनप्रतिनिधि जनता के सेवक बनना तो दूर अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगते हैं. यही कारण है कि ऐसे जनप्रतिनिधि कानून को भी ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आते हैं. वहीं दूसरी ओर सत्ता से जुड़े होने के सवाल पर कोई मामला सामने आता है तो पुलिस-प्रशासन के वरीय अधिकारी भी ऐसे जनप्रतिनिधियों पर हाथ डालने से कतराते हैं. लेकिन जब जनसमूह का आक्रोश और उबाल बढ़ने लगता है तो पुलिस-प्रशासन भी ऐसे मामले में कार्रवाई करने को बाध्य होता है. यह अलग बात है कि सत्ता से जुड़े जनप्रतिनिधयों को कभी-कभी राज्य के मुखिया के इशारे पर थोड़ी बहुत राहत भी मिल जाती है. लेकिन जब जन आक्रोश सत्ता को परेशान करने लगता है, तब सत्ता से जुड़े लोग अपने लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का सर्वाजनिक बयान देने पर बाध्य होते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नए गठबंधन की सरकार बनी. लेकिन अभी छह महीने भी नहीं हुए कि सत्ता से जुड़े विधायकों की हरकतों से पूरा प्रदेश परेशान हो गया है. एक मामला ठंडा नहीं होता है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है. जदयू विधायक सरफराज आलम ट्रेन में बिना टिकट सफर करते और शराब के नशे में महिला से छेड़खानी करते पकड़े जाते हैं, तो वहीं नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पकड़े जाते हैं. पटना जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ लड़की भगाकर अपने ड्राइवर से जबरन शादी कराने के मामले में चर्चा में आते हैं. वहीं पूर्णिया की जदयू विधायक वीमा भारती अपने आरोपी पति को थाने से भगाने के मामले में चर्चा में आती हैं. इस मामले में पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा का भी नाम आया था. हाल ही के दिनों में जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक डीएसपी को गंगा नदी में फेंक देने तथा सार्वजनिक रूप से नर्तकियों के साथ डांस करने और शराब पर बयानबाजी करने के मामले में चर्चा में आए थे. गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक कुंती देवी के पुत्र रंजीत यादव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बथानी के चिकित्सक की पिटाई करने के मामले में जेल में बंद हैं.

पूरे प्रदेश में अभी इन घटनाओं की चर्चा चली रही थी कि 7 मई 2016 को गया में विधान पार्षद मनोरमा देवी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद ऊर्फ बिंदी यादव के पुत्र रॉकी यादव ने एक व्यवसायी पुत्र की इसलिए गोली मार कर हत्या कर दी, क्योंकि उसने रॉकी यादव के लैंड रोवर को साइड नहीं दी. लेकिन इन सभी मामलों की जड़ में एक ही बात महत्वपूर्ण है कि पैसा और पावर के साथ सत्ता के साथ जुड़े प्रतिनिधियों और उनके परिजनों को यह अहसास होता है कि वह समाज में सबसे ऊपर हो गए हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लेकिन गया की घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है. इस मामले में यदि बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवसायी पुत्र के हत्यारे को त्वरित सुनवाई के माध्यम से सजा नहीं दिलाती है तो एक बार पुनः राज्य से व्यवसायियों का पलायन शुरू हो जाएगा. गया के पाइप व्यवसायी श्यामसुंदर सचदेवा का पुत्र आदित्य सचदेवा अपने पांच साथियों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था. उसके पीछे एमएलसी मनोरमा देवी के अंगरक्षक के साथ रॉकी अपनी 1.30 करोड़ की लैंड रोवर से आ रहा था. कार को साईड नहीं दिए जाने से गुस्साए एमएलसी के पुत्र राकेश रंजन यादव ऊर्फ रॉकी ने गया सेंट्रल जेल के पीछे वाली सड़क पर आदित्य की कार को ओवरटेक कर रुकवाई और अपने पिस्टल से हवा में फायरिंग की. आदित्य व उसके दोस्तों से मारपीट भी की. पांचों युवकों ने माफी भी मांगी और डरकर गाड़ी से भागने लगे. इसी दौरान रॉकी ने पीछे से गोली चला दी जो कार के शीशे को पार करते हुए आदित्य को जा लगी. उसके बाद आदित्य को लेकर उसके साथी मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां चिकित्सकों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस-प्रशासन को लगी उनके हाथ-पांव फूलने लगे. लेकिन मामला जैसे ही पता लगा कि व्यवसायी से जुड़ा है और बवाल बहुत अधिक हो सकता है, तब पुलिस ने देर रात गया के एपी कॉलेनी स्थित एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी की. जहां से हत्या में उपयोग की गई लैंड रोवर और अंग रक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन घटना के बाद गया पुलिस का जो रवैया रहा उससे आम लोगों में यही चर्चा थी कि हत्यारे और रॉकी को भगाने में पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है. सुबह होते ही यह मामला पूरे शहर में गरम हो गया और लोगों का आक्रोश सड़क पर आ गया, तब पुलिस ने विधान पार्षद मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को साक्ष्य मिटाने तथा अपने बेटे का गलत बचाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़ी घटना की प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस को लगभग 20 से 26 घंटे लगे. सत्ता से जुड़े लोगों के आरोपी बनने पर पुलिस यह चाह रही थी कि उनके मुताबिक प्राथमिकी दर्ज हो. इसके लिए मृतक आदित्य के परिजन तैयार नहीं थे. यहीं पर इस मामले में गया पुलिस भी संदेह की घेरे में आ गई. जबकि आदित्य के परिजन और चश्मदीद गवाह जो घटना हुई उसी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते थे और बाद में वही हुआ. गया के एसएसपी गरिमा मलिक बताती हैं कि यदि एमएलसी मनोरमा देवी के खिलाफ भी सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. एनडीए ने आदित्य हत्याकांड के विरोध में 9 मई 2016 को गया बंद का आह्वान किया था. घटना के तुरंत बाद सत्ता से जुड़े कुछ नेताओं का बयान आया कि इस कांड के दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन मुख्यमंत्री समेत अन्य वरिष्ठ सत्ताधारी नेताओं का बयान मृतक के परिजनों की सहानुभूति के लिए नहीं आने से लोगों को अंदेशा है कि बिंदी यादव और उसका पुत्र कहीं सत्ता का लाभ लेकर इस हत्याकांड से मुक्त न हो जाएं. गया की घटना को लेकर पटना में भी राजनीतिक पारा गरम है. कोई सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोस रहा है. जनता दरबार में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे. राकी यादव पकड़ भी लिया गया है, पर सवाल यही है कि आखिर आदित्य को किस गुनाह की सजा मिली और उसे दुनिया छोड़ कर जाना पड़ा. सत्ता का अहंकार ऐसा है कि छोटी सी बात पर एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वाली सोच ही इस तरह की परिस्थति पैदा करती है. और जिसे जाना होता हैं वह चला जाता है और फिर सड़को पर राजनीति शुरू हो जाती है. आदित्य के परिवार का दर्द इस राजनीति से कम नहीं होगा. अगर यह सरकार हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिला देती है, तो कम से कम पीड़ित परिवार को इतना तो संतोष जरूर होगा कि अब दोबारा कोई किसी की निर्मम हत्या करने के पहले सौ बार सोचेगा. हो सकता है कि इस सोच की वजह से किसी और आदित्य की जान बच जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

रॉकी यादव (आरोपी)

अपराध और बिंदी यादव का पुराना रिश्ता है

बिंदेश्वरी प्रसाद यादव ऊर्फ बिंदी यादव ऐसे तो पिछले ढाई दशक से विभिन्न आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रहा है. उसके ठेकेदार बनने के पीछे जीटी रोड पर प्रवेश का धंधा करने से लेकर आपराधिक मामले भी मुख्य रहे हैं. पिछले ढाई दशक में अकूत संपत्ति बनाने वाले बिंदी यादव की संपत्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बेटा राकेश रंजन यादव ऊर्फ रॉकी यादव 1.30 करोड़ की कीमत वाली लैंड रोवर से चलने और लगभग आठ लाख रुपये की कीमत वाला लाइंसेसी रिवाल्वर रखने का शौकीन है. उसके पास इतनी कीमती गाड़ी और रिवाल्वर कहां से आया यह भी जांच का विषय है. हाल ही में बिंदी यादव को जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए सरकारी अंगरक्षक का मामला भी सुर्खियों छाया हुआ था. बिंदी यादव पर पहले से ही दर्जनों केस थे. लेकिन वह गया शहर के सोना-चांदी के कारोबारी बबली जैन अपहरण कांड से चर्चा में आया. उसके बाद नक्सलियों को बड़े पैमाने पर कारतूस उपलब्ध कराने के मामले में बिंदी यादव पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला. लेकिन संयोग ऐसा रहा कि इन दोनों मामलों में बिंदी यादव बाहर निकलने में सफल रहा. उसके राजनीतिक आकाओं का उसे संरक्षण न मिले, तो अब उसके पुत्र रॉकी यादव द्वारा व्यवसायी पुत्र आदित्य की हत्या किए जाने के मामले में उसका बच पाना मुश्किल है. इन सबके अलावा बिंदी यादव पर अलग-अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं. जिनमें साक्ची थाना, जमशेदपुर अपराध संख्या 158/ 1995, धारा 387, साक्ची थाना जमशेदपुर अपराध संख्या 150/ 1995, धारा 387, रामपुर थाना अपराध संख्या 162/ 1995, धारा 160, 341, 323, 307, 504, मुफ्फसिल थाना अपराध संख्या 12/ 2004, धारा 379, सिविल लाइंस अपराध संख्या 132/ 2002 धारा 144, 353, 341, 504, 186, 189, सिविल लाइंस अपराध संख्या 281/2003, धारा 307, 379, 385, 504, 354, बोधगया थाना अपराध संख्या 17/2005, धारा 133 पीआर एक्ट, बाराचट्टी थाना अपराध संख्या 95/2005, धारा 406, 420 बाराचट्टी थाना अपराध संख्या 68/2001 धारा 25 (1) (बी) (ए) 26, बाराचट्टी थाना अपराध संख्या 133/2007, धारा 147, 148, 337, 353, 384, 386, 420, 120(बी), मदनपुर थाना अपराध संख्या 38/2005 धारा, 384, 420, बोधगया थाना अपराध संख्या 83/2010, धारा 414, 34, 33, कोंच थाना अपराध संख्या 29/2009, धारा 29(बी) 30 आर्म्स एक्ट, फतेहपुर थाना अपराध संख्या 79/2006, धारा 25(1-बी), 26, 35 आर्म्स एक्ट, वजीरगंज थाना अपराध संख्या 79/2006, धारा 147, 148, 143, 188, 171, 426, 427, बाराचट्टी थाना कांड संख्या 199/2006, धारा 341, 323, 379, 34. इसी प्रकार कई और थानों में बिंदी यादव के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके अलावा बिंदी यादव की पत्नी और विधान पार्षद मनोरमा देवी पर भी गया के थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं. चनौती थाना अपराध संख्या 160/ 2005, धारा 144, 171 (सी) 188, 123, (3), 131. चनौती थाना अपराध संख्या 161/ 2005, धारा 224, 225/34, मामले दर्ज हैं. ■

- सुनील सौरभ

MAKING THE NATION
IT SUPER POWER
www.vcsm-sts.com vcsmindia@gmail.com
VCSM®
विश्व कम्प्यूटर साक्षरता मिशन
A program initiated by Sanjeeo Technological System (P.) Ltd.
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified
VCSM की फ्रेंचाइजी बनिए और अपने साथ-साथ हजारों के कैरियर बनायें।
विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें : जूही अलका 9386551901

STS
A Part of Global IT Movement

झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के ख़िलाफ़ मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक नाराज़गी

शाह के तानाशाह

सभी फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

मुख्यमंत्री रघुवर दास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संरक्षण एवं आशीर्वाद मिलने के कारण कुछ ज्यादा ही दंभी हो गए हैं. यही कारण है कि वे राज्य के पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को तरजीह नहीं देते. यहां तक कि प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी उनका बेहतर समन्वय नहीं है. पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यवहार के कारण पार्टी से दूर होते जा रहे हैं. पार्टी के लोग अपने अध्यक्ष या संगठन मंत्री से खुलेआम शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी या सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे में पार्टी में बने रहने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है. राज्य में संगठन की स्थिति भी दिनोदिन कमजोर होती जा रही है.

प्रशांत शरण

झारखंड राज्य के गठन के 15 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ तो मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गया. पार्टी के अधिकांश विधायक किसी आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगे किसी की भी नहीं चली. अनुशासन का दंभ भरने वाली भाजपा में विधायकों की राय लिए बिना रघुवर दास को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और दास के माथे पर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया. अमित शाह के इस फैसले के बाद अधिकांश आदिवासी विधायक नाराज हो गए. यह अहसास अमित शाह के साथ ही रघुवर दास को भी होने लगा. पार्टी के बहुमत में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री को हमेशा सरकार गिरने का भय सताने लगा. यही कारण है कि दूसरी पार्टी को तोड़ने का काम भाजपा के आला नेताओं के इशारे पर शुरू हुआ. भाजपा से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई पार्टी बनाई थी. इस चुनाव में बाबूलाल की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने आठ विधानसभा क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया, पर उसके छह विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर भाजपा में शामिल करा लिया गया. विधानसभा एवं न्यायालय में दल-बदल को लेकर अभी भी मामला चल रहा है. फैसला आना अभी बाकी है. सरकार पर कोई खतरा नहीं आए यह सोच कर कांग्रेस को भी तोड़ने की मुहिम शुरू हुई पर भाजपाई इसमें सफल नहीं हो सके.

मुख्यमंत्री रघुवर दास शुरू से ही अंहकारी और बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते हैं. इस बार तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पर अहंकार और सिर चढ़कर बोलने लगा. पार्टी के वरीय नेताओं तक को अहमियत नहीं दी जा रही है. कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों को तो मुख्यमंत्री ऐसी फटकार लगाते हैं कि जैसे वो उनकी पार्टी का नेता नहीं होकर कोई अपराधी हो. इस वजह से पार्टी के लोगों के साथ उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं. मुख्यमंत्री के इस तानाशाही रवैये के कारण झारखंड में संगठन भी दिनोदिन कमजोर पड़ता जा रहा है. यह अहसास पार्टी के आला नेताओं को भी है पर अमित शाह के सामने अभी सबकी जुबान बंद पड़ी है, पर कभी भी यह विस्फोटक रूप ले सकता है. सरकार में शामिल घटक दल आजसू ने तो मुख्यमंत्री को तानाशाह ही करार दे दिया है. आजसू नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री सरकार को इस तरह चला रहे हैं जैसे कोई तानाशाह. किसी भी मुद्दे पर सहयोगी दलों के साथ मुख्यमंत्री सलाह-मशविरा करना उचित नहीं समझते हैं. स्थानीय नीति का हवाला देते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि उनकी पार्टी ने स्थानीय नीति को लेकर जो सुझाव दिए थे उसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया और आदिवासी-मूलवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए स्थानीय नीति घोषित कर दी, जिसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा है. पार्टी ने तो यहां तक चेतावनी दे डाली है कि अगर रघुवर अपने कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं तो पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है. यहां तक कि गठबंधन सरकार से अपना नाता भी तोड़ सकती है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास का अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भी संबंध मधुर नहीं रहा है. तालमेल एवं समन्वय का घोर अभाव है. मंत्रियों पर भड़ास निकालने में मुख्यमंत्री कोई गुरेज भी नहीं करते. राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय के मुख्यमंत्री का हुआ विवाद खुलकर सामने आ गया है. दरअसल दोनों के बीच खटास का रिश्ता शुरू से बना हुआ है. संघ परिवार के भारी दबाव के कारण मजबूरी में सरयू राय को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा था. झारखंड में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला और उन्हें केवल खाद्य आपूर्ति विभाग का झुनझुना थमा दिया गया. श्री राय इस तरह का विभाग मिलने से खुश नहीं थे, पर वे इस विभाग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कामकाज पटरी पर ला रहे थे. लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विभाग की समीक्षा के दौरान केवल इस विभाग की खामियां निकालीं और उसे गिनाना शुरू कर दिया. इससे विभाग के मंत्री बौखला गए. उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री बेवजह भड़ास न निकालें, नहीं तो कई और बातें सतह पर आने लगेंगी. मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच आंतरिक कलह चर्चा में है. विभागीय समीक्षा के दौरान भी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों पर हावी होने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना निर्णय थोपते हैं. मुख्यमंत्री के ऐसे रवैये और बार-बार अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण अधिकांश मंत्री नाखुश हैं. वरीय अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री का व्यवहार कुछ अव्यावहारिक ही है. अड़ियल रवैये के कारण राज्य के अधिकतर अधिकारी नाखुश हैं और इसका खामियाजा मंत्रियों को भुगतना पड़ता है. मुख्यमंत्री से नाखुश अधिकारी मंत्रियों पर अपनी खुन्नस निकालते हैं. इस कारण मंत्रियों और विभागीय सचिवों के बीच टकराव की नौबत बनी रहती है. मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी भरे शब्दों से ही संबोधित करते हैं. कभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की धमकी देते हैं तो कभी सचिवालय में शंट कर सड़ा देने की धमकी देते हैं. अधिकारियों को कभी अरे, क्या कर रहा है तू जैसे शब्दों का भी उपयोग कर देते हैं. अधिकारियों को काम करने की नसीहत एवं भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की नसीहत दे-देकर वे हमेशा अधिकारियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. सचिवालय में अधिकारी दबी जुबान से मुख्यमंत्री को अड़ियल और अहंकारी बताते हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री रघुवर दास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संरक्षण एवं आशीर्वाद मिलने के कारण कुछ ज्यादा ही दंभी हो गए हैं. यही कारण है कि वे राज्य के पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को तरजीह नहीं देते. यहां तक कि प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी उनका बेहतर समन्वय नहीं है. पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यवहार के कारण पार्टी से दूर होते जा रहे हैं. पार्टी के लोग अपने अध्यक्ष या संगठन मंत्री से खुलेआम शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी या सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे में पार्टी में बने रहने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है. राज्य में संगठन की स्थिति भी दिनोदिन कमजोर होती जा रही है. यह अहसास केंद्रीय नेताओं को है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे! निश्चित तौर पर इसका असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा. मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं कोखुलेआम दलाल और बिचौलिया वगैरह कहते रहते हैं, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा या पूर्व केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा जैसे नेता भी रघुवर सरकार को सलाह देने से कतराते हैं. यशवंत सिन्हा, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राय समेत कई अन्य वरीय नेता भी मुख्यमंत्री से दूर रहना ही ठीक समझते हैं. वैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास यह दावा करते हैं कि डेढ़ साल में झारखंड को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, विकास का कार्य दिखने लगा है, स्थानीयता का मुद्दा खत्म कर एक नया इतिहास बनाया है, राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त कर ही दम लेंगे, वगैरह वगैरह. लेकिन इन बातों से वे कब तक अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, यही देखना है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दे एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छतीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

शिशुओं को लू से बचायें

डॉ. सरिता सिंह
Child Specilist,MSM Hospital, Patna

ariskon Pharma Pvt.Ltd
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

गर्मी और हीट स्ट्रोक पर बातचीत हुई एम. एस.एम. हॉस्पिटल डॉ.सरिता सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ से। इन्होंने बताया कि बच्चों के प्रति लापरवाही न करें। इन दिनों गर्मी तेज है और छोटे बच्चे इसमें जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए जब भी आप बच्चों को लेकर बाहर निकलें तौलिया गमछा से ढक के बाहर निकलें। और साथ में पानी की बोतल लेकर अवश्य निकलें। हिट स्ट्रोक का हिन्दी अनुवाद होता है निर्जलीकरण इसलिए जरूरी है कि आप या छोटे बच्चे इस अवस्था में न पहुंचे इसके लिए इन्हें खूब सारा लिक्विड दिया जाना चाहिए। शरीर के तापामान में अचानक परविर्तन आने से लू लगने की संभावना ज्यादा होती है। डॉ राखी के अनुसार हिट स्ट्रोक के कारण बच्चों में जो लक्षण दिखेंगें वे इस प्रकार हैं- एक तो बच्चा अस्वस्थ दिखेगा। बच्चे में चिड़चिड़ापन रहेगा। त्वचा (ड्राय) रहना और पानी पीने की इच्छा में कमी आना। नैपकीन कम गीला करना। लू के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इस स्थिति में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और 103 डिग्री फारेनहाइट या अधिक के आस पास बुखार रहता है और शरीर से पसीना कम निकलता है। त्वचा सुखी लाल और गर्म रहती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को शांत रखने की कोशिश करें बच्चे को ठंढक वाली जगह पर रखें। बच्चे को सूती कपड़े ही पहनायें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ दें हो सके तो मां का स्तनपान करायें यदि वह छह महीने से छोटा हो तो यदि वह इससे अधिक हो तो तरल पदार्थ देते रहें। ज्यादा समय ब्यर्थ न करेके अच्छे फिजिशियन से सम्पर्क करें। आपको जो प्रमुख प्रयास करना है इस स्थिति में वह इस प्रकार है-जहां रहते हैं वहाँ का तापमान या टेम्प्रेचर कम करें कूलिंग रखें। बच्चे को ठंढ वाले जगह पर ले जायें। बच्चे से बातचीत कर या दुलार कर शांत रखने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को स्तन पान करायें। 6 महीने से उपर के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लिक्वीड दें। सबसे प्रमुख सलाहों में डॉक्टर राखी का मानाना है कि बच्चों को कूल बाथ दें। ठंढे पानी से नहायें। यह एक प्रकार का प्राथमिक उपचार है। ■ -भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

नाबालिग बता कर सपा नेता की बिटिया की शादी रुकवा दी, जनता स्तब्ध रह गई

दुष्ट दारोगा की बेशर्म करतूत

कानून के इस हाल से आजिज और अपमानित सपा नेता ने आत्मदाह कर लेने की धमकी दी है. मर्माहत गिरीश चंद्र पांडेय कहते हैं कि उन्हें सोची समझी साजिश का शिकार बनाया गया है. यही वजह है कि पुलिस ने गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. पांडेय कहते हैं कि न्याय नहीं मिला तो मैं पार्टी कार्यालय के सामने ही आत्मदाह कर लूंगा.

संतोष देव गिरि

एक तरफ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में पुनर्वापसी की तैयारी में जोर-शोर से जुटी है. सरकार की उपलब्धियों के तमाम बखान हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता साइकिल से जनसंदेश यात्रा निकाल कर पसीना बहा रहे हैं. लेकिन पार्टी से ही जुड़े आम कार्यकर्ताओं के सम्मान को सरेआम रौंदा जा रहा है, इस पर नेताओं का कोई ध्यान नहीं है. वाकया मीरजापुर जिले में पड़री थाना क्षेत्र के बेलवन गांव का है. गांव निवासी तथा समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता गिरीश चंद्र पांडेय की बिटिया की शादी 29 अप्रैल को होनी थी. बारात आ चुकी थी. सब लोग बारातियों के आवभगत में लगे थे कि पड़री थाने का दारोगा देवचन्द्र दो सिपाहियों के साथ विवाह स्थल पर आ धमका और यह कहते हुए लोगों को स्तब्ध कर दिया कि गिरीश पांडेय की बिटिया नाबालिग है. दारोगा ने सपा नेता की बिटिया को थाने ले जाने की जिद ठान दी. सपा नेता ने दारोगा को लड़की की पंजीकृत उम्र और

सामाजिक मार्यादा का हवाला दिया लेकिन दारोगा मानने को तैयार नहीं था. लड़की की उम्र की तस्दीक करने वाले हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देखने के बावजूद दारोगा ने गिरीश चंद्र पांडेय और उनके परिवार की प्रतिष्ठा का पूरा हनन किया. दारोगा ने रात में ही वह स्कूल खुलवाया, जहां से लड़की ने शिक्षा ग्रहण की थी. स्कूल में सारे रिकार्ड दुरुस्त पाए जाने के बाद ही दारोगा वापस लौटा. लेकिन दारोगा जो एजेंडा लेकर आया था, उसे पूरा कर गया. दारोगा की इस सार्वजनिक गुंडागर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस ने इतना ही बताया कि किसी ने फोन पर लड़की के नाबालिग होने की सूचना दी थी. इसी पर दारोगा गुंडई के तेवर में आ गए. इस घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं. उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऐसे स्वरूप की कोई कल्पना ही नहीं थी. सपा नेता ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कृषि मंत्री मनोज पांडेय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ मीरजापुर के पुलिस अधीक्षक व सपा के जिलाध्यक्ष को इस घटना की सूचना दी. लेकिन मामूली नेता की सत्ता-हनक के आगे क्या औकात है. पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन बेलाग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि यह मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है, फिर कहते हैं कि जांच कराई जा रही है. कानून के इस हाल से आजिज और अपमानित सपा नेता ने आत्मदाह कर लेने की धमकी दी है. मर्माहत गिरीश चंद्र पांडेय कहते हैं कि उन्हें सोची समझी साजिश का शिकार बनाया गया है. यही वजह है कि पुलिस ने गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. पांडेय कहते हैं कि न्याय नहीं मिला तो मैं पार्टी कार्यालय के सामने ही आत्मदाह कर लूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोगों के 90 करोड़ लेकर भाग गया पुलिस का चहेता फ्रॉड

फतेहपुर में फतह धोखेबाजों की

नूर अहमद सिद्दीकी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में करोड़ रुपये की धोखाधड़ी चर्चा में है. चिट फंड कंपनी बना कर लोगों को लूटने का धंधा पूरे प्रदेश में चल रहा है. कभी इलाहाबाद में तो कभी फतेहपुर में तो कभी किसी अन्य जिले में. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नेताओं को पैसा पहुंच रहा है और धंधा बेधड़क चल रहा है. अभी फतेहपुर जिले में ऐरायां ब्लॉक के अंतर्गत खजरियापुर गांव में नवम्बर 2015 से हमारा मिशन नामक चिट फंड कंपनी लोगों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई है. खजरियापुर गांव निवासी राजेश मौर्या (पुत्र मंगल प्रसाद मौर्या) ने प्रेमनगर कस्बे की खस्ताहाल सड़क को अपने निजी पैसों से सुधरवा कर लोगों में अपना विश्वास जमाया और उन्हें चूना लगा गया. लोगों ने समझा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते यह सब हो रहा है पर सच तो कुछ और ही निकला. राजेश मौर्या ने अपनी शादी में पूरे इलाके के लोगों को शानदार भोज कराया. उसकी बारात में 700 लक्जरी गाड़ियों और दर्जनों लक्जरी बसों का इंतजाम था. खैर, लोगों में साख जमाने के बाद उसने अपनी चिट फंड कंपनी मिशन ग्रुप्स ऑफ कम्पनीज़ में आयुर्वेदिक दवा बनाने के नाम पर लोगों से निवेश कराना शुरू किया.

लोगों से एकमुश्त 30 हजार रुपये लिए जाते थे और उन्हें अगले माह से 10 हजार रुपये लगातार 11 महीनों तक दिए जाने का वादा किया जाता था. यानी 30 हजार देकर प्रत्येक 11 महीने तक 10 हजार रुपये अर्थात 30 हजार के एवज में कुल एक लाख 10 हजार रुपये दिए जाने का वादा. लोगों ने ऐसे वादे पर संदेह नहीं किया और निवेशकों की तादाद बढ़ती ही गई. इस तरह धंधेबाज ने 90 करोड़ रुपये से अधिक धन जमा किया और लापता हो गया. कंपनी का संचालक राजेश मौर्या, उसका भाई ब्रजेश मौर्या, पत्नी पूजा मौर्या और खजरियापुर गांव के कुछ अन्य लोग फरार हैं.

राजेश मौर्या ने सबसे पहले अपनी मौर्या बिरादरी के लोगों को ही एजेंट बनाया और उनके जरिए लोगों का निवेश कराया. इन्हीं एजेंटों के माध्यम से अन्य लोग भी एजेंट बने. कंपनी द्वारा जमा की कोई रसीद नहीं देकर निवेशक को एक डायरी दिखाई जाती थी, जिसमें एजेंट और क्लाइंट का डिटेल लिखा जाता था. बाद में निवेशक से एक शपथ-पत्र भी लिया गया जिसमें लिखवाया गया की वे कंपनी को 30 हजार रुपये दान में दे रहे हैं. मतिभ्रम के शिकार लोग इसके बावजूद सतर्क नहीं हुए. लोग बताते हैं कि फ्रॉड राजेश मौर्या का धंधा केवल फतेहपुर में ही नहीं बल्कि कौशांबी, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, रायबरेली, उन्नाव व कुछ अन्य जिलों में भी फैला है. धंधेबाज ने नियुक्त किए गए एजेंटों को भी लूटने से परहेज नहीं किया. व्यापारी अशोक तिवारी और उनके रिश्तेदारों ने 15 लाख रुपये लगाए. ऐरायां सादात की ग्राम प्रधान के पति शमशाद कुरैशी और उनके रिश्तेदारों ने 20 लाख रुपये का निवेश किया था, जबकि कुरैशी उस फ्रॉड राजेश मौर्य का खास व्यक्ति था. इसी प्रकार सैकड़ों एजेंट्स के माध्यम से रुपये जमा कराए गए. थाना सुल्तानपुर घोष में राजेश मौर्या, ब्रजेश मौर्या, पूजा मौर्या के साथ ही उसी गांव के कुछ अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस के हाथ गर्म हो चुके हैं इसलिए वह हाथ पर हाथ धरे बैठी है. यह स्थानीय लोगों का स्पष्ट आरोप है. लोग यह भी कहते हैं कि स्थानीय नेता भी मौर्या से पैसा खाए हुए हैं. इस भीषण धोखाधड़ी से लोग गहरे सदमे में हैं. दबाव के कारण कई एजेंट्स के घरों में मौत हो चुकी है. सुल्तानपुर घोष गांव के दिनेश यादव के पिता राकेश यादव की इसी वजह से मौत हो गई. दिनेश ने लोगों के करीब 10 लाख रुपये जमा कराए थे. इसी तरह डोली का पुरवा निवासी झूरी ने बैंस बेचकर, प्रेमनगर के कपड़ा व्यापारी सैयद इंतियाक ने अपनी दुकान बेचकर, प्रेमनगर की मीरा ने बैंक से लोन लेकर, कसेरुआ की बिटान देवी और पोखरी के कल्लू और बुद्धिलाल ने साहूकार से कर्ज लेकर, बेहटापर के कल्लू व मनोज ने केसीसी से कर्ज लेकर पैसे लगाए थे जो डूब गए. ये सभी भीषण सदमे में हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है. ■

पहले भी फ्रॉड कर चुका है राजेश मौर्या

फतेहपुर जिले में कंपनी स्थापित करने से पहले राजेश मौर्या इलाहाबाद में भी ऐसी ही धोखाधड़ी कर चुका है. इलाहाबाद पुलिस ने उसकी कंपनी राज्य कल्याण मिशन (आरकेएम) पर छापा मारकर लाखों रुपये बरामद भी किए थे. कंपनी सील कर दी गई थी. लेकिन मौर्या ने दूसरे जिलों में अपना धंधा जारी रखा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा की उल्टी पड़ी चाल

हरीश सरकार बहाल

राजकुमार शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पहाड़ चढ़ने से पहले ही टूट गया. इसे आकार देने की जिम्मेदारी स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ली थी, जिसका सेनापति भाजपा के राष्ट्रीय महा सचिव कैलाश विजय वर्गीय को बनाया था. वे भी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए. अमित शाह की रणनीति थी कि कांग्रेस में बगावत पैदा कर उसी के तीर से हरीश सरकार को निशाना बनाया जाए और देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता पर किसी भी तरह से कब्जा जमा लिया जाए. उनके मंशा के अनुरूप हुआ भी, विजय बहुगुणा, डॉ हरक सिंह समेत कांग्रेस के नौ विधायक पद की लालच में भाजपा से जा मिले. विधायकों के बगावत करते ही मोदी सरकार ने हरीश रावत को बिना कोई अवसर दिए आनन-फानन में राष्ट्रपति शासन लगा दिया. देश की न्यायव्यवस्था ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए स्वयं हस्तक्षेप कर उत्तराखंड में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता दिखाया. पूरे देश में उत्तराखंड की इस घटना को लेकर मोदी सरकार की किरकिरी हुई. प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पूरे देश में सराहना हुई.

सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा तार-तार होने से बच गई. पूरे देश में यह संदेश गया कि मोदी सरकार का उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लोकतंत्र विरोधी था. सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में भी दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के एक-एक विधायक ने एक दूसरे के पक्ष में मतदान किया. इस अवसर पर सूबे के निर्दलीय विधायकों के फ्रंट पीडीएफ ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया. बसपा सुप्रीमों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और बसपा के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरीश सरकार को धराशाई करने की योजना विजय बहुगुणा ने भाजपा से मिलकर एक वर्ष पूर्व ही बना लिया था. इसी वजह से बार-बार बहुगुणा सरकार के सहयोगी दल पीडीएफ को सरकार से दूर करने की मांग कांग्रेस हाईकमान से करते रहे. और सूबे में हरीश सरकार को हमेशा निशाना बनाते रहे. हरीश रावत पहले ही विजय बहुगुणा के इस कदम से वाकिफ हो गए थे और पहले ही कांग्रेस हाईकमान के सामने सारी बातें रख दी थीं. ■

अमित शाह की रणनीति थी कि कांग्रेस में बगावत पैदा कर उसी के तीर से हरीश सरकार को निशाना बनाया जाए और उत्तराखंड की सत्ता पर किसी भी तरह से कब्जा जमा लिया जाए.

केंद्र ने कहा पानी लो तो अखिलेश बोले बुंदेलखंड में बहुत पानी है!

प्यास पर पॉलिटिक्स घिनौनी

उत्तर प्रदेश की सूखी जमीन पर नेताओं की शर्मो-हया पानी-पानी

इक़रार पठान

बुंदेलखंड में सुलग रही सियासी आग को केंद्र सरकार के पानी ने और बढ़ा दिया है. महोबा में वाटर एक्सप्रेस भेजे जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने है. दोनों तरफ से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं और इनमें से कोई भी बैकफुट पर जाने को राजी नहीं है. जनता के हितों का ढिंढोरा पीट रही दोनों ही सरकारों ने प्यास को पॉलिटिक्स में बदलकर राजनीति की जो घिनौनी तस्वीर गढ़ी है, वह बेहद शर्मनाक है. शर्मनाक है केंद्र सरकार की वह पहल जो आधी-अधूरी की गई और शर्मनाक है राज्य सरकार का वह बयान जिसमें कहा गया कि बुंदेलखंड में पानी ही पानी है और इससे भी अधिक शर्मनाक है प्रशासन की वह रिपोर्ट जिसके आधार पर राज्य सरकार ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान दे रही है. जो प्रशासन संगीनों के साये में पानी बांट रहा हो, जिसकी नज़रों के सामने पानी के लिए अनशन और प्रदर्शन हो रहे हों और जिस प्रशासन ने पानी चोरी में खुद एक किसान को जेल भेज दिया हो, वह सरकार सब ठीक-ठाक होने का दावा करे तो इसे बेशर्मी नहीं तो क्या कहेंगे! फकत सियासत के लिए जनता के मौलिक अधिकारों, उनकी संवेदनाओं और संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस तरह का खिलवाड़ माफी के काबिल नहीं है.

जिस सूखे ने बुंदेलखंड को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, आज वही सूखा यहां सियासत का जरिया बनाया जा रहा है. निरंतर हो रही किसानों की आत्महत्याओं, बढ़ते पलायन, भीषण विद्युत कटौती और बंजर हो चुकी कृषि भूमि जैसी समस्याओं से लापरवाह सियासतदान अब बुंदेलों की प्यास में राजनीतिक सफलता का जुगाड़ तलाश रहे हैं. यहां लोगों की संवेदनाओं को ताक पर रख सियासत का घिनौना खेल खेला जा रहा है. केंद्र सरकार वाटर ट्रेन भेजकर चुनावी वैतरणी पार करने की फिराक में है तो राज्य सरकार उसे रोक कर सत्ता वापसी का रास्ता टटोल रही है. इस सियासी नूराकुश्ती का अखाड़ा बन चुका बुंदेलखंड निरंतर बदहाली की तरफ अग्रसर है. उत्तर प्रदेश के इस सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र की दशा और उस पर होती पॉलिटिक्स का सच कितना घिनौना है, जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. विगत पांच वर्षों से दैवीय आपदाओं का शिकार बुंदेलखंड नेताओं के लिए राजनीति की बिसात और प्रशासनिक अफसरों के लिए चारागाह बना हुआ है. व्यवस्था के यह दोनों अंग मिल बांटकर इस क्षेत्र को लूट रहे हैं. एक योजनाओं को तैयार करने के नाम पर तो दूसरा उन योजनाओं के कथित क्रियान्वयन की आड़ में सरकारी धन को ठिकाने लगा रहा है. खुले शब्दों में कहें कि बुंदेलखंड का सूखा नीति-निर्धारकों तथा प्रशासनिक तंत्र के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है.

पैसा मांगते हैं, पर खर्च नहीं करते

विडंबना है कि सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की राहत के लिए दी गई धनराशि किसानों को नहीं दी जा रही. प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता में यह काम है ही नहीं. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि सूखा प्रभावित जनपदों में वितरित किए जाने के लिए सरकार ने 867 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उसमें से केवल 52 करोड़ रुपये ही बांटे जा सके. प्रशासन की इस लापरवाही पर मुख्य सचिव ने गहरी नाराजगी भी जाहिर की है. लेकिन इस नाराजगी का प्रशासन तंत्र पर कोई असर नहीं. बुंदेलखंड के कई जिलों के जिलाधिकारियों ने यह भी शिकायत भेजी है कि जल निगम द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेयजल समस्या से निपटने में मुश्किलें पेश आ रही हैं. सरकारी निर्देश है कि सूखे से प्रभावित प्रत्येक गांव में कम से कम एक तालाब पानी से अवश्य भरा हो, लेकिन प्रशासन को सरकार के इस निर्देश की कोई परवाह नहीं है. ■

पानी और अनाज के साथ बिजली की भी कटौती

पानी को राजनीति का हथियार बनाने वाले माननीयों और उनके इशारों पर नाचते प्रशासन को बुंदेलखंड में हो रही भीषण विद्युत कटौती नजर नहीं आती. विद्युत आपूर्ति के मामले में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम खिल्ली उड़ाई जा रही है, यह मुख्यमंत्री को नहीं दिखता. महोबा में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति के आदेश के बावजूद बमुश्किल कुछ घंटे ही बिजली दी जा रही है. अपनी दबंग और भ्रष्ट कार्यशैली के लिए मशहूर विद्युत विभाग का एक्सईएन नेकी राम किसी को भी ठेंगे पर रखने का दंभ भरता रहता है. जिलाधिकारी हों या फिर सत्ताधारी दल के स्थानीय नेता सब नेकी राम के ठेंगे पर ही रहते हैं. इस विभाग की मनमानी के खिलाफ बुंदेली समाज को धरने पर बैठे लगभग डेढ़ माह हो चला पर उनकी समस्याओं के निराकरण की बात तो छोड़ें, उनकी कोई बात भी नहीं सुन रहा. बुंदेलखंड में पानी की किल्लत पर केंद्र का ध्यान जाने का श्रेय यहां के बुद्धजीवी चौथी दुनिया को भी देते हैं. महोबा डीएवी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और वरिष्ठ समाजसेवी शिवकुमार गोस्वामी हों या कांग्रेस नेता और अधिवक्ता उमेश उपाध्याय या किसान नेता रामरतन गुरुदेव और हाजी हनीफ जैसे कई लोग यह कहते हैं कि यदि चौथी दुनिया ने बुंदेलखंड के सूखे को प्रमुखता से नहीं उठाया होता तो आज केंद्र सरकार नींद से नहीं जागती. बुंदेलखंड में समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर समाजसेवियों का मत है कि नेताओं को प्यास पर राजनीति न कर उस समस्या के निराकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उधर, कबरई के लोग भी पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. पेयजल संकट से जूझ रहे कस्बा वासियों ने बीते आठ मई को पूरा बाजार बंद कर दिया और कबरई नगर पंचायत अध्यक्ष शिवपाल तिवारी की अगुवाई में धरने पर बैठ गए. देशभर में पत्थर उद्योग के लिए पहचाना जाने वाला कबरई आज जिले में सर्वाधिक प्यासा क्षेत्र है. यहां कई टैंकर लगाए गए हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चल रहा. हाल ही में जल संस्थान और जल निगम के संयुक्त प्रयास पर तीन ट्यूब-वेल लगाए गए हैं और उनकी लाइन बिछाने का काम चल रहा है. जिला प्रशासन का दावा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति शीघ्र शुरू कर दी जाएगी. लेकिन स्थानीय लोग इस आश्वासन को झूठा बताते हैं. ■

पानी की कहासुनी पर भतीजी को सूखे कुएं में फेंक दिया

प्रदेश के मुख्यमंत्री महोबा में पानी की कमी से इंकार करते हैं, मगर महोबा की असलियत यह है कि पेयजल के लिए लोग अनशन, धरना और प्रदर्शन से लेकर झगड़ा करने तक के लिए मजबूर हैं. यहीं नहीं पानी के लिए रिश्ते भी तार-तार हो रहे हैं. महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम पिपरामाफ़ में घटित घटना पानी की समस्या की सच्ची तस्वीर दिखाती है. पिपरामाफ़ निवासी घनश्याम प्रजापति की आठ वर्षीया पुत्री क्रांति गांव में बने सरकारी हैंडपम्प में पानी भर रही थी तभी वहां घनश्याम का भाई किशन और उसकी पत्नी भी पानी भरने पहुंच गए. इन लोगों ने क्रांति की बाल्टी हटा कर अपनी बाल्टी लगा दी. क्रांति ने चाची से कहा कि वह पहले पानी भर ले, इस पर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई. क्रांति ने जब यह कहा कि यह सरकारी हैंडपम्प है तो उसका चाचा किशन क्रांति को पास के सूखे कुएं में फेंकने की धमकी देने लगा. उसकी पत्नी ने क्रांति को कुएं में धकेल भी दिया. कुएं में गिरकर क्रांति बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो उसने चीख पुकार शुरू कर दी. कुएं से लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे कुएं से निकाला. स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. क्रांति को पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आई. क्रांति को सीने और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन हत्या पर आमादा उसकी चाची और चाचा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. ■

पटरी से उतर चुकी यहां की व्यवस्था को पुनः बहाल करने का सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है. अगर ऐसा नहीं तो फिर पानी पर पॉलिटिक्स करने वाली राज्य सरकार को यहां की गंभीर समस्याएं नजर क्यों नहीं आ रहीं!

बुंदेलखंड में पानी ही पानी है, जैसा हास्यास्पद बयान देने वाले सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव को पानी नहीं केवल और केवल सियासत दिखती है. ऐसा भौंडा बयान देने से पहले महोबा जनपद के उन गांवों की तरफ एक नजर अवश्य दौड़ा लेनी चाहिए थी, जहां पुलिस की देख-रेख में पानी बांटा जा रहा है. कुछ बोलने से पहले उस एफआईआर पर भी गौर कर लेना चाहिए था, जो बीते दिनों पानी चोरी करने पर एक किसान के खिलाफ महोबा जल संस्थान द्वारा दर्ज कराई गई थी. केंद्र सरकार ने पानी की पेशकश क्या की महोबा डीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक सब हालात काबू में बताने लगे. हद तो तब हो गई जब सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने मातहतों की उस रिपोर्ट को बिना जांचे परखे हरी झंडी दे दी. उन्होंने अपने मातहतों से यह भी नहीं पूछा कि जब महोबा में पानी का संकट नहीं है तो सैकड़ों टैंकर पानी प्रतिदिन कहां और क्यों बांटा जा रहा है! यदि सब ठीक-ठाक ही है तो फिर कबरई में हजारों लोग बाजार बंद कर धरने पर क्यों बैठने पर विवश हुए! मुख्यमंत्री अपनी अपाहिज मशीनरी से यह भी पूछ लेते कि जब महोबा में पर्याप्त पानी है तो हीरालाल यादव को पानी चुराने की क्या जरूरत थी कि उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया! मुख्यमंत्री के सिपहसालार असल तस्वीर पर परदा डाल कर मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री को वही देखना अच्छा भी लग रहा है. सच वह नहीं है जो प्रदेश सरकार की विकलांग मशीनरी पेश कर रही है. सच वह है जो बुंदेलखंड की चीख में सुनाई और दिखाई दे रहा है. सत्ता अलमबरदारों और सियासतदानों को इसे गौर से सुनना-समझना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि बुंदेलखंड के अभिशप्त लोग नेताओं के सत्ता-सुख और सत्ता की छीनझपट पर कहर बन कर टूटें. पानी और भूख पर सियासत नेताओं के बुरे दिन का मार्ग खोल रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पानी चोरी में जेल! फिर भी बहुत पानी है

महोबा जनपद मुख्यालय के बंधान वार्ड निवासी हीरालाल यादव जेल में हैं. उन पर जो आरोप हैं उसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि बुंदेलखंड में कहां और कितना सूखा है. छह मई को जल संस्थान के अवर अभियंता एसके वर्मा ने कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी जिसमें हीरालाल यादव को पानी चोर बताया गया. वर्मा का कथन था कि आरोपी ने वाटर सप्लाई लाइन के सेल्युज वॉल्व को ढीला कर पानी की चोरी की है. गौरतलब है कि तहरीर देने वाला यह वही विभाग है जिसके आला अफसर अपनी रिपोर्ट में पेयजल संकट से इंकार कर चुके हैं. अब सवाल यह उठता है कि जब शहर में पर्याप्त पानी है तो फिर हीरालाल यादव ने यह अपराध क्यों किया? इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर से गंभीर मामलों पर कार्रवाई से कतराने वाली पुलिस ने आनन-फानन में जल संस्थान की तहरीर पर न केवल मुकदमा लिख लिया बल्कि बिना देरी किए आरोपी को जेल में भी ठूंस दिया. मानवीय पुलिस ने पानी चोर हीरालाल यादव पर लोक संपत्ति क्षति अधिनियम की धारा 430, 353 एवं 3/4 के तहत कार्रवाई की और संवेदनशील होने का बेहतर सबूत पेश किया. ■

हाथ में कटोरा, मदद का ढिंढोरा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बुंदेलखंड में पानी पर्याप्त है. फिर पानी की व्यवस्था के लिए केंद्र से पैसा भी मांगते हैं. फिर यह भी कहते हैं कि बुंदेलखंड में उपलब्ध पर्याप्त पानी के वितरण के लिए 10 हजार टैंकर खरीदने हेतु केंद्र सरकार पैसा दे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तब मुख्यमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराए जाने की मांग की थी. इसके बाद जब केंद्र ने ट्रेन से पानी भेजने का निर्णय लिया तो मुख्यमंत्री ने उसमें राजनीति घुसेड़ते हुए पानी लेने से मना कर दिया. जबकि इसके पहले मुख्यमंत्री ने सूखा मेमोरेंडम के तहत केंद्र से मांगी गई धनराशि का जिक्र करते हुए 1123.47 करोड़ रुपये मांगे थे. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष सीमित अनाज और सीमित चारे का भी रोना रोया था. लेकिन भूख और प्यास से किसानों की मौत या आत्महत्या की बात आती है तो मुख्यमंत्री समेत समस्त सरकार तरह-तरह के फर्जी दावे करने लगती है. मुख्यमंत्री ने केवल बुंदेलखंड के लिए सर्फेस स्रोत आधारित 24 पेयजल परियोजनाओं हेतु 1689.38 करोड़ रुपये मांगे. इसके अलावा सूखा प्रभावित जनपदों में नहरों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए भी केंद्र से रुपये मांगे गए. इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से प्रदेश के पेयजल संकट से निपटने में मदद मांगी थी. ■

बांग्लादेश में बदलाव की बयार

1947 के बंटवारे की वजह से न सिर्फ़ लाखों लोगों का पलायन हुआ, बल्कि कारख़ानों और खेती का रिश्ता भी इसने ख़राब कर दिया. बंटवारे के बाद कोलकाता की अधिकांश जूट मिलें कच्चा माल के अभाव में धीरे-धीरे बंद हो गईं. इससे न सिर्फ़ किसान, बल्कि मज़दूरों से उनका रोज़गार भी छिन गया. बांग्लादेश में मज़दूरों की स्थिति फ़िलहाल अच्छी नहीं है.

ढाका स्थित शहीद मीनार

शेख मुजीबुर्रहमान की स्मृति में बना संग्रहालय

अभिषेक रंजन सिंह

बांग्लादेश की राजधानी ढाका कमोबेश कोलकाता जैसी ही है. पुरानी बसावट के लिहाज से थोड़ा बहुत बनारस, भोपाल और हैदराबाद से मेल खाती हुई. दक्षिण एशिया की तरह एक जैसी समस्याएं, जिज्ञासाएं, बेचैनी और मन में अनगिनत सवाल! आंखों में तरक्की के सपने, अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रति बेहद लगाव. मस्जिदों और कामगारों के शहर ढाका की सुबह बेहद खूबसूरत होती है. सवेरे-सवेरे काम पर जाने वालों की भागम-भाग और शाम होते ही सड़कों पर सुकून और इत्मीनान का अहसास. यहां बांग्ला गीतों में रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां सुनने के बाद सीमाओं का बोध खत्म हो जाता है. ढाका रेडियो स्टेशन और टेलीविजन केंद्र का वाचनालय का मुख्य आकर्षण रवींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरूल इस्लाम का तैल चित्र उनकी अहमियत बताने के लिए काफी है.

ढाका यूनिवर्सिटी और उसके आस-पास के इलाके मसलन, लालमटिया, मुहम्मदपुर, असद गेट एवं धानमंडी इलाक़े में गिटार बजाते हुए नौजवानों के कई समूह देर रात तक आपको दिख जाएंगे. उनके गीतों में संघर्ष और बदलाव के धुन महसूस होते हैं. बांग्लादेश में भी छात्र राजनीति का गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन छात्रसंघ की स्थिति यहां थोड़ी बेहतर है. बांग्लादेश के ज्यादातर सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव होते हैं, जबकि भारत के कई राज्यों में छात्रसंघ पाबंदियां झेल रहे हैं. ढाका में कोलकाता की तरह ट्राम तो नहीं चलती, लेकिन मुंबई की तरह यहां डबल डेकर बसें जरूर चलती हैं. दिन में ढाका की सड़कें काफी व्यस्त रहती हैं. सड़क जाम यहां की एक बड़ी समस्या है. कई लोग सड़कों पर पैडल रिक्शा का बेरोक टोक परिचालन सड़क जाम की वजह मानते हैं. लेकिन ढाका को रिक्शा मुक्त कर पाना फिलहाल संभव नहीं है. ढाका के हर इलाक़े में आपको रिक्शा दिख जाएगा, यहां तक कि संसद भवन जैसे अति सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में भी. ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों का कहना है कि सरकार को रिक्शे का परिचालन ढाका में बंद कर देना चाहिए. वहीं कुछ सामाजिक संगठन ऐसी मांग के सख्त ख़िलाफ़ हैं. उनका मानना है कि रिक्शा न सिर्फ ढाका की पहचान है, बल्कि इससे हज़ारों लोगों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है. इसे बंद करने का मतलब है गरीबों से उनका रोज़गार छीनना और ढाका की पहचान ख़त्म करना. ढाका में रिक्शे की यही अहमियत उसके वजूद का कारण है. हालांकि, इसके पीछे सियासी मतलब भी छुपा हुआ है. सत्ताधारी अवामी लीग हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रिक्शों पर पाबंदी की बात कहना तो दूर की बात है, वे ऐसा सोच भी नहीं सकतीं, क्योंकि ढाका के रिक्शा चालक यहां की पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक भी हैं.

ब्रिटिश इंडिया के वक्त ढाका और कोलकाता एकीकृत बंगाल की प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक केंद्र थे. वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ढाका और कोलकाता मुफीद जगह थे. शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने ढाका में कई गुप्त बैठकें की थीं. ढाका का पलटन बाजार और तोपखाना रोड क्रांतिकारियों के गढ़ माने जाते थे. तोपखाना रोड की गलियों में आज भी कई ऐसे ब्रिटिशकालीन मकान मिल जाएंगे, जो उन दिनों की याद दिलाते हैं. ढाका के पुराने इलाकों में शुमार इन जगहों पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तर आज भी मौजूद हैं. इसके अलावा, यहां बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों ख़ासकर गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े यूनियनों के कार्यालय बहतायत हैं. एक दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की अच्छी ख़ासी भागीदारी है.

बंटवारे से पहले जूट की मिलें ज्यादातर कोलकाता में थीं, लेकिन जूट की सर्वाधिक खेती पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) में होती थी. 1947 के बंटवारे की वजह से न सिर्फ़ लाखों लोगों का पलायन हुआ, बल्कि कारख़ानों और खेती का रिश्ता भी इसने ख़राब कर दिया. बंटवारे के बाद कोलकाता की अधिकांश जूट मिलें कच्चा माल के अभाव में धीरे-धीरे बंद हो गईं. इससे न सिर्फ़ किसान, बल्कि मज़दूरों से उनका रोज़गार भी छिन गया. बांग्लादेश में मज़दूरों की स्थिति फ़िलहाल अच्छी नहीं है. शेख हसीना सरकार देश में निजीकरण पर ज़ोर दे रही है. विदेशी कंपनियों के लिए बांग्लादेश का रास्ता खोल दिया गया है. सरकार की इन आर्थिक नीतियों से देश के श्रमिक संगठन बेहद नाराज़ हैं. यहां मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी देने का सवाल हो या उनकी बाकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की, इस पर उतना ग़ौर नहीं किया जाता. भारत की तरह यहां के श्रमिक संगठन भी श्रम सुधारों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं. भूमि सुधार न होना बांग्लादेश की एक दूसरी बड़ी समस्या है. पाकिस्तान की तरह यहां भी भूमि के एक बड़े हिस्से पर राजनेताओं एवं उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा है. जिस तरह पाकिस्तान की राजनीति से जुड़े लोगों के पास हज़ारों एकड़ जमीन है, ठीक वही स्थिति बांग्लादेश में भी है. बांग्लादेश भूमिहीन समिति के महासचिव सुबल सरकार देश की भूमिहीन जनता को न्याय दिलाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. इस बारे में वह कहते हैं, अगर हमें बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के सपनों का देश बनाना है, तो सबसे पहले बांग्लादेश में भूमि सुधार क़ानून को लागू करना होगा. यहां चंद मुठ्ठी भर लोगों के पास बड़ी जमीनें हैं, बाकी ज्यादातर लोग उनके अधीन खेती करते हैं.

ढाका में 1971 के मुक्ति युद्ध की कई निशानियां मौजूद हैं. पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने वाले जनरल अरोड़ा और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की दस्तख़त करती एक पेंटिंग धानमंडी की दीवारों पर देखी जा सकती है. ढाका में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है. 21 फरवरी की पूरी रात ढाका वासी सोते नहीं हैं.

ढाका स्थित ट्रेड यूनियन की एक बैठक में भाषण दे रही महिला नेत्री

अभिव्यक्ति की आज़ादी की चर्चा बांग्लादेश में भी होती है. ट्रेड यूनियन से जुड़ी एक महिला इशरत परवीन बताती हैं कि तसलीमा नसरीन को पढ़ना उन्हें काफ़ी पसंद है, क्योंकि वह धार्मिक कट्टरता के बारे में खुलकर लिखती हैं. उनकी किताबों को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए. उन्होंने जो लिखा है, उसमें ग़लत कुछ नहीं है. तसलीमा को बांग्लादेश आने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि यह देश उनका भी है.

ढाका में 1971 के मुक्ति युद्ध की कई निशानियां मौजूद हैं. पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने वाले जनरल अरोड़ा और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की दस्तख़त करती एक पेंटिंग धानमंडी की दीवारों पर देखी जा सकती है. ढाका में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है. 21 फरवरी की पूरी रात ढाका वासी सोते नहीं हैं. लाखों की संख्या में लोग फूलों का गुलदस्ता लिए शहीद मीनार पहुंचते हैं. अपनी भाषा और अपने देश के प्रति यह प्रेम देखने लायक होता है. संयुक्त राष्ट्र ने भी साल 2010 में इस कुर्बानी की अहमियत समझते हुए 21 फरवरी के दिन को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में घोषित किया. गौरतलब है 1952 में पाकिस्तानी सेना ने उर्दू भाषा का विरोध कर रहे छात्रों की निर्मम हत्या कर दी थी. शहीद होने वालों में सोहिद, रफ़ीक, अब्दुल जब्बार समेत कई छात्र थे. मेरा ढाका ऐसे वक्त आना हुआ, जब यहां मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा था. रात क़रीब 10 बजे तोपखाना रोड से हम लोग शाहबाग स्थित शहीद मीनार की तरफ पैदल बढ़ रहे थे. सबसे ख़ास बात यह थी कि लाखों लोगों की इस भीड़ में एक गजब का अनुशासन था. सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा. ढाका की सड़कों पर यूं रात भर पैदल चलते रहना काफी रोमांचकारी था. रात पौने दो बजे हम शहीद मीनार पहुंचे. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और सरकार में शामिल मंत्रियों एवं सांसदों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद आम लोगों के लिए शहीद मीनार खोल दिया गया. शहीद मीनार जाने वाले लोग अपने जूते और चप्पल बाहर ही खोलकर रख देते थे. पवित्रता का यह ख्याल अक्सर मंदिरों और मस्जिदों में देखने को मिलता है. शहीद मीनार पहुंचने पर ढाका यूनिवर्सिटी के एक छात्र अश्फाक को जब यह पता चला कि मैं भारत से हूं, तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई. भारत अमार बंधु कहते हुए उसने एक पट्टी मेरे सर में बांध दी, जिसमें बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज अंकित था. शहीद मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हमारे साथ मौजूद आठ-दस लोग ढाका प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे. वहां हमारी मुलाकात स्थानीय बांग्ला नाट्य कलाकारों से हुई. उनके आग्रह पर हम लोग प्रेस क्लब के बाहर चाय पीने के लिए रुक गए. वहां हमारी मुलाकात कोलकाता से साइकिल चलाकर ढाका पहुंचे प्रशांत मजूमदार से हुई. उन्होंने बताया कि वह मातृभाषा दिवस का जश्न मनाने ढाका आए हैं. वहां बातचीत का दौर लगभग डेढ़ घंटे तक चला. उसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, बंटवारे ने एकीकृत बंगाल को हर मामले में नुक़सान पहुंचाया! बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल से कई बड़ी हस्तियां पश्चिम बंगाल में जाकर बस गईं और उसी तरह पश्चिम बंगाल की कई शख़्सियतें यहां ढाका में बस गईं. यह दर्द दोनों तरफ के लोगों का है. शायद यही दर्द पंजाब में भी महसूस किया जाता है. लाहौर के लोगों की निगाहें अमृतसर की तरफ लगी रहती हैं और अमृतसर के लोगों की निगाहें लाहौर की तरफ. दरअसल, यह त्रासदी उस अव्यवहारिक बंटवारे का नतीज़ा है, जो हर साल इस दर्द को ताज़ा कर देती है. 22 फरवरी को मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान मेमोरियल म्यूजियम देखने पहुंचा. 1975 में इसी आवास पर शेख मुजीब, उनके बेटे, पत्नी और बहू की निर्मम हत्या जियाउर रहमान ने करवा दी थी. दीवारों पर गोलियों के निशान और खून के सूखे धब्बे आज भी उन दिनों की बर्बरता की याद दिलाती है. देश भर से इस म्यूजियम को देखने हजारों लोग ढाका आते हैं.

इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश का जन्म एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ. तमाम झंझावतों को झेलते हुए यह देश प्रायः हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. बांग्लादेश कपड़ों का बड़ा बाजार है. रेडीमेड कपड़ों की हज़ारों फैक्ट्रियां यहां मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश में कपास की खेती का रकबा महज पांच फ़ीसद है. यहां कपास की खेती मुख्यतः गाज़ीपुर, मैमन सिंह, पंचगढ़, नीलफामारी और हिलटैम्स में होती है. उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका से 60 फ़ीसद, भारत से 20 फ़ीसद और पाकिस्तान से 15 फ़ीसद कपास का आयात करता है. इतनी बड़ी मात्रा में कपास आयात करने के बावजूद बांग्लादेश वस्त्रोद्योग में निरंतर प्रगति कर रहा है. व्यापार के लिए यातायात के साधनों का विकास होना काफ़ी ज़रूरी है. इस दिशा में बांग्लादेश सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है. प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल अरबों रुपये की लागत से पद्मा नदी पर बनने वाले पुल को मंजूरी दे दी. इस पुल के बनने से दक्षिण एशिया ख़ासकर भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और वर्मा से सड़क मार्ग आसान हो जाएगा. ■

मातृभाषा दिवस के मौके पर ढाका में उमड़ी लोगों की भीड़

शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा एक समूह

feedback@chauthiduniya.com

Rio2016

रियो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन दल

महिलाओं के कंधों पर पदक का दारोमदार

साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने दो रजत और चार कांस्य सहित कुल छह पदक जीतकर इतिहास रच दिया था. बैडमिंटन में भी भारत ने एक कांस्य पदक जीता था. इस बार रियो के लिए सात भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि इस बार भी वे ओलंपिक से खाली हाथ नहीं लौटेंगे. निशानेबाज़ी, मुक्केबाज़ी, तीरंदाजी और कुश्ती के बाद पदक जीतने का दारोमदार बैडमिंटन खिलाड़ियों के कंधों पर ही है. आइए नज़र डालते हैं कि ये खिलाड़ी सवा अरब भारतीयों की आशाओं पर कितना खरा उतरेंगे.

नवीन चौहान

रियो ओलंपिक के आयोजन में सौ दिन से भी कम का समय बचा है. ऐसे में भारत के लिए बैडमिंटन से जुड़ी अच्छी खबर आई है. इस साल अगस्त में ब्राजील के शहर रियो डि जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत के सात बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है. गौरतलब है कि साल 2012 में लंदन ओलंपिक के लिए केवल पांच बैडमिंटन खिलाड़ी क्वालीफाई कर सके थे, जिनमें से सायना नेहवाल ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था. आशा की जा रही है कि इस बार सायना के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर देश को एक बार फिर गौरान्वित करेंगे.

इस बार विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालीफिकेशन तय हुए हैं. इसके लिए 4 मई 2015 से 1 मई 2016 के बीच खिलाड़ियों द्वारा अर्जित अंकों को आधार बनाया गया. बैडमिंटन की महिला एकल वर्ग में पहली बार दो भारतीय खिलाड़ियों सायना नेहवाल और पीवी सिंधू ने क्वालीफाई किया है. रियो में सायना का साथ देंगी दो बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी पीवी सिंधू. यह सिंधू का पहला ओलंपिक होगा. पुरुष एकल स्पर्धा में लोगों को आशा थी कि पी कश्यप ओलंपिक कोटा हासिल कर लेंगे, लेकिन लगातार चोटों ने उनसे दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का मौका छीन लिया. इस बार पुरुष एकल की जिम्मेदारी 23 वर्षीय किदम्बी श्रीकांत के कंधों पर है. वह भी पहली बार ओलंपिक में शिरकत करेंगे. महिला युगल स्पर्धा के लिए ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने टिकट हासिल किया है. इन दोनों की जोड़ी लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पहुंची है. इसके अलावा पहली बार कोई भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में सफल हुई है. मनु अत्री और सुमित रेड्डी की इस जोड़ी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. इसलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे.

भारत के अलावा बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा में चीन (लि जुरेई, वांग यिहान), जापान (नोजोमी ओकुहारा और अकाने यामागुची) और कोरिया (सुंग जि हुन और बाई यिन जु) की भी दो-दो खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है. सायना और सिंधू ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों ही खिलाड़ी लगातार टॉप रैंकिंग में बनी रही हैं. सायना पिछले साल कुछ समय तक विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर रही थीं. फिलहाल वह 9वें नंबर पर हैं, जबकि सिंधू 10वें पायदान पर हैं. पुरुष एकल में क्वालीफाई करने वाले किदाम्बी श्रीकांत रियो क्वालीफिकेशन की दौड़ में दसवें स्थान पर थे. जबकि पुरुष युगल के लिए क्वालीफाई करने वाली मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी की वर्तमान विश्व रैंकिंग 19वीं है, जबकि क्वालीफिकेशन की दौड़ में उन्हें 10वां स्थान मिला था. वहीं ओलंपिक के लिए लगातार दूसरी बार क्वालीफाई करने वाली गुट्टा और पुनप्पा की जोड़ी क्वालीफिकेशन की दौड़ में नौंवे पायदान पर थी. हालांकि मिक्स-डबल्स स्पर्धा के लिए कोई भी भारतीय जोड़ी इस बार क्वालीफाई नहीं कर सकी.

सायना नेहवाल साल 2015 में सैय्यद मोदी इंटरनेशनल, इंडियन ओपन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, विश्व चैंपियनशिप और चाइना ओपन आदि प्रतियोगिताओं के फाइनल तक पहुंचीं थीं. लेकिन वह केवल सैय्यद मोदी इंटरनेशनल और इंडियन ओपन का खिताब जीतने में कामयाब रहीं. उन्होंने सैय्यद मोदी इंटरनेशनल के फाइनल में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कैरोलीन मरीन को हराकर खिताब जीता था, लेकिन मरीन के खिलाफ उन्हें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन और विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं चाइना ओपन के फाइनल में विश्व की पूर्व नंबर एक चीनी खिलाड़ी ली जुईरूई से वह पार नहीं पा सकीं. इंडियन ओपन के फाइनल में उन्होंने थाइलैंड की रैचनोक इनतानोन को मात दी थी. हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग में सायना 9वें पायदान पर हैं. वहीं कैरोलीन मरीन पहले, इनतानोन दूसरे और ली जुईरूई तीसरे पायदान पर हैं. ऐसे में इन खिलाड़ियों से ओलंपिक में पार-पाना सायना के लिए आसान नज़र नहीं आ रहा है. चोट से उबरने के बाद पिछले पांच महीने में उनके हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है. हालांकि सायना तीसरी बार ओलंपिक में भाग ले रही हैं. बीजिंग और लंदन ओलंपिक में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था. 2008 में बीजिंग ओलंपिक में वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंची थीं.

जब सायना ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था. तब पीवी सिंधू महज 16 साल की थीं. पदक जीतने के बाद जब सायना गोपीचंद अकादमी पहुंची थीं, तभी से सिंधू ने सायना की राह पर चलने का सपना देखा और महज चार साल में वह अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बल पर विश्व की टॉप टेन खिलाड़ियों में शामिल हुईं. सायना के बाद वह ओलंपिक के महिला एकल के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं. हालांकि रियो में सिंधू का ओलंपिक पदार्पण होगा लेकिन इससे पहले भी वह विश्वपटल पर अपनी चमक बिखेर चुकी हैं. साल 2013 और 2014 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था. वह विश्व चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं. लेकिन अब उनकी नजरें ओलंपिक पदक पर हैं जिसे खेलों की दुनिया में सर्वोच्च माना जाता है. पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. उन्होंने साल 2013 से 2015 तक लगातार तीन बार मकाऊ ओपन का खिताब जीता. 2016 में मलेशिया मास्टर्स ग्रांप्री का खिताब जीत चुकी हैं. लिहाजा उनसे ओलंपिक में सायना के साथ-साथ बेहतरीन प्रदर्शन की आशा के साथ पदक की उम्मीद की जा सकती है. चूंकि दोनों की विश्व रैंकिग में ज्यादा अंतर नहीं है इसलिए ओलंपिक में इन दोनों के बीच प्रारंभिक दौर में मुक़ाबला होने की आशंका जताई जा रही है. दरअसल दोनों ही खिलाड़ी पदक जीतने का माद्दा रखती हैं.

> **इस बार विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालीफिकेशन तय हुए हैं. इसके लिए चार मई 2015 से एक मई 2016 के बीच खिलाड़ियों द्वारा अर्जित अंकों को आधार बनाया गया. बैडमिंटन की महिला एकल वर्ग में पहली बार दो भारतीय खिलाड़ियों सायना नेहवाल और पीवी सिंधू ने क्वालीफाई किया है. रियो में सायना का साथ दो बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी पीवी सिंधू देंगी, उनका यह पहला ओलंपिक होगा. पुरुष एकल स्पर्धा में लोगों को आशा थी कि पी कश्यप ओलंपिक कोटा हासिल कर लेंगे, लेकिन लगातार चोटों ने उनसे दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का मौका छीन लिया. इस बार पुरुष एकल की जिम्मेदारी 23 वर्षीय किदम्बी श्रीकांत के कंधों पर है. वह भी पहली बार ओलंपिक में शिरकत करेंगे. महिला युगल स्पर्धा के लिए ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने टिकट हासिल किया है. इन दोनों की जोड़ी लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पहुंची है.**

अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी लंदन ओलंपिक में बड़े ही नाटकीय ढंग से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने से महज एक अंक से चूक गई थी. लेकिन इस बार भी दोनों खिलाड़ियों से आशा की जा रही है कि उनकी जोड़ी ओलंपिक पदक जीतने में सफल होगी. इस जोड़ी ने 2014 में एशियाई खेलों में महिला युगल का कांस्य पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया. इन दोनों की जोड़ी ने दिल्ली में हुए उबेर कप में भारतीय टीम को कांस्य पदक जितवाने में अहम भूमिका अदा की थी. साल 2015 में इस जोड़ी ने कैनेडियन ग्रांप्री का खिताब जीता और पहली बार विश्व रैंकिंग के टॉप टेन में जगह बनाई. इंडियन ओपन में यह जोड़ी सेमीफाइनल और अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची. इसलिए इस जोड़ी से रियो में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने की आशा की जा सकती है. दोनों ही खिलाड़ी कई सालों से एक साथ खेल रही हैं. दोनों के बीच बेहतर तालमेल है. दोनों एक दूसरे के खेल की पूरक हैं, यदि इस जोड़ी ने रियो में अपना बेहतरीन खेल दिखाया तो यह जोड़ी भारतीय बैडमिंटन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी. पुरुष एकल में 2014 चाइना ओपन विजेता 23 वर्षीय किदाम्बी श्रीकांत के लिए यह पहला ओलंपिक है. वह वर्तमान में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष खिलाड़ी हैं. फिलहाल वह विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर हैं. उनमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को हराने की क्षमता है यह उन्होंने 2014 में चाइना ओपन के फाइनल में विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी मलेशिया के लिन डेन को सीधे सेटों में हराकर साबित कर दिया था. साल 2015 में श्रीकांत ने स्विस ओपन ग्रांप्री और इंडियन ओपन का खिताब अपने नाम किया. वहीं साल 2016 में उन्होंने सैय्यद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. इसके अलावा साल 2016 में हुई बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में वह अपराजित रहे. जबकि इस प्रतियोगिता में चीन और मलेशिया जैसे देशों के चोटी के खिलाड़ी भाग ले रहे थे. ऐसे में श्रीकांत से ओलंपिक पदक की आशा की जा सकती है.

पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली सुमित रेड्डी और मनु अत्री की जोड़ी पिछले दो-तीन साल से एक साथ खेल रही है. साल 2013 में इस जोड़ी ने टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज के रूप में अपना पहला खिताब जीता था. साल 2014 में यह जोड़ी अपना खिताब बचाने में कामयाब रही. साल 2015 में इन्होंने लाओस इंटरनेशनल का खिताब जीता. हालांकि इस जोड़ी के पास ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन सायना और सिंधू जैसी स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव इनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

जिन सात खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है उनमें से सायना, पीवी सिंधू, के श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा, सुमित रेड्डी और मनु अत्री भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) का हिस्सा हैं. इन सभी को भारत सरकार की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के तहत रियो ओलंपिक की तैयारियों के लिए व्यक्तिगत कोच रखने और अन्य किसी ट्रेनिंग के लिए 90 लाख रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा इन खिलाड़ियों की मदद ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट संस्था भी कर रही है. ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट सायना, सिंधु, ज्वाला और अश्विनी की मदद पिछले कई सालों से कर रही है. हालांकि पी कश्यप को भी मदद मिल रही थी, लेकिन वह ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके.

इन खिलाड़ियों को मिल रही सरकारी और गैर-सरकारी मदद का असर उनके खेल पर दिख रहा है. खिलाड़ी अपने खेल को और बेहतर बनाने और अपनी कमियों को दूर करके ओलंपिक की तैयारी में जुटे हुए हैं. पहले खिलाड़ियों को अंतिम दौर में सरकारी मदद का आश्वासन मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसी गलती नहीं की है, जिससे खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ खेल पर ध्यान दे रहे हैं. उन्हें अपनी आवश्यक्ताओं के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही पुलेला गोपीचंद जैसे कोच की उपस्थिति खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है. उनकी देखरेख में भारतीय बैडमिंटन आज अपने सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहा है. ऐसे में निश्चित तौर पर साझे प्रयास का असर रियो ओलंपिक में बैडमिंटन कोर्ट पर नज़र आएगा और भारतीय बैडमिंटन दल रियो में एक बार फिर इतिहास रचेगा. ■

navinonline2003@gmail.com

बॉलीवुड ख़बरें

अब शाहरुख़ ख़ान बनेंगे बौना

तनु वेड्स मनु, रांझणा और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फ़िल्मों के निर्देशक आनंद एल राय एक और शानदार कहानी लेकर बड़े पर्दे पर आ रहे हैं. उनकी इस फ़िल्म में शाहरुख़ ख़ान होंगे और वह एक बौने के किरदार में नज़र आ सकते हैं. राय काफ़ी अरसे से शाहरुख़ ख़ान के साथ काम करना चाहते थे और अब उनका यह सपना पूरा हो रहा है. वो कहते हैं कि यह मेरी महत्वाकांक्षी फ़िल्म है. मैं समय लेकर इस पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं. यह फ़िल्म एक बौने किरदार पर आधारित है जिसका दिल बहुत बड़ा है. ख़ान साहब का मुझ पर विश्वास है और मैं इस विश्वास को पूरी लगन के साथ निभाना चाहता हूं. ज़मीन से जुड़ी कहानियां बयान करने वाले आनंद एल राय द्वारा निर्मित फ़िल्म *निल बटे सन्नाटा* ने फ़िल्म समीक्षकों से ख़ूब तारीफ़ें बटोरीं. राय यह मानते हैं कि ऐसी फ़िल्मों को ज़िंदा रखने के लिए बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की फ़िल्मों को बनाना बेहद जरूरी है जो धीरे-धीरे ख़त्म होती दिख रही हैं. *निल बटे सन्नाटा* का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है और स्वरा भास्कर ने फ़िल्म में अहम भूमिका निभाई है.■

रणवीर से मिलने पेरिस जाएंगी दीपिका

गोलियों की रासलीला-रामलीला से शुरू हुआ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का रिश्ता दिनों-दिन मज़बूत होता चला गया. रणवीर ने खुले आम कई समारोहों में दीपिका के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट की है. बाज़ीराव मस्तानी की विराट सफलता के बाद दीपिका ने भी रणवीर को अपना प्यार बताया है. यह दोनों सितारे अभी अपनी फ़िल्मों में व्यस्तता के कारण आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, लेकिन अब ख़बरें आ रही हैं कि यह दूरियां मिटने जा रही हैं. दीपिका टोरंटो में चल रही अपनी हॉलीवुड फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म करने के बाद घर लौटने से पहले रणवीर से मिलने पेरिस जाएंगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

प्रियंका की ख़ूबसूरती का राज

मुझे कसरत के अलावा योगाभ्यास करना काफी पसंद है, इससे मुझे सुकून और ऊर्जा मिलती है. मैं समझती हूं कि स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मन बसता है और योग की मदद से दोनों को फिट रखा जा सकता है. सौभाग्य से मुझमें वजन बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है और मैं जितना चाहूं उतना खा सकती हूं. आगे वह कहती हैं कि मैं एक पंजाबी कुड़ी की तरह खूब खाती हूं.

प्रियंका चोपड़ा हर उम्र की महिलाओं के लिए एक आइकॉन हैं. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उन्होंने अपनी अदाकारी और ख़ूबसूरती से लाखों दिलों में जगह बनाई है. सिर्फ उनके बॉलीवुड सुपरस्टार होने की वज़ह से ही नहीं बल्कि उनके ख़ूबसूरत फिगर की वज़ह से भी लोग उनके दीवाने हैं.

प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखने के लिए वो बहुत कड़ाई से दिनचर्या का पालन करती हैं. वह अपने वजन को काबू में रखने के लिए कसरत के अलावा योगाभ्यास करना काफी पसंद है, इससे मुझे सुकून और ऊर्जा मिलती है. मैं समझती हूं कि स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मन बसता है और योग की मदद से दोनों को फिट रखा जा सकता है.

सौभाग्य से मुझमें वजन बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है और मैं जितना चाहूं उतना खा सकती हूं. आगे वह कहती है कि मैं एक पंजाबी कुड़ी की तरह खूब खाती हूं. मेरे रोज के खाने में रोटी, सब्जी, सूप, सलाद, चावल और दाल के साथ बहुत सारे फल शामिल हैं. मैं खूब पानी पीती हूं और जूस भी लेती हूं. हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हमें बेहद खुशी

देते हैं. मेरे मामले में यह मेरा परिवार है. वो मेरे लिए सब कुछ है.

मैं अच्छा संगीत सुनती हूं और जब मुझे ज्यादा काम की वजह से तनाव महसूस होता है तो मैं कुछ अच्छा सोचती हूं या फिर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हूं. छुट्टी के दिन घर पर रहना और कोई अच्छी फिल्म देखना मुझे वैसी ही खुशी का एहसास देता है जैसे कि 24 घंटे शूटिंग करना.■

सुल्तान के सेट पर बेहोश हुए रणदीप

सलमान ख़ान की आगामी फ़िल्म सुल्तान की दिल्ली में चल रही शूटिंग के दौरान अभिनेता रणदीप हुड्डा बेहोश हो गए. रणदीप को शूटिंग के दौरान अपेंडिक्स का दर्द उठा और वो बेहोश हो गए. फ़िल्म के प्रवक्ता की ओर से दिए बयान में बताया गया कि रणदीप इस समस्या से काफ़ी समय से जूझ रहे थे और कुछ दिनों से परेशान भी थे. लेकिन शूटिंग शेड्यूल की वजह से वो इसे नज़र अंदाज़ कर रहे थे. इस फ़िल्म में सलमान के कोच की भूमिका निभा रहे रणदीप शॉट की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें दर्द उठा और वो बेहोश हो गए. रणदीप पिछले कुछ समय से काफ़ी व्यस्त हैं और वो सुल्तान के अलावा फ़िल्म *सरबजीत* में भी काम कर रहे हैं.■

फिर नज़र आएगी अक्षय-सोनाक्षी की जोड़ी

अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी *राउडी राठौर और हॉलीडे* जैसी सफल फिल्में दे चुकी है. एक बार फिर यह जोड़ी साथ नज़र आने वाली है. निर्माता-निर्देशक विपुल शाह ने सोनाक्षी को *नमस्ते इंग्लैंड* के लिए अक्षय कुमार के अपोजिट साइन किया है. विपुल का कहना है कि यह नमस्ते लंदन का सीक्वल नहीं है. देखना दिलचस्प होगा कि सोनाक्षी-अक्षय की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती हैं. ■

पर्सनैलिटी

मोहम्मद रफ़ी

तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे!

मोहम्मद रफ़ी से हुआ था लता मंगेशकर का झगड़ा

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी काफी अच्छे दोस्त थे, पर अचानक ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं. 60 के दशक की बात है जब लता मंगेशकर ने अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेने की बात कही, इस बात को लेकर रफ़ी साहब और लता में झगड़ा हो गया. लता जी का कहना था कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए. लेकिन रफ़ी साहब इसके ख़िलाफ़ थे, उनका कहना था कि एक बार रिकॉर्डिंग हो गई और गायक को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उसके बाद गायक को और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए. इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों में मनमुटाव हो गया. यहां तक कि मोहम्मद रफ़ी ने लता जी से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ गाने ही नहीं गाऊंगा. इसी बात पर लता जी ने पलट कर कह दिया कि आप ये तकलीफ मत करिए मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ. लता ने संगीतकारों को फोन करके कह दिया कि वो रफ़ी साहब के साथ गाने नहीं गाएंगी. इस तरह से दोनों का झगड़ा करीब साढ़े तीन साल तक चला.

लंबे समय के बाद अभिनेत्री नरगिस के कहने पर दोनों महान कलाकारों ने फिल्म ज्वेल थीफ में एक साथ गाना गया. जिसके बोल थे... दिल पुकारे, आरे आरे आरे...अभी न जा मेरे साथी.■

मोहम्मद रफी का जन्म पंजाब में अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था. रफी को बचपन में ही एक फकीर ने अपने गीतों से मोहित कर लिया था. संगीत के प्रति मोह शायद तभी से हुआ और नन्हें रफी ने गायक बनने की चाह अपने दिल में जगाई. इस चाह को पहचाना रफी के बड़े भाई हमीद ने. हमीद ने देखा था दो वर्ष के उस रफी को जो सुल्तानपुर (लाहौर) में उनके दरवाज़े पर खैरात मांगने आए फकीर को गाते हुए न केवल देखता, बल्कि उसकी तरह गाने का प्रयास भी करता था.

कहा तो यह भी जाता है कि रफी के बड़े भाई की नाई की दुकान थी, रफी का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था. रफी जब सात साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर के पीछे लग जाते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था. उसकी आवाज़ रफी को बहुत पसंद आती थी और रफ़ी उसकी नकल करने लगे थे. इस नकल में निपुणता देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी. एक दिन उस फ़कीर ने भी सुना, उसने देखा कि फ़कीरी गीत गाते वक्त नन्हे रफ़ी के दिल में ख़ास भक्तिभाव आ जाता है, यह देख फकीर बहुत खुश हुआ और 6 साल के रफी को उसने आशीर्वाद दिया और कहा...बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा गायक बनेगा.

26 हज़ार गाने गाए थे रफ़ी ने

मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पेशेवर जिंदगी में तकरीबन 26 हजार गीत गाए और लगभग सभी भाषाओं में. वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से उन्होंने हिन्दी फिल्म जगत के पायदान पर कदम रखे थे और उसके बाद कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा. आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया. उन्होंने बेगम बिलकिस से शादी की और उनकी सात संतानें हुईं-चार बेटे तथा तीन बेटियां.

रफ़ी को मिले सम्मान

55-60 का दशक था जब रफ़ी की आवाज़ हरेक कानों में गूंजने लगी थी. प्यार-मोहब्बत हो या दर्द भरे नगमे रफ़ी की आवाज़ से शब्द ज़िंदा होकर उठते थे और लोगों के दिलो में बस जाया करते थे. इन्ही दिनों एक गीत आया-*चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो*. इस गीत ने ऐसा गजब ढाया कि हर जवान दिलों के मुंह पर अपने चांद के लिए यही गीत छा गया. लिहाजा पहली बार मोहम्मद रफ़ी को इस गीत के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाज़ा गया. इसके बाद 1961 में रफ़ी को दूसरा फ़िल्मफेयर पुरस्कार गीत *तेरी प्यारी प्यारी सूरत को* के लिए मिला. 1965 में ही संगीतकार लक्ष्मीकान्त प्यारेलाल के निर्देशन में

फ़िल्म दोस्ती के लिए गाए गीत *चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे* के लिए रफ़ी को तीसरा फ़िल्मफेयर पुरस्कार मिला. साल 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा. साल 1966 में फिल्म सूरज के गीत *बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है...* बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. साल 1968 में संगीतकार शंकर जयकिशन के निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत *दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर* के लिए उन्हें पाचवां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और 1977 में छठा और अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें *क्या हुआ तेरा वादा...* गीत के लिए मिला.

ज़िंदगी के सफर में रफ़ी

यह बहुत काम लोग जानते होंगे कि मोहम्मद रफ़ी ने दो शादियां की थीं. उन्होंने अपनी पहली शादी की बात जमाने से छिपाकर रखी थी. बस उनके घरवाले जानते थे. यह बात शायद पता भी नहीं चलती अगर रफ़ी की पुत्रवधू यास्मीन ख़ालिद रफ़ी की पुस्तक बाज़ार में न आती. यास्मीन की प्रकाशित पुस्तक *"मोहम्मद रफ़ी. मेरे अब्बा..एक संस्मरण"* में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि तेरह साल की उम्र में रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था. इस विवाह से उनका एक बेटा सईद हुआ था. घर में इस बात का ज़िक्र करना भी मना था, क्योंकि रफ़ी की दूसरी बीवी बिलकिस बेगम इसे नापसंद करती थीं और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात भी करे. यदि कभी कोई इसकी चर्चा करता भी था, तो बिलकिस बेगम और रफ़ी के साले ज़हीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को वहीं दबा देते थे.

रफ़ी और नौशाद

बात 1944 की है जब मोहम्मद रफ़ी नौशाद साहब के नाम एक सिफारशी पत्र लेकर मुंबई आ गए थे. नौशाद ने इस पत्र का आदर किया और रफ़ी की आवाज़ सुनी. सुनकर वो ऐसे मदहोश हुए कि उन्हें लगा मानो कोई फरिश्ता उनके सामने गा रहा हो, नौशाद ने रफ़ी को हिन्दी फिल्म *पहले आप* में गवाया और इस गाने के लिए रफ़ी को 50 रुपये मेहनताना भी दिए गए. यहां से शुरू हुआ रफ़ी का संघर्ष पूर्ण सफर. पहली सफलता मिली फिल्म *जुगनू के गीत यहां बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है* से. इसके बाद देखते ही देखते कोटला सुल्तान सिंह का फीकू अब मोहम्मद रफ़ी बन चुका था, जिसमें नौशाद का अहम योगदान भी था.

जब नौशाद साहब की आंखें भर आईं

एक बार रिकॉर्डिंग के बाद सभी लोग चले गए और मो. रफ़ी साहब स्टूडियो के बाहर खड़े रहे. करीब दो घंटे बाद नौशाद साहब स्टूडियो के बाहर आए. वहां रफ़ी जी को देखकर नौशाद साहब चौंक गए और उनसे वज़ह पूछते हुए कहा कि आप अभी तक घर नहीं गए. इस पर रफ़ी साहब ने कहा कि...मेरे पास घर जाने के लिए ट्रेन किराए के लिए पैसे नहीं हैं, यह सुनकर नौशाद साहब दंग रह गए और बोले कि अगर ऐसी बात थी तो अंदर आकर पैसे ले लेते, तो रफ़ी साहब ने ज़वाब दिया कि अभी तो रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं हुई है, तो पैसे कैसे मांगता. कल फिर आना है इसलिए सोचा कि आज की रात स्टूडियो के बाहर ही काट लूं, नौशाद साहब की आंखे भर आईं, इतनी शराफ़त और नेकदिली ही इंसान को महान बनाती है.

माहे पाक रमज़ान का वो दिन

रमज़ान में मोहम्मद रफ़ी का इंतेकाल हुआ था और रमज़ान में भी अलविदा के दिन. बांद्रा की बड़ी मस्जिद में उनका नमाज़े जनाज़ा हुआ था. पूरा ट्रैफिक जाम था. क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कौम सड़कों पर आ गई थी. नमाज़ के पीछे जो लोग नमाज़ में शरीक थे उनमें राज कपूर, राजेन्द्र कुमार, सुनील दत्त के अलावा इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे. हर मज़हब के लोगों ने उनको कंधा दिया. अंतिम यात्रा के दिन लोगों का हुजूम उमड़ा वो मोहम्मद रफ़ी के लिए ही था. यहां तक की आसमान भी रो पड़ा था. पूरी यात्रा के दौरान बारिश होती रही. प्रकृति भी मानो अपने महान गायक को अलविदा कह रही थी. मगर उनकी रूह हर दिल को कह रही थी-तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे!■

– चौथी दुनिया ब्यूरो